राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 58

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शनिवार, 7 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

कांसा नहीं, बेटियों ने जीता दिल

>> 12

ओलिंपिक में तीसरे राउंड में शाट लगातीं भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ● एएफपी

अदिति से पदक की उम्मीद, बजरंग कांस्य के लिए लड़ेंगे

टोक्यो ओलिंपिक में शुक्रवार को भारत कोई पदक तो नहीं जीत सका, लेकिन अदिति अशोक ने गोल्फ में भारत के पहले पदक की उम्मीदों को कायम रखा। अदिति तीसरे दौर में तीन अंडर 67 स्कोर करके दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। स्वर्ण के दावेदार माने जा रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने निराश किया। वह कुश्ती के 65 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग के सेमीफाइनल में तीन बार के विश्व चैंपियन हाजी अलियेव से 5-12 से हार गए। अब वह शनिवार को कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे।
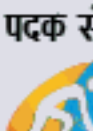
पदक से चूकी महिला हाकी टीम : भारतीय महिला हाकी टीम का पहला ओलिंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया। उसे कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से हराया।

संबंधित खबरें >> पेज 12

भारत के अन्य परिणाम

- कुश्ती में सीमा बिसला महिला 50 किग्रा वर्ग के पहले दौर में ही ट्यूनीशिया की सारा हमदी से 1-3 से हार कर बाहर हो गईं।
- गोल्फ में दीक्षा डागर एक ओवर 72 के स्कोर के साथ संयुक्त 51वें नंबर पर रहीं।
- प्रियंका गोस्वामी 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में 17वें और भावना जाट 32वें स्थान पर रहीं।
- गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किमी पैदल चाल पूरी नहीं कर सके और गर्मी व उमस के कारण हुई ऐंठन की वजह से नाम वापस ले लिया।
- चार गुणा 400 मीटर पुरुष रिले टीम (मुहम्मद अनस, टाम नोह निर्मल, राजीव अरोकिया और अमोल जैकब) नौवें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए जगह बनाने से चूक गई।

राजीव गांधी नहीं, अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जगह पूर्व भारतीय हाकी कप्तान मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। भारतीय हाकी टीमों के टोक्यो ओलिंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद इस सम्मान का नाम महान हाकी खिलाड़ी को समर्पित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हाकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया है। अब हाकी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, जो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। मालूम हो कि खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपये की राशि भी दी जाती है।

सबसे बड़े खिलाड़ी

हाकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में और निधन तीन दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने 185 मैच में 570 गोल दागे। वह 1928-एम्सटर्डम, 1932-लास एंजिलिस व 1936-बर्लिन ओलिंपिक की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे। उनके नाम से पहले ही ध्यानचंद लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। बर्लिन ओलिंपिक के बाद उनके खेल से अभिभूत होकर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें अपने देश की नागरिकता का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

मेजर ध्यानचंद

देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। **-अमित शाह,** केंद्रीय गृह मंत्री

चीनी सेना ने गोगरा में अस्थायी निर्माण भी हटाए

सुलह की राह ▶ 15 महीने के गतिरोध के बाद टकराव वाले स्थान से पीछे हटे सैनिक

एलएसी पर यथास्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं होगा

संजय मिश्र, नई दिल्ली

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य टकराव खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत और चीन ने गोगरा इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। दोनों देशों ने गोगरा में एलएसी के पेट्रोलिंग प्वाइंट 17ए से सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही इस अग्रिम मोर्चे पर बनाए गए सभी अस्थायी निर्माण और बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया है। गोगरा के इस पेट्रोलिंग प्वाइंट पर बीते 15 महीने से दोनों देशों के सैनिक टकराव की स्थिति में थे। सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही दोनों देश एलएसी पर बाकी बचे इलाकों के गतिरोध का हल निकालने के लिए आगे बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हैं। दोनों देश इस पर भी राजी हैं कि एलएसी पर यथास्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं करेंगे।

भारत-चीन के सैन्य कमांडरों की बीते 31 जुलाई को चुशूल-मोल्डो पोस्ट पर 12वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप गोगरा इलाके से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया दो दिनों में पूरी की गई है। दोनों देशों ने चार-पांच अगस्त को पेट्रोलिंग प्वाइंट 17ए से अपने-अपने सैनिक को हटा लिए। भारतीय सेना ने एक बयान में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सैन्य कमांडरों के बीच पश्चिमी सेक्टर में बाकी बचे इलाकों से टकराव खत्म करने को लेकर हुई गहन और खुली बातचीत में सैनिकों को पीछे हटाने पर समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार ही भारत और चीन ने गोगरा में अग्रिम मोर्चे पर तैनात अपने-अपने सैनिकों को चरणबद्ध और समन्वित तरीके से हटा लिया है।

गोगरा से सैनिकों को हटाए जाने के साथ ही एलएसी पर सैन्य तनातनी के एक और मोर्चे का टकराव खत्म हो गया है। इसी के साथ पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैन्य टकराव के छह मोर्चों में से चार का गतिरोध दूर हो गया है।

पिछले साल से डटे थे सैनिक : गोगरा इलाके में पिछले साल मई से ही दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने के टकराव की स्थिति में डटे थे। हालांकि गोगरा में दोनों देशों के सैनिकों की संख्या और साजो-सामान गलवन और पैंगोंग झील इलाके में तैनाती के मुकाबले कम थी।

- चार और पांच अगस्त को दोनों देशों ने अपने सैनिकों को हटाया
- सैन्य कमांडरों के बीच 12वें दौर की वार्ता में बनी थी इस पर सहमति

सैनिकों को हटाने का सत्यापन भी किया : दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को हटाने की इस प्रक्रिया का परस्पर सत्यापन भी किया है। सेना का कहना है कि गतिरोध दूर करने के लिए हुआ यह समझौता सुनिश्चित करता है कि दोनों देश इन इलाकों में एलएसी का कड़ाई से अवलोकन करने के साथ ही इसका सम्मान भी करेंगे।

इससे पहले दोनों देशों ने गलवन और पैंगोंग झील से हटाए थे सैनिक

- गोगरा से पहले गलवन, पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे के अग्रिम मोर्चों से दोनों देशों ने अपने-अपने सैनिकों को पीछे हटाकर यहां बफर जोन बनाया था।
- पैंगोंग झील इलाके में इसी साल फरवरी में सैनिकों को हटाए जाने के बाद बातचीत के कई दौर के उपरांत गोगरा इलाके से सैनिकों को दोनों पक्षों ने हटाया है।

अब हाट स्प्रिंग और देपसांग में गतिरोध

- अब एलएसी पर हाट स्प्रिंग और देपसांग इलाकों में भारत और चीन के सैनिक टकराव की स्थिति में तैनात हैं।
- सेना ने एलएसी के बाकी इलाकों के टकराव का हल निकालने के लिए कमांडर वार्ता में दोनों ओर से जताई गई प्रतिबद्धता का जिक्र भी किया है।
- सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ मिलकर वह पश्चिमी सेक्टर में एलएसी पर शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

'जजों को धमकी गंभीर मामला'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने जजों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, उनकी सुरक्षा को लेकर राज्यों से मांगा जवाब
- धनबाद में जज की हत्या के मामले में सीबीआइ को जारी किया नोटिस

जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जजों को धमकियां अत्यधिक गंभीर मामला है। अदालत ने कहा कि पुलिस, आइबी या सीबीआइ जैसी एजेंसियों से इसकी शिकायत की जाती है तो कई बार वे इस पर ध्यान देना तो दूर जवाब तक नहीं देतीं। आइबी और सीबीआइ न्यायपालिका की कोई मदद नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा कि जजों को न सिर्फ शारीरिक रूप से धमकाया जाता है बल्कि वाट्सएप आदि पर भद्दे संदेश भेजकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से इस मामले में मदद का अनुरोध करते हुए जजों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों पर सभी राज्यों से 17 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को नोटिस जारी करते हुए उस केस को सोमवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है।

एक नया चलन हो गया है कि हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में जब आरोपितों को कोर्ट से मनचाहे आदेश नहीं मिलते तो वे न्यायपालिका की छवि खराब करने लगते हैं। - सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जजों की सुरक्षा के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान कहा कि कई बार हाई प्रोफाइल लोगों या गैंगस्टर के आपराधिक मामलों में जजों को धमकियां मिलती हैं। जजों को शिकायत दर्ज कराने की आजादी तक नहीं है।

सीबीआइ पर तल्ख टिप्पणी पेज>>5

जागरण विशेष

रोग की सटीक पहचान में एआइ बनेगी मददगार

कानपुर: आधुनिक तकनीक के सहारे देश में अब इलाज की राह और आसान होगी। चिकित्सीय जांच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जोड़ने की तैयारी चल रही है। (पेज-10)

तालिबान ने की अफगान राष्ट्रपति के प्रवक्ता की हत्या

काबुल: अफगानिस्तान में तालिबान संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार को तालिबान आतंकियों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता की हत्या कर दी। साथ ही, आतंकियों ने नमरुज प्रांत की राजधानी जरंज पर भी कब्जा कर लिया है। इसे किसी राजधानी पर आतंकियों का पहला कब्जा माना जा रहा है। अफगान सरकार आतंकियों के कब्जे से इन्कार कर रही है। (पेज-11)

अंदर की खबरें

महंगाई का खतरा, लेकिन ग्रोथ प्राथमिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा शुक्रवार को पेश करते हुए आरबीआइ के गवर्नर डा. शक्तिकांत दास ने महंगाई के खतरे के बावजूद आर्थिक विकास दर की रफ्तार को तेज करने का विकल्प चुना। मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एमपीसी) की तीन दिनों की बैठक में यह फैसला किया गया है कि अभी ब्याज दरों को स्थिर ही रखा जाए और कर्ज को निचले स्तर पर ही बनाए रखने की कोशिश हो। लिहाजा आरबीआइ ने कर्ज की दरों को तय करने वाले रेपो रेट को चार फीसद ही बनाए रखने का एलान किया है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर के अनुमान को पूर्व के 5.1 फीसद से बढ़ा कर 5.7 फीसद कर दिया गया है। इस अवधि के लिए आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को 9.5 फीसद पर ही स्थिर रखा गया है।

एमपीसी में आरबीआइ गवर्नर समेत छह लोग होते हैं और इस बार इनमें से पांच लोगों ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का समर्थन किया है। जबकि जून, 2021 की बैठक में सभी छह सदस्यों ने विकास दर को प्राथमिकता देने के लिए ब्याज दरों को नहीं बढ़ाने के पक्ष में मत दिया था। इसका संकेत यह लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों के निचले स्तर पर रहने का समय संभवतः अगले चार से छह महीनों में खत्म हो सकता है। यह सातवीं समीक्षा है जिसमें ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। कोविड के पहले दौर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए आरबीआइ ने 22 मई, 2020 को ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी। यह भी संकेत है कि अब ब्याज दरों के नीचे रहने की अवधि समाप्त होने के कगार पर है। फरवरी, 2019 से मई, 2020 के बीच ब्याज दरों को तय करने वाले प्रमुख वैधानिक दर (रेपो रेट) में 2.50 फीसद की कटौती की जा चुकी है।

खुदरा महंगाई में वृद्धि की आशंका : आरबीआइ को पूरे वर्ष के दौरान महंगाई दर चार फीसद (दो फीसद नीचे या उपर) रखने को लेकर कदम उठाने होते हैं। शुक्रवार को डा. दास ने कहा कि, जुलाई-सितंबर की अवधि में खुदरा महंगाई की दर 5.9 फीसद, अक्टूबर-दिसंबर में 5.3 फीसद और जनवरी-मार्च, 2022 की तिमाही में बढ़ कर 5.8 फीसद होने की आशंका है। इसके बाद की तिमाही में यह फिर से 5.1 फीसद पर आ सकती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए महंगाई की औसत दर 5.7 फीसद अनुमानित है, जो आरबीआइ की लक्ष्य की ऊपरी सीमा के करीब है। इसके बावजूद ब्याज दरों को एमपीसी ने इसलिए नहीं बढ़ाया है ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार पर कोई आंच नहीं आए।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास। एएनआइ

- मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर को चार फीसद ही बनाए रखने का फैसला
- महंगाई दर के अनुमान को 5.1 फीसद से बढ़ाकर 5.7 फीसद किया

अहम फैसले

- रिवर्स रेपो रेट को 3.35 फीसद और बैंक रेट को 4.25 फीसद बनाए रखा
- गवर्नमेंट सिक्युरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के दूसरे चरण यानी जी-सैप 2 में 25-25 हजार करोड़ की और दो नीलामी होगी
- कोरोना महामारी के बीच विकास को बनाए रखने के लिए आरबीआइ उदार रुख बनाए रखेगा

ब्याज दरों का हो सकता है प्रतिकूल असर पेज>>7

कानूनी उपाय

देखभाल में गड़बड़ी पर सरकार से फंड लेने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई, इस सिलसिले में विधेयक को अगले हफ्ते कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी, तय नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने के साथ होगा अब सजा का भी प्रविधान

बुजुर्गों की देखभाल में कोताही की तो खैर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल में खामी के लिए न सिर्फ बच्चे बल्कि वे एजेंसियां भी जिम्मेदार होंगी, जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। इन एजेंसियों के स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी को जेल की सजा हो सकती है। सरकार ने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस संशोधित विधेयक को कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। इन बदलावों के बाद प्रस्तावित यह कानून और ज्यादा सख्त हो जाएगा।

संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इस विधेयक में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उनमें बुजुर्गों की देखभाल के लिए काम करने वाली एजेंसियों को ज्यादा जिम्मेदार बनाया है। अब यदि कोई एजेंसी किसी स्तर पर इसके तय नियमों या मापदंडों का पालन नहीं करती है, तो उसके अधिकारी को जेल की भी सजा हो सकती है। अभी तक विधेयक में ऐसी स्थिति में सिर्फ दंड का ही प्रविधान रखा गया है। इसके साथ ही बुजुर्गों को तकनीकी और वित्तीय कामकाज को लेकर सभी तरह की जरूरी सुविधाएं मुहैया करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

संसदीय समिति का मानना था कि इस समय वित्तीय धोखाधड़ी का सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में उन्हें बैंकों में डिजिटल तरीके से होने वाले लेन-देन को लेकर पूरी तरह से अपडेट किया जाए।

सरकार ने माता-पिता और बुजुर्गों के भरण-पोषण के लिए वर्ष 2007 में बने कानून को कुछ बड़े और अहम बदलावों के साथ दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया था। वहां से इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

सभी जिलों में खोले जाएंगे वृद्धाश्रम : विधेयक में सभी जिलों में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खोलने का भी प्रविधान किया गया है। अभी देश के करीब सात सौ जिलों में से सिर्फ 482 जिलों में ही वृद्धाश्रम हैं। ऐसे में समिति ने सरकार को सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने को कहा है।

नाती, नातिन भी माने जाएंगे बच्चे : संसदीय समिति के सुझाव के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विधेयक में एक और बड़ा बदलाव किया है। इसमें बच्चों की परिभाषा के दायरे को बढ़ाते हुए उनमें गोद लिए बच्चे, नाती, नातिन को भी शामिल किया गया है। साथ ही भरण-पोषण में सिर्फ भोजन और रहने की व्यवस्था ही नहीं होगी, बल्कि उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

24 घंटे में शुक्रवार को राजधानी में कोरोना से पांच मरीजों की मौत हो गई। वहीं, 44 मामले आए और 41 मरीज ठीक हुए। संक्रमण दर 0.08 फीसद से घटकर 0.06 फीसद हो गई है।

पिंक लाइन पर शिव विहार से मजलिस पार्क तक उपलब्ध हुई सीधी मेट्रो सेवा

सुविधा ▶ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी

पहले दो हिस्सों में हो रहा था मेट्रो का परिचालन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी-संजय झील से मजलिस पार्क के बीच डेढ़ किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाकर इस कारिडोर पर मेट्रो के परिचालन का शुभारंभ किया। इसके बाद दोपहर तीन बजे यह कारिडोर यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इससे 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी लाइन चालू हो गई है। इससे शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो गई है।

इसके पहले पिंक लाइन पर दो हिस्सों में मेट्रो का परिचालन हो रहा था। इसके तहत मजलिस पार्क से मयूर विहार पाकेट एक और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध थी। मयूर विहार पाकेट एक से त्रिलोकपुरी के बीच डेढ़ किलोमीटर के कारिडोर में 290 मीटर का हिस्सा जमीन विवाद के कारण पहले नहीं बन पाया था। जमीन विवाद खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने स्टील गार्डर से इस हिस्से पर एलिवेटेड कारिडोर तैयार किया। इसका परिचालन शुरू होने से दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 390 किलोमीटर हो गया है और 285 स्टेशन हैं। इसमें नोएडा का मेट्रो कारिडोर व गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो सेवा शामिल है।

हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ने राष्ट्रीय राजधानी में विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई है। पिंक लाइन के पूरे हिस्से पर परिचालन शुरू होने से आनंद विहार, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, लाजपत नगर मार्केट, साउथ एक्सटेंशन सहित कई प्रमुख स्थलों पर पहुंचना लोगों के लिए आसान हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कारिडोर घनी आबादी वाले इलाके से गुजर रहा है। इससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा।

फेज चार के तीन कारिडोर को जल्द मंजूरी की सिफारिश: शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि फेज चार में 65.10 किलोमीटर नेटवर्क के तीन कारिडोर बन रहे हैं। 42 किमी. लंबाई के तीन अन्य कारिडोर का निर्माण भी होना है। उन्होंने दिल्ली सरकार से इन तीन कारिडोर की परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की सिफारिश की।

पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पाकेट एक के बीच मेट्रो का परिचालन शुभारंभ करते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य–मेट्रो

पिंक लाइन पर होगा देश का पहला रिंग मेट्रो कारिडोर

पिंक लाइन का निर्माण रिंग रोड के समानांतर किया गया है। फेज चार में मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच 12.55 किलोमीटर का मेट्रो कारिडोर बन रहा है। यह पिंक लाइन की विस्तार परियोजना है। वर्ष 2023 में इसका निर्माण पूरा होने पर पिंक लाइन पर रिंग मेट्रो कारिडोर तैयार हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर होगी। इससे पिंक लाइन देश का सबसे बड़ा मेट्रो कारिडोर बन जाएगा। 3अयह देश का पहला रिंग मेट्रो कारिडोर भी होगा, जो दिल्ली को चारों तरफ से कनेक्ट करेगा।

देश की सेवा करने वाले जवानों मिलनी चाहिए सुविधा : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

- नान-फैमिली जोन में तैनात बीएसएफ जवानों को आवंटित भवन खाली करने के आदेश पर रोक
- कहा, कठिन इलाके में तैनाती करने पर जवानों को भवन खाली करने को नहीं कह सकते

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों के परिवार को दिल्ली के अलग-अलग सरकारी आवासीय परिसरों में आवंटित भवन खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। आदेश के खिलाफ इंस्पेक्टर गजेंद्र समेत 70 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि देश की सेवा के लिए माइनस 30 डिग्री तापमान में काम करने वाले जवानों को सुविधा दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि अगर आप तीन हजार जवानों का तबादला ऐसी जगह पर कर रहे हैं, जहां परिवार को साथ रखने की व्यवस्था नहीं है और उससे आवंटित भवन खाली करा लेंगे तो उसका परिवार क्या सड़क पर रहेगा। पीठ ने यहां तक कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप दिल्ली में भवन दीजिए, लेकिन आप उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। पीठ ने कहा कि अगर आप जवान की तैनाती का समय बढ़ा रहे हैं, तो फिर परिवार को दी गई आवास की सुविधा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश नियमों के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। सभी को यह सुविधा देना संभव नहीं है। हालांकि, पीठ ने उनकी दलील को ठुकराते हुए केंद्र सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, ऐसे में उनके परिवार पर अगली सुनवाई तक भवन खाली करने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

यह है मामला: अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला के माध्यम से गजेंद्र कुमार समेत 70 जवानों ने शहरी आवास मंत्रालय के चार मार्च, 2021 को भवन खाली करने के संबंध में जारी आदेश को चुनौती दी है। अरविंद कुमार शुक्ल ने दलील दी कि बीएसएफ जवान त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, असम, कुपवाड़ा में तैनात हैं। नियम के तहत जवानों की तैनाती तीन साल के लिए की जाती है और फिर इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार को सिर्फ तीन साल के लिए ही भवन आवंटित किया जाता है, जो कि मनमाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन सभी के लिए आवंटित भवन को खाली कर अन्य भवन का इंतजाम करना मुश्किल भरा काम है।

'बच्चे को मां के उपनाम के इस्तेमाल का हक'

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हर बच्चे को अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिता यह तय नहीं कर सकता कि नाबालिग बच्चे उसके ही उपनाम का इस्तेमाल करें। इस मामले में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने याचिकाकर्ता पिता से पूछा कि अगर नाबालिग लड़की अपने उपनाम से खुश है तो दिक्कत क्या है? बच्चे को अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है। दरअसल, पिता ने याचिका दायर कर मांग की थी कि प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसकी बेटी के दस्तावेज में मां के बजाय उसका नाम उपनाम के रूप में दर्शाया जाए। पीठ ने आदेश देने से इन्कार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की बेटी नाबालिग है और वह इस तरह के मामले पर खुद निर्णय नहीं ले सकती है। उन्होंने दावा किया कि नाम में बदलाव करने से बीमा फर्म से लिए गए बीमा का लाभ उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि पालिसी उनके उपनाम के साथ ली गई थी।

न्यूज गैलरी

अस्थाना को पुलिस आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली: एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने गुजरात काडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने और उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने जा रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के रूप में उन्हें एक साल का कार्यकाल दिया गया है। (प्रेट्र)

एंबियंस ग्रुप के मालिक राज सिंह गहलोत की रिमांड बढ़ी

नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए गुरुग्राम स्थित एंबियंस ग्रुप के मालिक राज सिंह गहलोत की रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिन के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को रिमांड समाप्त होने पर ईडी ने राज सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में पेश कर सात दिन की रिमांड और मांगी, लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड बढ़ा दी। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गहलोत को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उस पर 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। (जासं)

सागर हत्याकांड में कोर्ट ने आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली: अदालत ने माडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो अगस्त को रोहिणी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को आरोप पत्र को मुख्य महानगर दंडाधिकारी सतबीर सिंह की अदालत के सामने रखा गया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी। पेश आरोप पत्र के अनुसार सागर की हत्या की साजिश पहलवान सुशील कुमार ने रची थी। उसने साथी पहलवानों व गैंगस्टरों के साथ साजिश रच चार मई की देर रात घटना को अंजाम दिया था। (जासं)

जीएनसीटीडी कानून में संशोधन के खिलाफ कोर्ट जाएगी विधानसभा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कानून में संशोधन करके विधानसभा की समितियों की शक्ति को कम किया गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार इस तरह से दिल्ली विधानसभा की शक्तियों को कम नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि मार्च में संसद में पारित संशोधित कानून यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल हैं। जीएनसीटीडी संशोधित कानून के तहत अब दिल्ली विधानसभा की कोई भी कमेटी दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के विरुद्ध जांच या कार्रवाई नहीं कर सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने कहा कि वह कानून के केवल उस हिस्से को चुनौती देंगे, जो विधानसभा समितियों की शक्तियों को छीनने के संबंध में है। इसे लेकर वह कानूनी राय ले रहे हैं। केंद्र द्वारा पारित जीएनसीटीडी कानून असंवैधानिक है और चार जुलाई 2018 के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का भी उल्लंघन है।

विस को 2018 से अब तक 34 प्रश्नों के नहीं मिले जवाब

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2018 से अभी तक करीब 34 विधायकों ने विधानसभा में, जो सवाल पूछे थे, उसका जवाब नहीं मिला। इसके अलावा डीडीए और कानून व्यवस्था से संबंधित, अगर कोई जानकारी इन विभागों से मांगी जाती है, तो अधिकारी दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटियों के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए विधानसभा और इसकी समितियों ने बहुत काम किया है। उसमें केंद्र सरकार लगातार अड़चन डालने कोशिश कर रही है।

मानसून सत्र में आप के दो विधायकों सोमनाथ भारती और बंदना कुमारी ने सवाल पूछे थे, जिसका अधिकारियों ने रिजर्व सब्जेक्ट का हवाला देकर उत्तर नहीं दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। विशेषाधिकार समिति का फैसला आने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा।

मासूम के साथ दरिंदगी से पीएम दुखी, परिवार को मिलेगा इंसाफ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली कैंट में नौ वर्षीय बच्ची के साथ हुई हृदयविदारक घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी व्यथित हैं। उन्होंने बाहरी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। सांसद ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और पीड़ित परिवार तक उनका संदेश भी पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा।

सांसद हंसराज हंस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद उनके प्रतिनिधि के तौर पर वह गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिले और प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है।

सांसद ने बताया कि समाज के लोगों से बात कर शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री तक पीड़ित परिवार का दर्द पहुंचा दिया है। घटना की पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी है।

सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की अपील प्रधानमंत्री से की है। उन्होंने कहा कि कई लोग बच्ची को अनुसूचित जाति की बेटी कह रहे हैं। बेटी आखिर बेटी होती है, वह भारत की बेटी थी और उसे न्याय जरूर मिलेगा।

एफएसएल टीम के साथ दोबारा घटनास्थल पर पहुंची क्राइम ब्रांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली कैंट इलाके के पुराना नांगल गांव की नौ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर नमूने जुटाए। गुरुवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया था। जांच टीम घटना वाले दिन आरोपितों की लोकेशन और उनकी काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) हासिल कर रही है। टीम यह भी जांच कर रही है कि वारदात के समय कितने लोग थे। क्राइम बांच की टीम ने अपील की है कि इस मामले में अगर कोई चश्मदीद हो तो वह सामने आए। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर पीड़ितों व स्थानीय लोगों के नए सिरे से बयान दर्ज किए हैं। अब टीम जेल में बंद चारों आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में आरोपितों को रिमांड पर लिया जा सकता है। वहीं, टीम को घटनास्थल पर लगे वाटर कूलर में शार्ट-सर्किट होने की भी जानकारी मिली है। टीम ने वाटर कूलर को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मशीन से फिंगरप्रिंट मिलने की उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सच्चाई जानने के लिए आरोपितों से अलग-अलग पूछताछ की जाएगी। वारदात का सीन रिक्रीएट भी किया जा सकता है। इससे पहले इस मामले की जांच दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस कर रही थी।

पहचान छिपाकर श्मशान में काम कर रहा था आरोपित सलीम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली कैंट इलाके में नौ वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। घटना के मुख्य आरोपितों में से एक सलीम अपना असली नाम छिपाकर श्मशान भूमि परिसर में कार्य कर रहा था। वह लोगों को अपना नाम कभी रामू तो कभी राजू बताता था। मामले से पर्दा उस समय हटा जब एफआइआर में आरोपित का असली नाम पुलिस ने सलीम लिखा। इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि नाम बदलकर काम करने के पीछे सलीम का क्या मकसद था। इसकी भी पुलिस को जांच करनी चाहिए।

> सलीम श्मशान भूमि में अपनी पहचान छिपाकर कार्य कर रहा था। यह जानकारी इस मामले में काफी अहम है। हो सकता है कि घटना का मुख्य षडयंत्रकारी सलीम ही हो। इस पर पुलिस की पूरी निगाह होनी चाहिए और अपराधियों को कठोर सजा शीघ्र मिलनी चाहिए। मामले में तीन माह में फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्णय दे तथा दोषियों को फांसी की सजा के साथ ही पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराए।
>
> –विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विहिप

स्थानीय निवासियों ने बताया कि सलीम को लोग पुजारी का खास सहयोगी मानते थे। वह कभी अपना नाम रामू तो कभी राजू बताता था। ऐसे में किसी को भी उसके मुसलमान होने का शक तक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि संभव है कि पुजारी को भी सलीम ने अपना असली नाम नहीं बताया होगा। अब जब राज से पर्दा हटा है तो कई तरह के सवाल लोगों के जेहन में हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि वह कहां का रहने वाला है। क्या इससे पहले भी उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज था। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जांच के दौरान इन सब सवालों के जवाब ढूंढेगी और असलियत सामने आएगी।

रैन बसेरों में रह रहे बेघरों को भोजन देगी अक्षय पात्र संस्था

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे बेघरों को अब सामाजिक संस्था 'अक्षय पात्र' भोजन उपलब्ध कराएगी। भोजन दो समय दोपहर व शाम को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार और संस्था के बीच अगले छह माह के लिए करार हुआ है। भोजन के लिए पूरा खर्च संस्था अपनी ओर से उठाएगी।

राजधानी में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) रैन बसेरे चलाता है। दिल्ली में 209 रैन बसेरे हैं। इनमें करीब 10 हजार लोग रहते हैं। विभिन्न संस्थाओं की ओर से इन लोगों को भोजन दिया जाता है। मगर अब इन लोगों को भोजन इस संस्था से मिलेगा। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अक्षय पात्र के चेयरमैन मधु पंडित दास की उपस्थिति में इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा।

साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन किया। उनके साथ काफी संख्या में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारी चंदगी राम अखाड़े से नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जब दिल्ली में शराब की दुकानें और माल खुल सकते हैं तो इन बाजारों में दुकान लगाकर भरण पोषण करने वालों को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल और पार्कों में साप्ताहिक बाजार लगाने की बात करते थे। उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। कोरोना के मामले बढ़ने पर 27 सौ साप्ताहिक बाजारों को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं इसलिए इन्हें भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन बाजारों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी हैं और काम धंधा बंद हो जाने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।

भाजपा के नेतृत्व में साप्ताहिक बाजार खुलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ती साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोगों की भीड़। ध्रुव कुमार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को बंद कर केजरीवाल सरकार छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम की बसें चल रही हैं। विधानसभा सत्र भी आयोजित हुआ। यहां तक कि शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं, जहां भीड़ लग रह है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे दिल्ली के पांच लाख दुकानदारों को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल सरकार साप्ताहिक बाजार को न खोलकर लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा कर रहे हैं। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, विधायक अभय वर्मा एवं पूर्व महापौर जयप्रकाश सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे हज हाउस : आदेश गुप्ता

जासं, नई दिल्ली : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आज कालेज, स्कूल और अस्पतालों की कमी है। उनको बनाने के बजाय दिल्ली सरकार लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाकर हज हाउस बनाकर एक विशेष वर्ग को राजनीतिक लाभ के लिए समर्थन दे रही है। द्वारका के सेक्टर-22 में बनने वाला हज हाउस लोगों की भावनाओं के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार मनमानी कर रही है, उसको हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जहां हज हाउस बनाने की बात हो रही है, वहां जब मुस्लिम लोग रहते नहीं है और जो रहते हैं उनकी भी चाहत है कि यहां हज हाउस न बनकर स्कूल, कालेज या अस्पताल बने तो फिर हज हाउस बनाने का क्या मतलब।

अरावली का मामला

सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया, अभी चल रही जांच, फरीदाबाद के खोरी गांव में वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने का मामला

अवैध निर्माण मामले में हरियाणा ने मांगा समय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के मामले में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूरजकुंड रोड पर स्थित मैरिज फार्म और बैंक्वेट हाल के मामलों में जांच कर पता लगाया जा रहा है कि ये वन भूमि पर बने हैं कि नहीं। राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि अभी जांच चल रही है। इसलिए कोर्ट मामले की सुनवाई 10 दिन के लिए टाल दे। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी।

यह आदेश जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मैरिज फार्म और बैंक्वेट हाल की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई टालते हुए दिया। हरियाणा सरकार की ओर से शुक्रवार को सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। मेहता ने कहा कि अर्जीकर्ताओं ने ज्ञापन दिए हैं। अभी जांच चल रही है कि इनका निर्माण वन भूमि में आता है कि नहीं। ऐसे में कोर्ट प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दे दे। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 20 अगस्त तक टाल दी। साथ ही अपना अंतरिम आदेश भी 20 अगस्त तक बढ़ा दिया। यह मामला 14 मैरिज फार्म और बैंक्वेट हाल की ओर से दाखिल की गई अर्जी का था। इसके अलावा शुक्रवार को कुछ नए अर्जीकर्ता भी कोर्ट आए। उन्होंने भी कोर्ट से मामले की जांच होने तक डिमोलेशन से संरक्षण दिए जाने की मांग की। पीठ ने कहा कि उसका आदेश बहुत स्पष्ट है। वन भूमि पर जो भी अवैध निर्माण होगा, वह हटाया जाएगा। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज से कहा कि अगर अर्जीकर्ताओं का वन भूमि पर अवैध निर्माण है तो हटा दिया जाए और अगर वन भूमि पर नहीं है तो 20 अगस्त तक उसे न हटाया जाए। इस मामले में सूरजकुंड रोड पर स्थित 14 मैरिज फार्मों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नगर निगम के अवैध निर्माण हटाने के लिए भेजे गए नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मांग की है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह स्पष्ट रूप से वन भूमि चिह्नित करे। यह भी कहा गया है कि नियम के मुताबिक शुल्क लेकर उनके मैरिज फार्म नियमित किए जाएं। अर्जीकर्ताओं का कहना है कि उनके मैरिज फार्म जहां हैं, वह जगह अधिसूचित वन क्षेत्र नहीं है।

मालूम हो कि खोरी गांव के पास वन भूमि से करीब 10 हजार अवैध निर्माणों को हटाने के मामले में कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को अवैध निर्माण हटाने के लिए 23 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वन भूमि पर हर तरह का अवैध निर्माण हटाया जाएगा।

एमिटी के ग्रुप वाइस चांसलर से मांगी 50 लाख की रंगदारी

जासं, नोएडा: एमिटी यूनिवर्सिटी के ग्रुप वाइस चांसलर के मकान पर कब्जा कर उनसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फेस दो रंगदारी मांगने वाले आरोपित को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना फेस-2 प्रभारी ने बताया कि सेक्टर-92 निवासी गुरजिंदर सिंह एमिटी यूनिवर्सिटी के ग्रुप वाइस चांसलर है। गुरजिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2019 में दिल्ली के रहने वाले हरचरण सिंह सरना को अपना मकान किराये पर दिया था। इस दौरान रेंट एग्रिमेंट भी किया गया था। इसके तहत नवंबर 2020 में हरचरण को मकान खाली करना था। आरोप है कि कई बार कहने के बावजूद उसने मकान खाली नहीं किया। आरोपित ने पड़ोसी के माध्यम से गुरजिंदर के पास संदेश भिजवाया कि वह 50 लाख रुपये देगा तो मकान खाली हो जाएगा। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी।

डीयू ने वापस लिया 16 अगस्त से कक्षाएं चलाने का फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- स्नातक, स्नातकोत्तर के विज्ञान वर्ग के छात्रों की नहीं चलेंगी फिजिकल कक्षाएं
- शिक्षक संगठनों ने डीयू के फैसले का किया था विरोध

दिल्ली विश्वविद्यालय व कालेज अब 16 अगस्त से नहीं खुलेंगे। डीयू ने स्नातक, स्नातकोत्तर के विज्ञान वर्ग के छात्रों की फिजिकल कक्षाएं चलाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। ऐसा राज्य सरकार द्वारा कालेज खोलने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं होने व शिक्षकों के विरोध के चलते किया गया है। हालांकि शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों के कालेज में नियमित आने के फैसले को नहीं बदला गया है।

डीयू सूत्रों ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज खोलने को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं। डीयू परिसर या कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। हालांकि फैसला बदलने के पीछे शिक्षक संगठनों का विरोध भी एक वजह है। कालेज खोलने के डीयू के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की थी। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने कार्यवाहक कुलपति प्रो. पीसी जोशी को पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। डीयू को पहले महामारी की स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए था। फैकल्टी और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए थी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा चुकी है। डीयू के छात्र विभिन्न राज्यों से आते हैं। ऐसे में छात्रों से संक्रमण फैलने का खतरा है। एनडीटीएफ ने डीयू कुलपति से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की थी।

1,427 शिकायतें मिली थीं 2019–20 में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल को। 2020–21 में घटकर सिर्फ 110 और चालू वर्ष में 12 रह गई। यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पर बदल रहा अमेरिका

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी को लेकर अमेरिका का रुख बदल रहा है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि शुक्रवार को इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वह पिछले पांच-छह वर्षों के रवैये से अलग है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका यूएनएससी के विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन दूसरे देशों को वीटो करने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल के महीनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से तीन बार मुलाकात हुई है। दोनों के बीच विस्तार से द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा भी हुई है लेकिन उसमें यूएनएससी के विस्तार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम यूएनएससी में कुछ विस्तार के समर्थन में हैं और स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर सहमति बनाने के पक्ष में हैं। परंतु, इसके वीटो के अधिकार का विस्तार नहीं होना चाहिए। प्राइस का यह वक्तव्य भारत को समर्थन देने की अभी तक की अमेरिकी नीति से अलग है। सनद रहे कि यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्य हैं- अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। भारत की दावेदारी का अभी तक चीन के अलावा सभी चारों देश समर्थन करते रहे हैं। वर्ष 2015 में पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की बैठक के बाद और 25 फरवरी, 2020 को पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की आधिकारिक बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में साफ तौर पर कहा गया था कि यूएनएससी में शामिल किए जाने पर भारत की दावेदारी का अमेरिका समर्थन करता है।

बाइडन प्रशासन का रवैया अलग : हाल के दिनों में यह पहला मौका नहीं है जब बाइडन प्रशासन की तरफ से भारत की इस दावेदारी को समर्थन देने में हिचकिचाहट दिखाई गई है। इसके पहले जनवरी, 2021 में यूएन में अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थामस ने भारत, जापान, जर्मनी व ब्राजील के समूह-चार को समर्थन देने के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था और कहा था कि इस बारे में काफी क्षेत्रीय विरोध है।

स्थिति में नहीं आएगा कोई बदलाव

जानकारों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से स्पष्ट समर्थन नहीं मिलने का जमीनी तौर पर स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चीन के समर्थन के बगैर इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका के समर्थन के बावजूद भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया है कि चीन इसकी राह में हर बार अड़ंगा डाल देता है। भारत अभी दो वर्षों के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है।

भारत, श्रीलंका व मालदीव ने की उप एनएसए स्तर की पहली बैठक

कोलंबो, एएनआइ : भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच पहली बार उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की वर्चुअल बैठक हुई। बुधवार को हुई बैठक का लक्ष्य समुद्री एवं तीनों देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर करीबी सहयोग तैयार करना था।

यह बैठक श्रीलंकाई सेना प्रमुख एलएचएससी सिल्वा की अध्यक्षता में हुई। भारत के उप एनएसए पंकज सरन और मालदीव के एनएसए कार्यालय के सचिव ऐशाथ नूशिन वाहिद ने बैठक में भाग लिया। बांग्लादेश, मारीशस और सेसेल्स पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। बैठक में कोलंबो सुरक्षा कान्क्लेव के तहत सहयोग के चार स्तंभों की पहचान की गई। इसमें समुद्री संरक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरपंथ, तस्करी एवं संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

बैठक के दौरान भारत, श्रीलंका और मालदीव ने क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग एवं समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। तीनों देशों ने सहयोग के लिए विशेष प्रस्ताव पर भी चर्चा की ओर नियमित संवाद, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधि आयोजित करने का फैसला किया।

कतर के विशेष प्रतिनिधि मुतलाक नई दिल्ली पहुंचे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा शुरू होने के साथ ही कतर के विदेश मंत्री के विशेष प्रतिनिधि मुतलाक बिन माजेद अल-कहतानी नई दिल्ली पहुंचे हैं। अल-कहतानी का नई दिल्ली पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ वह दोहा में चल रही अफगान शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा रहे थे बल्कि माना जाता है कि पूर्व में भारत का तालिबान से संपर्क कराने में भी उनकी अहम भूमिका थी।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अल-कहतानी ने शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान) जेपी सिंह से मुलाकात की और उन्हें शांति वार्ता की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। साथ ही अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर भी चर्चा हुई। उनकी कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है।

अल-कहतानी की इस यात्रा की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि वह शनिवार को वदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष शृंगला से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे।

कहतानी को अभी अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। वो अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में होने वाली हर वार्ता में शामिल रहे हैं, बल्कि जब भी वार्ता की डोर कमजोर होती दिखी तो उन्होंने दोनों पक्षों को फिर से इसके लिए राजी करने का भी काम किया है। अल-कहतानी ने ही जून, 2021 में यह दावा किया था कि उन्होंने भारत और तालिबान के बीच संपर्क स्थापित करवाया है। भारत इस बात से आधिकारिक तौर पर इन्कार करता रहा है। वह कतर के विदेश मंत्री के आतंकवादरोधी व विवाद निपटान के क्षेत्र में विशेष प्रतिनिधि हैं।

▸ अफगानिस्तान शांति वार्ता में अल-कहतानी की अहम भूमिका

मुतलाक बिन माजेद। फाइल/इंटरनेट मीडिया

ट्विटर ने नियुक्त किए शिकायत अधिकारी

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए आखिरकार ट्विटर ने नए आइटी नियमों के तहत मुख्य शिकायत अधिकारी (सीसीओ), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति (एनसीपी) की स्थायी नियुक्ति कर दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर ट्विटर ने चार अगस्त को हुई इस नियुक्ति की जानकारी दी। पीठ ने इसे रिकार्ड पर लेने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता व केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या ट्विटर की तरफ से नियमों का अनुपालन किया गया है। इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है, लेकिन हमें सत्यापित करना होगा। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने ट्विटर की तरफ से दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जाहिर की थी। पीठ ने कहा था कि ट्विटर बार-बार भ्रमित करने वाले हलफनामा पेश कर रहा है। अमित आचार्य ने याचिका दायर कर कहा था कि नए आइटी नियमों का ट्विटर अनुपालन नहीं कर रहा है। एक मामले में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने पर उन्हें पता चला कि ट्विटर ने अब तक नए आइटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है।

न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खेदजनक बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पद नहीं भरे जाने को खेदजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से बताने को कहा है कि इस सिलसिले में उसने क्या कदम उठाया है? अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने आशंका जाहिर की है कि इसके पीछे संभवतः कुछ लाबी काम कर रही है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में स्पष्ट रुख जानना चाहते हैं कि न्यायाधिकरणों को जारी रखा जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि नौकरशाही इन न्यायाधिकरणों को नहीं चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण से लेकर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण तक कुल 15 अर्ध न्यायिक निकायों में पीठासीन अधिकारी के 19 पद रिक्त हैं। इसके अलावा न्यायिक सदस्यों के 110 और तकनीकी सदस्यों के 111 पद रिक्त हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन न्यायाधिकरणों में लोगों की नियुक्ति नहीं करने को लेकर वह वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर उनसे इसका कारण पूछ सकती है। पीठ ने कहा, हमें उम्मीद है कि एक सप्ताह में आप इस पर ध्यान देंगे और हमें इससे अवगत कराएंगे। अन्यथा हम इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। हम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर इसका कारण पूछ सकते हैं। कृपया ऐसी स्थिति न आने दें।

भारी–भरकम दस्तावेज रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में भारी-भरकम दस्तावेज पेश करने पर नाराजगी जताई और कहा कि इसका मकसद जजों को आतंकित करना है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आदेश पर बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में 51 खंडों में दस्तावेज पेश किए गए हैं। इसका क्या मकसद है? हम इन्हें नहीं पढ़ सकते।

पेगासस के साथ किसानों के मुद्दे पर आक्रामक हुआ विपक्ष

सियासी संग्राम ▸ जंतर–मंतर पर जाकर किसान संसद में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के अन्य नेता

हंगामे के चलते सुचारू रूप से नहीं चली संसद, सरकार ने पारित कराए दो अहम विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड पर जारी सियासी संग्राम के बीच विपक्षी दलों ने मानसून सत्र में सरकार की घेरेबंदी के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए शुक्रवार को संसद की कार्यवाही के बजाय कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जारी किसान संसद में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुआई में 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से जंतर-मंतर जाकर कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग का समर्थन किया। पेगासस कांड के साथ किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर वार जारी रखते हुए हंगामा कर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का सिलसिला भी जारी रखा। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं के किसान संसद में आने को सही ठहराते हुए कहा कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ हम अपना समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुआई में 14 विपक्षी दलों के नेताओं की हुई बैठक में पेगासस के साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को जोर-शोर से उठाने की रणनीति बनी और संसद भवन से एकजुट होकर जंतर-मंतर पर किसान संसद में जाने का फैसला हुआ। इसी के अनुरूप राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और सदन कई बार स्थगित हुआ। सदन के स्थगन के दौरान ही दोपहर 12.30 बजे संसद भवन से राहुल गांधी और खड़गे के साथ विपक्षी दलों के नेता एक बस में सवार होकर जंतर-मंतर पहुंचे। हालांकि विपक्षी नेता न किसान संसद के मंच पर गए और न ही वहां कोई भाषण दिया, बल्कि सभी वहां बनाए गए दर्शक दीर्घा में बैठे और किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। इनमें राहुल और खड़गे के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत, द्रमुक के तिरुची शिवा, माकपा के इलामारम करीम, भाकपा के विनय विश्वम, राजद के मनोज झा आदि मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस और आप के नेता जंतर-मंतर पर गए विपक्षी नेताओं में शामिल नहीं थे।

किसान संसद में हिस्सा लेने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर किसान की समस्याओं और इन काले कानूनों को हटाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पेगासस पर बात करना चाहता है, पर इस जासूसी कांड पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है। किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के सवाल पर राहुल ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून हैं और इनको रद करना पड़ेगा।

जंतर-मंतर के साथ ही संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष का सरकार पर हमला जारी रहा और कृषि कानूनों व पेगासस पर हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इसी हंगामे के दौरान लोकसभा ने कर सुधार से संबंधित बेहद अहम विधेयक और लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक पारित कर दिए। सियासी गतिरोध व हंगामे में ही विधेयक पारित कराने के सरकार के तौर-तरीके पर विपक्षी विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सुधार से जुड़े विधेयक पर अपनी संक्षिप्त बात रखी और फिर इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी तरह लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर अपनी बात रखी और पीठासीन सभापति ने हंगामे में ध्वनिमत से विधेयक पारित होने का एलान कर सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा भी कई दौर के हंगामे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

नई दिल्ली में जंतर–मंतर पर कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रही किसान संसद में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व अन्य विपक्षी दलों के नेता। प्रेट्र

प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता को सरकार तैयार : तोमर

नई दिल्ली, प्रेट्र : जंतर-मंतर पर तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमेशा वार्ता करने को तैयार है।

तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार कृषि कानूनों पर किसान यूनियनों से भी बातचीत करने को तैयार है और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए भी सरकार तत्पर है। मंत्री ने कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है।

सात महीने से भी अधिक समय से मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर शिविर लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि इन तीन कानूनों से फसल पर सरकार की ओर से मिलने वाला समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार की इजाजत से इनमें से 200 किसानों के एक दल ने दिल्ली के जंतर-मंतर में संसद परिसर से कुछ सौ मीटर की दूरी पर कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन शुरू कर रखा है।

नरेंद्र सिंह तोमर बोले, प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए भी सरकार तत्पर।

खेल पुरस्कार का नाम बदलने का कांग्रेस ने किया स्वागत

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर महान हाकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदूरदर्शी राजनीति का नमूना भी कहा है जिसमें मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी के नाम का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस ने आशा जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने और अरुण जेटली के नाम वाले प्रमुख स्टेडियमों के नाम बदलकर उन्हें मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और पीटी ऊषा के नाम करेंगे। सरकार ने टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय हाकी टीमों के अच्छे प्रदर्शन के बाद मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नामकरण किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया में कहा, ओलिंपिक वर्ष में खेलों का बजट घटाने वाली केंद्र सरकार ने किसानों, पेगासस और महंगाई के मसलों से ध्यान हटाने के लिए नाम बदलने का यह काम किया है। सुरजेवाला ने कहा, राजीव गांधी की पहचान किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि उनके बलिदान और विचारों से है। उन्हें देश को 21 वीं सदी की ओर ले जाने वाले विकासोन्मुखी कदमों के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि खेल पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाना भाजपा और आरएसएस की नेहरू-गांधी परिवार के प्रति घृणास्पद राजनीति को प्रदर्शित करता है।

रणदीप सुरजेवाला ने दी प्रतिक्रिया। फाइल

लक्षद्वीप के मुख्य प्रशासक को हटाने के लिए प्रदर्शन

नई दिल्ली, एएनआइ : केरल के वाम दलों और कांग्रेस के सदस्यों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास लक्षद्वीप के मुख्य प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को कई सांसदों को प्रतिमा के पास 'सेव लक्षद्वीप' के प्लेकार्ड लिए खड़े देखा गया। लक्षद्वीप में लोग कई कानूनों के मसौदों का विरोध कर रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप प्रिवेंशन आफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन (गुंडा एक्ट), लक्षद्वीप एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन एंड लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, 2021 आदि।

इंडियन मुस्लिम लीग के ईटी मुहम्मद बशीर ने कहा कि पूरे दिल से लक्षद्वीप के प्रति सद्भावना है। ऐसी जगहों पर अलोकतांत्रिक कानून लाए जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उन्हें प्रशासक को वापस बुलाना चाहिए। भाकपा के सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि लक्षद्वीप के लिए संघर्ष हो रहा है। वामदल, यूडीएफ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए।

सिंधु जल संधि पर पाक से वार्ता करने का दिया सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान से बातचीत की सिफारिश की है, ताकि नदी घाटी में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के असर से निपटा जा सके। इसके अलावा संधि में जिन चुनौतियों का जिक्र नहीं है, उस पर भी बातचीत करने को कहा गया है।

जल संसाधन पर संसद की स्थायी समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे, ताकि वह भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बदलाव न कर सके।

समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत पूरब की सभी नदियों-सतलज, व्यास और रावी के पानी का आवंटन भारत को किया गया है। पश्चिम की नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटन किया गया है। संधि के अनुसार, भारत को विशिष्ट मानदंडों के अनुरूप पश्चिमी नदियों पर नदी घाटी परियोजनाओं के जरिये पनबिजली उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यह संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय पनबिजली परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी देती है। समिति का मानना है कि सरकार को इस संधि के प्रविधानों के अधिकतम इस्तेमाल की संभावना पर विचार करना चाहिए।

- ▸ नदी घाटी में पानी की उपलब्धता पर न पड़े जलवायु परिवर्तन का असर
- ▸ ब्रह्मपुत्र पर चीन की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखने की सिफारिश
- ▸ संसद की स्थायी समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की डिग्रियां मान्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की डिग्रियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने साफ किया है, कि इसकी डिग्रियां पूरी तरह से मान्य हैं। इस संस्थान का गठन भी संसद के नियमों के तहत हुआ है। इसे भी दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह डिग्री देने का अधिकार है।

यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश भी दिया है, कि वह दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की डिग्रियों को मान्यता दे। साथ ही इसके आधार पर वह उच्च शिक्षा और नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से पात्र है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भी लिखा है। साथ ही सभी भर्ती बोर्ड और उससे जुड़ी एजेंसियों को भी इस संबंध में जानकारी दी है। गौरतलब है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन वर्ष 1964 में संसद के नियमों के तहत किया गया था। तब से यह लगातार हिंदी के क्षेत्र में काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश को मिले 2,400 करोड़ रुपये

जल जीवन मिशन

प्रदेश के 60 हजार गांवों में अगले साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा काम, राज्य के ढाई करोड़ घरों में से फिलहाल 32 लाख घरों में ही कनेक्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में 'जल जीवन मिशन' को रफ्तार देने की खातिर केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 2,400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इससे राज्य में 78 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। दिसंबर 2021 तक राज्य के 60 हजार से अधिक गांवों में पेयजल आपूर्ति की परियोजनाएं चालू हो जाएंगी।

मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास धनराशि की कमी नहीं पड़ेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य के मद में 10,870 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष का 466 करोड़ रुपये बचा हुआ है। राज्य के हिस्से की धनराशि को मिलाकर उत्तर प्रदेश के पास चालू साल में 23,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश के 97 हजार गांवों के 2.63 करोड़ परिवारों में से केवल 32 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति होती है। 'जल जीवन मिशन' की घोषणा से पहले राज्य में केवल पांच लाख से कुछ ही अधिक यानी दो फीसद से भी कम घरों में नल कनेक्शन था। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पांच जिलों को 'हर घर जल' आपूर्ति की योजना बनाई है। जल जीवन मिशन की रफ्तार बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इनमें जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना, प्रबंधन, परिचालन और रख-रखाव के लिए बड़ी संख्या में मिस्त्रियों, प्लंबरों, इलेक्ट्रिशियनों, मोटर मैकेनिकों, पंप आपरेटरों आदि की जरूरत पड़ती है। जल आपूर्ति परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न सामग्रियों सीमेंट, ईंट, रोड़ी, पाइप, वाल्व, पंप, नल आदि की भी आवश्यकता होती है। इससे स्थानीय स्तर पर कारीगरों और घरेलू उत्पादन की मांग बढ़ेगी।

बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों-झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के ग्रामीण इलाकों में नल जल आपूर्ति योजना की आधारशिला फरवरी 2019 में और विंध्याचल के मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला नवंबर 2020 में रखी गई थी। इनके पूरा होने पर यहां के 6,742 गांवों के 18.88 लाख घरों और 1.05 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। केंद्र ने बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों की नल जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने की अपील की है।

बुंदेलखंड, विंध्य, प्रयागराज और कौशांबी के लगभग 140 गांवों में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 'जल जीवन मिशन' का कार्य चालू कर दिया गया है। इसी तरह आगा खान फाउंडेशन ने भी लखनऊ और सीतापुर के 40 गांवों में कार्य शुरू कर दिया है। टाटा ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के तीन जिलों बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के 200 गांवों में तैयारी शुरू कर दी है। जनभागीदारी से 'जल जीवन मिशन' को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द की काम शुरू हो जाएगा।

जेईई–मेन के नतीजे घोषित, 17 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के तीसरे संस्करण के नतीजे घोषित कर दिए। इसमें 17 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल का स्कोर किया है। जिन छात्रों को 100 पर्सेंटाइल मिले हैं उनमें आंध्र प्रदेश के कर्णम लोकेश, डुग्गीनेनी वेंकट पनीश, पसाला वीर सिवा और कंचनपल्ली राहुल नायडू, बिहार के वैभव विशाल, राजस्थान के अंशुल वर्मा, दिल्ली के रुचिर बंसल और प्रवर कटारिया, हरियाणा के हर्ष और अनमोल, कर्नाटक के गौरब दास, तेलंगाना की पोलु लक्ष्मी साई लोकेश रेड्डी, मदुर आदर्श रेड्डी और वेलावली वेंकट तथा उत्तर प्रदेश के पल अग्रवाल और अमैया सिंघल शामिल हैं।

जेईई मेन परीक्षा के लिए 7.09 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसका आयोजन 334 शहरों के 915 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी

250 करोड़ की लागत से राजस्थान में विधायकों के लिए बनेंगे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स। विधानसभा भवन के ठीक सामने ज्योति नगर में बनने वाले 160 फ्लैट्स में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 अगस्त को इस योजना का शिलान्यास करेंगे।

'इंटरनेट मीडिया पर विपक्ष के षड्यंत्रों को करें बेनकाब'

रणनीति ▶ भाजपा की आइटी और इंटरनेट मीडिया विभाग की कार्यशाला में बोले उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ

फील्ड में मजबूती से डटकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

इंटरनेट मीडिया को बेलगाम घोड़ा और बिना माई-बाप का बताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के आइटी व इंटरनेट मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं से कहा है कि इसे नियंत्रित करने के लिए मुकम्मल तैयारी और प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश-विदेश में बैठे कुछ लोग सुनियोजित तरीके से खास मौकों पर इंटरनेट मीडिया पर सच्चाई से परे मुद्दों को उछाल कर सरकार पर दबाव बनाने और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ बिना मुहूर्त देखे इंटरनेट प्लेटफार्म के जरिये विपक्ष के इस षड्यंत्र को बेनकाब करें। विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए योगी ने कहा कि 'यह फील्ड में मजबूती से मोर्चा संभालने का वक्त है।'

शुक्रवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के आइटी और सोशल

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ। जागरण

मीडिया विभाग की कार्यशाला के समापन सत्र में योगी ने पेगासस और राफेल प्रकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया पर ऐसे षड्यंत्रों से निपटने के लिए यदि आपकी मुकम्मल तैयारी नहीं होगी तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने और माहौल खराब करने वाले मुट्ठी भर लोगों को जवाब देना होगा। इसके लिए हमें टीम बनाकर पेशेवर तरीके और पूरी व्यूह रचना के साथ काम करना होगा। योगी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों और कोरोना काल में दोनों सरकारों के कार्यों का उल्लेख करते हुए इन उपलब्धियों को इंटरनेट मीडिया व आइटी के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने की नसीहत दी। लाभार्थियों से मिलकर उनके जीवन में आए परिवर्तनों का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने की सलाह दी। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा में शेर पलते हैं, सियार नहीं। हमारा कार्यकर्ता कल का मोदी-योगी है। उन्होंने बूथ स्तर तक वाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। कार्यकर्ताओं को अपना आचरण ठीक रखने की हिदायत दी।

उपमुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से समसामयिक घटनाक्रम और विपक्ष के तीखे प्रहारों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में जागरूक रहते हुए इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपको विपक्ष की कमजोरियों की जानकारी भी होनी चाहिए। भाषा भी संयमित होनी चाहिए। कार्यशाला के प्रथम सत्र में भाजपा के आइटी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन के सेवा कार्यों को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाई। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं को संगठन के सेवा कार्यों की जानकारी दी।

उप्र में भाजपा की चुनावी तैयारियों को परखेंगे नड्डा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ लखनऊ में आज विधानसभा प्रभारियों संग बैठक, ब्लाक प्रमुख-जिपं अध्यक्षों का मार्गदर्शन भी करेंगे

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी की जमीनी तैयारियों को परखने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार और रविवार को संगठनात्मक प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। पहले दिन वह लखनऊ में विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे तो ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रविवार को वह ब्रज क्षेत्र में संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे।

नड्डा शनिवार सुबह 11 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वह ब्लाक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव के लिए मंत्र देंगे। सम्मेलन में प्रदेश के

जेपी नड्डा जागरण आर्काइव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डा.दिनेश शर्मा तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे।

अब पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लाबिंग शुरू

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

▶ मीणा, गुर्जर और जाट समाज के नेता हो गए हैं सक्रिय

▶ गहलोत खेमे ने मीणा व कटारिया का नाम आगे बढ़ाया

राजस्थान में सत्ता और संगठन में फेरबदल की कवायद के बीच राज्य के कांग्रेसी नेताओं के एक वर्ग ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का अध्यक्ष बनाने को लेकर आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाने को लेकर आलाकमान के समक्ष लाबिंग करने वालों में मीणा, गुर्जर और जाट समाज के नेता शामिल हैं।

राज्य की राजनीति में उक्त तीनों जातियों का खासा प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान में जहां मीणा और गुर्जर दो दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वहीं जाट जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग की राजनीति को प्रभावित करते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की मंशा है कि यदि आलाकमान अध्यक्ष बदलना ही चाहता है तो कार्यसमिति के सदस्य रघुवीर मीणा या राज्य सरकार में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया में से किसी एक को यह पद दिया जाना चाहिए। इसी बीच गहलोत ने अपने विश्वस्तों को साफ कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बिना उनकी मर्जी के राजस्थान को लेकर कोई फैसला नहीं करेंगी। गहलोत लगातार सोनिया गांधी के संपर्क में हैं।

राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने पिछले दिनों राज्य की राजनीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रिपोर्ट दी है। श्रीवास्तव पूर्व में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी के ओएसडी रहने के साथ ही रायबरेली संसदीय क्षेत्र का जिम्मा संभाल चुके हैं। वह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी काम कर चुके हैं।

राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में नई नियुक्तियों को लेकर आलाकमान द्वारा की जा रही कसरत के बीच पायलट खेमा सक्रिय हो गया। पायलट खेमे के विधायक रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, पीआर मीणा, इंद्रराज गुर्जर, राकेश पारीक, वेद प्रकाश सोलंकी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा की पीसीसी अध्यक्ष कुमारी सैलजा, प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की थी। अब ये सभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात का विचार कर रहे हैं। उधर, गत दिनों दिल्ली यात्रा के दौरान सचिन पायलट की प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं से मुलाकात हुई है। पायलट का मानना है कि आलाकमान अपने वादे के अनुरूप उनके समर्थकों को सत्ता और संगठन में समायोजित करेगा। पायलट अगले माह से राज्य का दौरा शुरू कर सकते हैं।

सचिन पायलट अगले माह से शुरू कर सकते हैं राजस्थान का दौरा। फाइल/इंटरनेट मीडिया

गहलोत से मिल रहे मंत्री और विधायक

फेरबदल की कसरत के बीच पिछले चार दिन में लगभग सभी मंत्रियों व करीब तीन दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सीएम से मिलने वालों में तीन निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन विधायकों ने गहलोत के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे सभी दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करने को तैयार हैं। हालांकि, गहलोत ने इन विधायकों से सोनिया गांधी के प्रति विश्वास रखने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि फेरबदल को लेकर पिछले दिनों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन तीन दिन तक जयपुर में रहे थे, लेकिन आलाकमान की मंशा के अनुरूप बदलाव करने को लेकर वह गहलोत को नहीं मना सके थे। आलाकमान ने गहलोत से बात करने के लिए कुमारी सैलजा और कर्नाटक के पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी जयपुर भेजा था।

योगी के शासनकाल में कुख्यातों की 1848 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफिया व अपराधियों की काली कमाई जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मार्च, 2017 से जुलाई माह के बीच पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत माफिया व अपराधियों की रिकार्ड 1848 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। माफिया के कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर बेधड़क चला है।

एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि मार्च, 2017 से अब तक गैंगेस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज कर 43,294 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। 630 आरोपितों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये तक के 10,402 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 50 हजार रुपये से अधिक के 107 अपराधी पकड़े गए। गैंगेस्टर एक्ट के 1447 प्रकरणों में पुलिस ने माफिया व अपराधियों की 1848 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति जब्त की है।

असम व मेघालय सीमा विवाद हल करने को आगे आए

गुवाहाटी, प्रेट्र : मिजोरम के साथ हाल के हिंसक सीमा विवाद से सबक लेते हुए असम ने मेघालय के साथ अपने सीमा मसलों को सुलझाने के लिए अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के बीच वार्ता में इस बावत दो समितियों के गठन पर सहमति बनी। दोनों प्रदेशों में कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली ये समितियां 12 विवादित इलाकों में से छह पर वार्ता कर उनसे जुड़े मसले निपटाएंगी।

दोनों मुख्यमंत्रियों की संयुक्त प्रेस वार्ता में सरमा ने कहा, जो मसले दोनों प्रदेशों की वार्ता में नहीं निपटेंगे, उन्हें केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। क्षेत्रीय समितियों के संबंध में निर्णय लिया गया कि उनमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी और विवादग्रस्त इलाकों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। दोनों समितियां 30 दिन में वार्ता कर विवादों के समाधान का मसौदा तैयार कर अपनी-अपनी सरकारों को सौंपेंगी। सरमा ने कहा कि असम की तरफ से किसी इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन मेघालय सरकार का दावा है कि 12 स्थानों पर उसकी जमीन पर असम के लोगों का कब्जा है। इन्हीं में से छह स्थानों के लिए अभी वार्ता शुरू की जाएगी। जिन इलाकों के लिए वार्ता होगी, वे हैं- ताराबाड़ी, गिजांग, हाहिम, बाकलापाड़ा, खानापाड़ा-पिलिंगकाटा और रताचेरा।

मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने कहा, दोनों राज्य सरकारों का लंबे समय से लंबित इन मामलों को लेकर नजरिया स्पष्ट है। दोनों ही इन विवादों का समाधान चाहती हैं। विवादित इलाकों के लोग लंबे समय से इन विवादों का दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। इसलिए, सम्मान और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान करने के लिए दोनों सरकारें आगे आई हैं। यह हम दोनों की राजनीतिक इच्छाशक्ति का नतीजा है।

गुवाहाटी में शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (बाएं) ने असम-मेघालय सीमा विवाद के मुद्दे पर बैठक के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को स्मृति चिह्न भेंट किया। एएनआइ

शुरू नहीं हुआ दोनों राज्यों के बीच आवागमन

असम से मिजोरम आने वाले रास्ते पर लगाई गई रोक अभी पूरी तरह नहीं हटी है। इसी का नतीजा है कि अभी दोनों प्रदेशों के बीच आवागमन शुरू नहीं हुआ है। यह बात मिजोरम के मुख्य सचिव ललनुनमाविया चुआंगो ने कही है। दोनों प्रदेश के बीच हिंसक सीमा विवाद के बाद असम सरकार ने प्रदेशवासियों को मिजोरम न जाने की सलाह दी थी। अब वह एडवाइजरी वापस ले ली गई है लेकिन दोनों तरफ के लोगों का आवागमन अभी भी शुरू नहीं हुआ है।

राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों का विरोध छोड़ने के लिए समझा रही है भाजपा

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

▶ महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे से की मुलाकात

▶ मनपा के चुनाव में मनसे के साथ उतरना चाहती है भाजपा

भाजपा महाराष्ट्र में राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों का विरोध छोड़ने के लिए समझा रही है। अगले वर्ष मुंबई महानगरपालिका (मनपा) के चुनाव में भाजपा राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ लेकर शिवसेना और महाविकास अघाड़ी का सामना करना चाहती है।

शुक्रवार को महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से मिलने उनके दादर स्थित निवास कृष्णकुंज पहुंचे। वहां से निकलने के बाद पाटिल ने मनसे के साथ निकट भविष्य में चुनावी गठबंधन होने से इन्कार किया, लेकिन कहा कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के विरोधी नहीं हैं। भाजपा नेता के अनुसार, उन्होंने राज ठाकरे से कहा कि राज्य के लोग चाहते हैं कि वह नेतृत्व करें, लेकिन इसके लिए उन्हें उत्तर भारतीय समुदाय के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। उनके मन में उत्तर भारतीयों के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा।

दरअसल अगले वर्ष फरवरी में होने वाले मनपा चुनाव के लिए मनसे और भाजपा के नजदीक आने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। इस गठबंधन में

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। एएनआइ

भाजपा के सामने बड़ा रोड़ा राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोधी छवि है। भाजपा इन दिनों कृपाशंकर सिंह समेत कई अन्य उत्तर भारतीय नेताओं को शामिल कर हिंदीभाषी समुदाय में अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में राज ठाकरे की नजदीकी से उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे और भाजपा के साथ आने से मुंबई मनपा चुनाव में शिवसेना को बड़ा झटका दिया जा सकता है। मुंबई की मराठी मतदाता बहुल सीटों पर मनसे, शिवसेना के मतों में भारी सेंध लगा सकती है। पिछले विस चुनाव में शिवसेना से लगभग दो गुनी सीटें जीतकर भी सत्ता से दूर रह गई भाजपा, शिवसेना के गढ़ पर चोट करना चाहती है। पिछले मनपा चुनाव में वह 82 सीटें पाकर भी शिवसेना से सिर्फ दो सीट पीछे रह गई थी। दूसरी ओर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के सात सभासद आए थे, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिन बाद उनमें से छह शिवसेना में शामिल हो गए थे।

रूपाणी बोले, देश में बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : देश में बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कई साल के शासन में उसने ऐसी नीतियां नहीं बनाईं जिनसे बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाती। यह बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यहां एक कार्यक्रम में कही। वह अपनी सरकार के पांच साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।

शुक्रवार को रोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए रूपाणी ने सूरत में 60 हजार युवक-युवतियों को सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनुबंधम रोजगार पोर्टल का लोकार्पण किया। राज्य के जिला एवं तहसील क्षेत्रों में सरकार की ओर से 50 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में 18174 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को गुजरात अप्रेंटिस एक्ट में शामिल किया गया है। सरकार की ओर से 1947 भर्ती मेलों का आयोजन कर अब तक 76326 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अहमदाबाद में 20 एकड़ जमीन पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ स्किल का निर्माण किया जाएगा, जहां 5000 युवक-युवतियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तृणमूल की अविलंब उपचुनाव कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल में सात विधानसभा सीटों के लिए लंबित उपचुनाव कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। टीएमसी के महासचिव व राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की अगुआई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के हाथों विधानसभा चुनाव हार गई थीं। ऐसे में उपचुनाव उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं।

मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता का चार नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में तृणमूल लगातार जल्द से जल्द उपचुनाव की मांग कर रही है। इससे पहले 15 जुलाई को तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया था और जल्द उपचुनाव कराने की मांग की थी। अब मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद पार्थ चटर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तीन महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, पर अब भी उपचुनाव को लेकर आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया है। कोरोना महामारी से उपजे हालात में सुधार के मद्देनजर हमने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही अविलंब चुनाव कराने की मांग की। पार्थ ने यह भी बताया कि हमने आयोग से यह अनुरोध भी किया है कि वह उपचुनाव टालने की कोशिश कर रही भाजपा की बातों में नहीं आए। प्रतिनिधिमंडल में पार्थ के अलावा चार अन्य वरिष्ठ मंत्री सुब्रत मुखर्जी, जावेद अहमद खान, डा. शशि पांजा व चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल थे।

बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच डीवीसी को लेकर राजनीति गरमाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) से पानी छोड़ने को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डीवीसी की शिकायत की थी। अब भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर डीवीसी का बचाव किया है।

ममता ने मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि डीवीसी की ओर से राज्य सरकार को सूचित किए बिना बांधों से पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे हर साल बंगाल के विभिन्न जिलों में बाढ़ आ जाती है। इस पत्र पर नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विस में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर डीवीसी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्र में जो बातें कही हैं, वे झूठी और बेबुनियाद हैं। डीवीसी की तरफ से पानी छोड़ने से पहले हमेशा राज्य सरकार को सतर्क कर दिया जाता है। बंगाल में अभी बाढ़ के जो हालात हैं, इसके लिए राज्य प्रशासन जिम्मेदार है। सुवेंदु ने पत्र में आगे लिखा है कि डीवीसी पूरी तरह से केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है। इसमें बंगाल और झारखंड सरकारों की भी हिस्सेदारी है।

सुवेंदु के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस राय ने कहा कि सुवेंदु जब सिंचाई मंत्री थे, तब डीवीसी पर दोषारोपण किया करते थे और अब भाजपा में शामिल होने के बाद उल्टा राग अलाप रहे हैं।

इस बीच डीवीसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माइथन और पंचेत बांधों की ड्रेजिंग और मरम्मत कार्य में 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि 10,000 करोड़ की लागत से नए बांध का निर्माण किया जा सकता है।

देश में कई नेता पीएम पद के योग्य : उपेंद्र कुशवाहा

जागरण संवाददाता, शेखपुरा

देश में नरेंद्र मोदी के अलावा देश के कई और नेता प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। इसमें नीतीश कुमार भी हैं। शुक्रवार को बिहार के शेखपुरा में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही। कुशवाहा ने कहा कि मेरी मंशा पीएम मोदी को चुनौती देने की नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इतने बड़े देश में कई नेता हैं, जो पीएम पद के योग्य हैं।

उन्होंने कहा कि जदयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए अटूट है। पेगासस मुद्दे को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गंभीर बताया और कहा कि देश की जनता को सब कुछ जानने का हक है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। कहा कि जातीय गणना होनी चाहिए। भाजपा द्वारा जातीय गणना का विरोध करने पर कहा कि जब जनगणना में धार्मिक आंकड़ा जुटाने पर कोई विद्वेष नहीं होता है तो जातीय गणना से कैसे विद्वेष फैलेगा। लालू प्रसाद की बढ़ी सक्रियता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद चिकित्सकों की सलाह पर अपनी बढ़िया सेहत के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं। उनकी इस सक्रियता से राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा।

वहीं, बिहार के पंचायती राजमंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल संबंधी बयान पर कहा कि अगले दो चुनावों तक देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस पद के लिए सुयोग्य और काबिल एकमात्र नरेंद्र मोदी हैं। शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा के निकलते ही सम्राट चौधरी शेखपुरा पहुंचे थे।

उप्र की राजनीति में पांव जमाने में जुटे हैं सहनी, 15 को फिर पहुंचेंगे लखनऊ

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में भाजपा के सहयोगी और एनडीए सरकार का हिस्सा वीआइपी नेता मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में हैं। बिहार के बाद उप्र में पांव जमाने में जुटे सहनी 165 नेताओं को प्रभारी बनाकर उप्र भेजने की तैयारी में हैं। वह 15 अगस्त को लखनऊ में मीडिया सम्मेलन करना चाहते हैं।

महज सात साल में बिहार की राजनीति में पहचान बनाने वाले सहनी अब उत्तर प्रदेश (उप्र) में पार्टी विस्तार की कवायद में जुटे हैं। पिछले महीने पूर्व सांसद और निषाद नेता फूलन देवी की पुण्यतिथि पर सहनी उप्र के 18 प्रमंडलों में फूलन की प्रतिमा लगाने वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन ना तो सहनी प्रतिमा लगाने में सफल हो पाए ना ही वह वाराणसी में प्रवेश ही कर

वीआइपी नेता मुकेश सहनी। फाइल

पाए। सहनी इस बात को भूले नहीं हैं। अब वह 18 प्रतिमाओं पर रोक का जवाब वह 50 हजार प्रतिमा से देने की तैयारी में हैं। विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जागरण से बातचीत में बताया कि वह फूलन देवी की 50 हजार प्रतिमाएं बनवा रहे हैं, जो उप्र में घर-घर में लगाई जाएंगी। इसके साथ ही लाखों लाकेट भी पार्टी बनवा रही है, जिनमें फूलन देवी की फोटो होगी। ये लाकेट युवाओं में बांटे जाएंगे और इस बहाने फूलन देवी के संदेश को घर-घर पहुंचाया जाएगा।

सहनी ने बताया कि अगले महीने वीआइपी के 165 नेता प्रभारी बनकर दो पहिया वाहन से उत्तर प्रदेश जाएंगे। जहां वे चार महीने समय बिताएंगे और संगठन को मजबूत करने के साथ योगी की नीतियों की खामियों से लोगों को अवगत कराएंगे। खुद सहनी का 15 अगस्त को लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। वह लखनऊ में मीडिया सम्मेलन करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर मीडिया से बात करेंगे। इस दौरान निषाद समुदाय से जुड़े कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन वीआइपी में शामिल भी होंगे। सहनी यूपी में 165 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा चुनाव को लेकर पार्टी अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से यूपी में पार्टी बड़ी जीत दर्ज कराएगी।

बंगाल में हिंसा पीड़ित महिलाओं को अब आर्थिक मदद देगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में भाजपा की महिला इकाई विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की शिकार महिलाओं को अब आर्थिक मदद का मरहम लगाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से हिंसा पीड़ित महिलाओं को पांच हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कदम को महिला मतदाताओं को एक संदेश देने के लिए राजनीतिक रूप से एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य में उनकी हिस्सेदारी कुल मतदाताओं का लगभग 49 फीसद है।

दरअसल, चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति द्वारा पिछले महीने सौंपी गई रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से की गई हिंसा में कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। इसको लेकर भाजपा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लगातार हमलावर भी है। वहीं, अब हिंसा पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद देकर भाजपा यह धारणा बनाने की भी कोशिश करेगी कि वह ऐसी पार्टी है, जो महिलाओं की परवाह करती है।

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष व विधायक अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा पीड़ित महिलाओं को उनकी शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने हिंसा का सामना किया। पाल ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जो हिंसा के बाद घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे, उन्हें घर लौटने और बुनियादी आजीविका के लिए हम उन्हें वित्तीय सहायता देंगे सहित कई प्रकार की मदद कर रहे हैं।

3,512 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को कोरोना काल में। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई स्थानों पर टोल प्लाजा बंद रहने से 814.13 करोड़ का नुकसान हुआ।

न्यूज गैलरी

असम और निकोबार में भूकंप के झटके

मोरीगांव : असम और निकोबार द्वीप में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के मोरीगांव जिले में 5.2 रिक्टर पैमाने की तीव्रता का भूकंप आया। जबकि निकोबार द्वीप समूह में 4.6 रिक्टर पैमाने की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फार सेस्मोलाजी (एनसीएस) ने बताया कि दोपहर 12.46 बजे असम के मोरीगांव जिले में धरती कांपी। जमीन से दस किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। (एएनआइ)

रोज वैली चिटफंड घोटाले के सरगना गौतम को जमानत

कोलकाता : हजारों करोड़ रुपये के रोज वैली चिटफंड घोटाले के सरगना गौतम कुंडू को उसकी मां की बीमारी के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट से सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। वह नौ अगस्त से सात दिनों के लिए जेल से बाहर रहेगा। (राब्यू)

ईडी ने महबूबा की मां को फिर पूछताछ के लिए बुलाया

श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मुहम्मद सईद की पत्नी और महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को पूछताछ के लिए अपने स्थानीय कार्यालय में तलब किया है। उनसे मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज मामले में पूछताछ की जानी है। इससे पूर्व ईडी ने उन्हें 14 जुलाई को बुलाया था, लेकिन उन्होंने हाजिर होने के बजाय ईडी से नोटिस भेज मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। (राब्यू)

अब पवित्र गुफा तक रोपवे चलाने की तैयारी

जम्मू : भले ही दो साल कोरोना संक्रमण के चलते श्री अमरनाथ यात्रा न हो पाई हो, लेकिन यदि सबकुछ योजनानुसार चला तो आने वाले कुछ वर्षों में भोले के भक्त रोपवे (केबल कार) से भी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से यात्रा का प्रतिवर्ष आंकड़ा 10 लाख पार करने का प्रयास किया जाएगा। (राब्यू)

शशिकुमार हत्याकांड में दाखिल किया आरोपपत्र

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पांच साल पुराने सी. शशिकुमार हत्या मामले के प्रमुख साजिशकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। हिंदू मुन्नानी (अग्रिम) के पदाधिकारी शशिकुमार की कोयंबटूर में हत्या कर दी गई थी। मामले में एनआइए चार अन्य गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। (प्रेट्र)

'इसरो मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी'

कोच्चि : सीबीआइ ने केरल हाई कोर्ट में तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों और गुप्तचर ब्यूरो (आइबी) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की इसरो साजिश मामले में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान की आइएसआइ जैसी विदेशी खुफिया एजेंसियों ने भारत में क्रायोजेनिक तकनीक के विकास को बेपटरी करने की साजिश रची थी। इस अभियान के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए आरोपितों से पूछताछ जरूरी है। जस्टिस अशोक मेनन के सामने सीबीआइ की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह दलील दी। (प्रेट्र)

राजौरी में मुठभेड़, दो पाक आतंकी ढेर

आतंक का सफाया ▸ दो अन्य आतंकियों के छिपे होने की आशंका

सुरक्षाबल ने पूरे जंगल क्षेत्र को घेर रखा है, देर रात तक चलता रहा आपरेशन

जागरण संवाददाता, राजौरी

जम्मू के राजौरी जिले के थन्ना मंडी इलाके में शुक्रवार को एक मुठभेड़ में सेना व पुलिस ने दो पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के दो अन्य साथियों की तलाश में रात तक आपरेशन जारी रहा। सुरक्षाबल ने पूरे जंगल क्षेत्र को घेर रखा है। जहां मुठभेड़ चल रही है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम को सेना और पुलिस को क्षेत्र में कुछ संदिग्ध तत्वों के मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। रातभर घेराबंदी के बाद शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे भंगाई टाप क्षेत्र में जंगल में पहली गोली चली। इसके बाद सेना व पुलिस ने अपना अभियान तेज किया और अतिरिक्त संख्या में सुरक्षाबल भी मौके पर पहुंचे गए। सुबह करीब 11:30 बजे जंगल के अंदर से एक बार फिर से आतंकियों ने फायर शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पाकिस्तानी हैं।

राजौरी जिले की थन्ना मंडी तहसील के भंगाई क्षेत्र में शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों से बरामद हथियार व अन्य सामान। जागरण

आतंकियों से बरामद हथियार

- दो एके-47 राइफल
- सात मैगजीन
- खाने-पीने का सामान
- कुछ दवाएं

फिलहाल, उनकी पहचान की जा रही है।

मुठभेड़ स्थल में दो अन्य आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस व सेना के उच्चाधिकारी इस पूरे अभियान की कमान संभाले हुए हैं।

10 दिन पहले घुसपैठ की आशंका : आशंका जताई जा रही है कि मारे गए आतंकी लगभग 10 दिन पहले सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए थे। पहले ये आतंकी कालाकोट, राजौरी के छावा क्षेत्र में देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन यह आतंकी वहां से बच निकले। इसके बाद अब यह दल थन्ना मंडी इलाके में देखा गया। हालांकि घुसपैठ को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आतंकियों के साथ एक गाइड भी : सूत्रों के अनुसार, आतंकियों के दल के साथ एक गाइड भी है, जो इन्हें कश्मीर ले जाने के प्रयास में था। दो आतंकियों के मारे जाने के बाद अब सुरक्षा बल गाइड व अन्य दो आतंकियों की तलाश में हैं। देर रात तक कार्रवाई चलती रही।

सांबा में सीमा के पास ड्रोन से गिराए हथियार

जागरण संवाददाता, जम्मू : पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन से हथियार भारतीय क्षेत्र में गिराने की साजिश की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में शुक्रवार की सुबह ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए गए हैं। नाले में जिस जगह हथियार मिले हैं, वह आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता रहा है। यहां से सीमा मात्र दो किलोमीटर दूर है। इस नाले के रास्ते से आतंकी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं, पुंछ जिले में भी सुरक्षाबलों आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू संभाग में ड्रोन की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। गत 26-27 जून की रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से दो बम धमाके किए गए थे। इसके बाद से जम्मू शहर समेत अंतराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन की घुसपैठ की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। गत 23 जुलाई को जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में सुरक्षाबलों ने एक ड्रोन मार गिराया था, जिसमें पांच किलो आईईडी बंधी थी। गत सप्ताह ही सांबा सेक्टर में आधा दर्जन बार ड्रोन देखे गए हैं। आतंकियों की ड्रोन साजिश के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही हाई अलर्ट घोषित किया है। जम्मू-कश्मीर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध तक लगाया जा चुका है।

भारत में सक्रिय आइएस आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश

नीलू रंजन, नई दिल्ली

अहम सफलता

- एक साल तक चले आपरेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियों को मिली कामयाबी
- एक महीने में 21 जगह मारे गए छापे में 10 आतंकी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा अलकायदा के आतंकी माड्यूल को उजागर करने और उससे जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट (आइएस) से जुड़े आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश किया है। पिछले एक महीने में जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल में 21 जगहों पर मारे गए छापे में कुल 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां कई संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लगभग एक साल पहले भारत में सक्रिय आइएस माड्यूल के बारे में जानकारी मिली थी। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये आतंकी 'क्रानिकल फाउंडेशन' के नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल पर बड़ी संख्या में आइएस की दुष्प्रचार सामग्री डाल रहे थे। इस चैनल के पूरी दुनिया में 5,000 सक्रिय सदस्य थे। सुरक्षा एजेंसियों ने छद्म नामों से सक्रिय इसके सदस्यों की पड़ताल शुरू की, तो कर्नाटक के मंगलुरु और बेंगलुरु के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपुरा में इनके लोकेशन का पता चला। धीरे-धीरे इन आतंकियों की पहचान की गई और इस साल मार्च में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच में यह भी पता चला कि इनमें से कई आतंकी आइएस के कब्जे वाले सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ तो अप्रैल, 2019 में ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की कोशिश भी कर चुके थे।

हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे आतंकी : सूत्रों के अनुसार ये आतंकी कश्मीर में आइएस आतंकियों का ढांचा तैयार करने और हमलों को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों को ये धन भी दे रहे थे। गिरफ्तार आतंकी डा. रहीस के पास से बरामद डिजिटल डिवाइस में आइईडी बनाने की तकनीक की विस्तृत जानकारी थी। ये आतंकी हिंदूवादी नेताओं की हत्या कर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और मीडिया संगठनों पर हमला करने की योजना बना रहे थे।

छद्म नाम से आनलाइन पत्रिका निकालता था आतंकी : आइएस के एक अन्य माड्यूल के सरगना जूफरी जौहर दामूदी और उसके सहयोगी अमीन जूहैब को शुक्रवार को कर्नाटक के भटकल से गिरफ्तार किया गया। जूफरी पिछले साल अप्रैल से 'वायस आफ हिंद' नाम से एक आनलाइन पत्रिका निकालता था, जिसमें आइएस के दुष्प्रचार के साथ-साथ भारतीय युवाओं को भड़काने की सामग्री होती थी।

भाजपा नेता और भतीजे की कार से कुचलकर हत्या

जागरण संवाददाता, बदायूं

▸ 15 बीघा तालाब में मछली पालन को लेकर चाचा से चल रही थी रंजिश, दो गिरफ्तार, पांच फरार

उप्र के बदायूं में पंद्रह बीघा तालाब में मछली पालन की रंजिश में भाजपा नेता और उनके भतीजे की हत्या कर दी गई। बाइक में टक्कर मारने के बाद हमलावर चाचा व उसके स्वजन करीब तीन सौ मीटर तक घसीटते ले गए। आरोप है कि हमलावरों ने उनके एक हाथ-पैर भी काट लिए। गुरुवार शाम को हुई घटना को पुलिस हादसा मान रही थी मगर, घायलों के दिए बयान ने वारदात से पर्दा हटाया। इसके बाद सात आरोपितों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को दो को गिरफ्तार कर लिया गया।

बदायूं में गांव अलीपुर चिचैटा के रिटायर्ड सैनिक आर्येंद्र पाल सिंह भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष थे। उनके भाई आजेंद्र पाल सिंह 15 बीघा तालाब पर मछली पालन करते थे, जिस पर चाचा सुभाष चंद्र भी दावा करता था। इसी पर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। गुरुवार शाम करीब पांच बजे आर्येंद्र पाल सिंह अपने भतीजे गौरव उर्फ भोले के साथ बाइक से इस्लामनगर जा रहे थे। स्वजन के अनुसार, कंधरपुर व लभारी गांव के बीच पहले से घात लगाए बैठे सुभाष व अन्य हमलावरों ने आर्येंद्र पाल की बाइक पर कार चढ़ा दी। बाइक फंसी तो आरोपितों ने कार की गति बढ़ा दी और करीब तीन सौ मीटर तक घसीटते ले गए। इस बीच कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई तो आरोपित भाग निकले। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण को हादसा मानकर घायल आर्येंद्र व गौरव को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हालत गंभीर होने पर बरेली भेजा गया मगर, रास्ते में दोनों की मौत हो गई।

झील के दलदल में फंसा है हेलीकाप्टर का मुख्य हिस्सा

कमल कृष्ण हैप्पी, जुगियाल (पठानकोट)

81 घंटे बाद दुर्घटना स्थल का पता चला, विमान जैसा हिस्सा दिखा, असली वजह अभी भी स्पष्ट नहीं

मामून कैंट से उड़ान भरने वाले सेना के ध्रुव हेलीकाप्टर एएलएच मार्क-चार के मंगलवार की सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर रणजीत सागर बांध की झील में दुर्घटनाग्रस्त होने के 81 घंटे बीत जाने के बाद भी दुर्घटना की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। अच्छी खबर यह है कि चौथे दिन एक्सीडेंट प्वाइंट का पता चल गया है। झील में हाई रेजोलूशन कैमरे लगाकर कुछ फोटो भी ली गई है। इसमें विमान जैसा कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब सेना, नेवी और एयरफोर्स की तकनीकी टीमें इसी प्वाइंट के इर्द-गिर्द काम करने में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि शनिवार को कामयाबी हासिल हो जाएगी। शुक्रवार को भी लापता पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल एस बाठ और सह पायलट कैप्टन जयंती जोशी का कुछ पता नहीं लग पाया है। दोनों पायलटों और ब्लैक बाक्स को ढूंढने के लिए सुबह 11 बजे से अभियान शुरू किया गया। बारिश के चलते पहाड़ों से झील में आने वाला पानी मिट्टी भरा होने के कारण गोताखोरों को समस्या आ रही है। नेवी के डीप डाइवर के पास गहरे पानी में फोटोग्राफी करने के लिए तीन प्रकार के पावरफुल कैमरे लाए गए हैं। दोपहर को झील में एक्सीडेंट के कुछ सबूत दिखाई दिए। पूरी तहकीकात करने में अधिकारियों को शाम छह बज गए। हालांकि, इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन, सेना के सूत्रों का कहना है कि शनिवार को अभियान में सफल हो जाएंगे।

- हेलीकाप्टर के पायलट और सह-पायलट का अभी कोई सुराग नहीं
- झील में हाई रेजोलूशन कैमरे लगाकर ली गई कुछ तस्वीरें

रणजीत सागर बांध की झील में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के हेलीकाप्टर के पायलट व सह पायलट की तलाश बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसका एक कारण झील की भौगोलिक स्थिति भी है, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जुड़ी हुई है। जागरण

मुंबई से पनडुब्बी मंगवाने पर चलता रहा मंथन : सेना के सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर तक कोई कामयाबी नहीं मिलती देख उच्चाधिकारियों ने मुंबई से पनडुब्बी मंगवाने पर मंथन किया। कारण यह कि अंदर कम से कम पांच से सात फीट तक गाद जमा है। गोताखोर वहां तक अगर किसी तरह पहुंच भी जाते हैं तो गाद में उनके भी फंसने का खतरा है। इसलिए, झील की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखते हुए पनडुब्बी को मंगवाया जाए।

झील में मिल रहीं अज्ञात लाशें : मंगलवार को झील के पास से दो शव मिले। माना गया कि ये दोनों पायलटों के शव हैं, परंतु बाद में ये जम्मू-कश्मीर के निवासियों के निकले। शवों को वहां की पुलिस के हवाले किया गया।

जांबाजों के साथ विज्ञानियों के लिए भारत रक्षा पर्व

जेएनएन, नई दिल्ली : सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए पिछले 16 साल से देशभर की बहनें दैनिक जागरण के माध्यम से रक्षा बंधन के अवसर पर राखियां भेजती रही हैं। सीमा पर तैनात इन प्रहरी भाइयों को बहनें राखी के माध्यम से अपनी शुभकामनाओं का कवच भेजती हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान दैनिक जागरण के 'भारत रक्षा पर्व' का दायरा बढ़ाते हुए महामारी से लोहा लेने वाले कोरोना योद्धाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की रक्षा के लिए दैनिक जागरण की ओर से कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए थे। इस बार इसमें उन विज्ञानियों को भी शामिल किया जा रहा है, जो देशवासियों को महामारी के प्रकोप से बचाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इन कोरोना योद्धाओं को 'डिजिटल रक्षा सूत्र' प्रदान किया जाएगा।

- कोरोना योद्धाओं को भेजा जाएगा 'डिजिटल रक्षा सूत्र'
- पाठकों की मदद से जागरण करेगा योद्धाओं की पहचान

दैनिक जागरण देशभर के अलग-अलग शहरों में अपने पाठकों, स्थानीय निवासियों और शासन-प्रशासन की मदद से कोरोना योद्धाओं की पहचान करेगा और 'भारत रक्षा पर्व' के दौरान उनको शुभकामना संदेश पहुंचाएगा। पिछले साल 'भारत रक्षा पर्व' के दौरान करीब 50 हजार कोरोना योद्धाओं को दैनिक जागरण के माध्यम से सम्मानित किया गया था। कोरोना महामारी के पहले आयोजित 'भारत रक्षा पर्व' के दौरान करीब 29 लाख से अधिक राखियां व 11 लाख शुभकामना संदेश सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाए गए थे।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ दशक पहले सरकारों द्वारा दिए गए हर एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते थे?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

सीबीआइ ने आरोपित लखन व राहुल को लिया रिमांड पर

जागरण संवाददाता, धनबाद

जज हत्याकांड

▸ सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के ट्रांसफर किए गए हत्याकांड से जुड़े अभिलेख

न्यायाधीश उत्तम आनंद की आटो से टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों लखन वर्मा व राहुल वर्मा को शुक्रवार को पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। सीबीआइ की स्पेशल टीम के एसपी जगरूप एस सिन्हा और एएसपी सह कांड के अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में टीम शुक्रवार की सुबह 10: 40 बजे कोर्ट पहुंची। सीबीआइ के आवेदन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित धनबाद थाना कांड संख्या 300/21 के पूरे अभिलेख को सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया।

इधर, अभिलेख एसडीजीएम की अदालत में पहुंचने के बाद दोपहर 3:44 बजे सीबीआइ के विशेष अभियोजक अदालत पहुंचे। सीबीआइ की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में अभियुक्तों को पांच दिनों के लिए रिमांड में देने की अर्जी पर बहस हुई। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को पांच दिनों के लिए सीबीआइ हिरासत में देने का आदेश जेल प्रशासन को दिया।

एसआइटी ने भी लिया था पुलिस हिरासत में : इससे पूर्व मामले की जांच कर रही पुलिस की एसआइटी ने भी दोनों आरोपितों को 29 जुलाई की शाम पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लिया था। एसआइटी की पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपितों ने नशे में रहने के कारण आटो से टक्कर लग जाने की बात बताई थी। एसआइटी ने पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने से पहले ही दोनों आरोपितों को दो अगस्त को अदालत को वापस कर दिया था।

गुरुवार को एसआइटी ने सौंपा दस्तावेज : झारखंड सरकार की अनुशंसा व उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चार अगस्त को सीबीआइ की स्पेशल टीम ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआइ की टीम चार अगस्त को धनबाद पहुंच गई थी, जबकि उनका सहयोग करने के लिए फोरेंसिक टीम पांच अगस्त को धनबाद पहुंची।

सीबीआइ पर तल्ख टिप्पणी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

पीठ ने कहा कि एक दो मामलों में सीबीआइ जांच के आदेश दिए गए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय एजेंसी ने कुछ नहीं किया। एक साल से ज्यादा समय हो गया है। पीठ ने कहा कि उन्हें अपेक्षा थी कि सीबीआइ के रवैये में कुछ बदलाव आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस रमना ने कहा कि वह ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। वे घटनाएं जानते हैं। इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इससे ज्यादा और नहीं कहेंगे। मामला गंभीर है। पीठ ने वेणुगोपाल से कहा कि वह इस मामले में रुचि लें और न्यायपालिका की मदद करें।

अटार्नी जनरल ने भी जताई चिंता : वेणुगोपाल ने भी जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जज खतरे की जद में रहते हैं। जज को नौकरशाहों से भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि नौकरशाह बंद कमरे में फैसले लेते हैं जबकि जज खुली अदालत में फैसले सुनाते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस मामले में एक लिखित नोट कोर्ट में दाखिल करेंगे।

झारखंड को फटकार : धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच सीबीआइ को दे दी गई है। सीबीआइ ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस पर पीठ ने कहा कि आपने हाथ झाड़ लिए। राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 22 सदस्यीय एसआइटी गठित की थी। दो आटो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया था। एसआइटी ने साक्ष्य एकत्र किए थे। पीठ ने उनसे पूछा कि आपने हलफनामे में जजों को सुरक्षा देने का जो भरोसा दिलाया है आप उसे पूरा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

स्पेशल टास्कफोर्स पर जवाब तलब : कोर्ट ने वेणुगोपाल से कहा कि एक और याचिका कोर्ट में लंबित है जिसमें जजों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। जजों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्कफोर्स बनाने की बात है और गाइडलाइंस तय करने की मांग की गई है।

'शर्मनाक हरकत करने वालों को देश देगा जवाब'

सलाह

ग्रेट ब्रिटेन से हुए मुकाबले के बाद मां और भाइयों से की फोन पर बात, शरारती तत्वों को लेकर परिवार को दी सलाह, संयम बरतें, भाई चंद्रशेखर ने कहा, वंदना ने बढ़ाई परिवार की हिम्मत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

टोक्यो ओलिंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारतीय महिला हाकी टीम की एकमात्र खिलाड़ी वंदना कटारिया ने कहा कि बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने उनके घर के बाहर आतिशबाजी करने के साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को महामूर्ख करार देते हुए उन्होंने कहा कि शर्मनाक हरकत करने वालों को देश जवाब देगा। अपने परिवार के सदस्यों को सलाह दी कि वे परेशान न हों और संयम बरतते हुए इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया न दें।

पिछले दिनों अर्जेंटीना से हुए मुकाबले में भारत की हार के बाद कुछ शरारती तत्वों ने वंदना के घर के बाहर पटाखे छोड़े और जातिसूचक शब्दों के साथ अभद्र टिप्पणी की थी। शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद वंदना ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित अपने घर पर मां और तीन भाइयों से फोन पर बात की। उनके भाई चंद्रशेखर ने बताया कि शरारती तत्वों की हरकत के बाद उनकी मां सोरण देवी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अभी उनका इलाज चल रहा है। वंदना के साथ हुई बातचीत को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि बहन ने कहा है कि 'ऐसी हरकत करने वालों को भी हम पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैंने उनका और गांव का भी तो मान बढ़ाया है।' वंदना ने मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। कहा कि तुम मां का ध्यान रखो। भाई पंकज ने कहा कि इस घटना से वंदना आहत तो हैं, लेकिन उन्होंने न केवल खुद को संभाला, बल्कि परिवार की भी हिम्मत बढ़ाई। पंकज और चंद्रशेखर के अनुसार, ओलिंपिक में भाग ले रही वंदना की इन दिनों परिवार से बेहद कम बात हो पाती है।

मौन से विरोध : वंदना कटारिया। फाइल फोटो

मानवाधिकार आयोग ने हरिद्वार एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने हाकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे छोड़ने और जातिसूचक शब्द कहने की घटना का संज्ञान लिया है। इस घटना को लेकर आयोग ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबुदेई को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा और आरएस मीणा की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को अखबार की प्रति भेज कर उन्हें पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने इस प्रकरण में पुलिस ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।

भगवान विष्णु के प्रिय पीत वर्ण में सजेगी अवधपुरी

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

- अयोध्या के विजन डाक्युमेंट में शामिल किए गए प्रधानमंत्री के सुझाव
- मंदिर मार्ग पूरी तरह से होगा नो व्हीकल जोन, दिव्यांगों को मिलेगी सुविधा

विजन डाक्युमेंट में शामिल किए गए प्रधानमंत्री के सुझावों के मुताबिक अवधपुरी रामरज की चमक से आलोकित होगी। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं, जल्द ही रामनगरी भगवान विष्णु को प्रिय पीत वर्ण की कांति से शोभायमान होगी। 26 जून को अयोध्या के विकास को लेकर बनी योजनाओं की वर्चुअल समीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम सुझाव दिए थे। अयोध्या के विजन डाक्युमेंट में शामिल किए गए प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार नगर के भवनों को एकरूपता प्रदान करने की भी योजना है। माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पीत वर्ण की मिट्टी को इसीलिए रामरज कहा जाता है। अब इस रंग का उपयोग विष्णु के अवतार भगवान राम की नगरी को नवरंग देने के लिए किया जाएगा।

पीएम के सुझाव पर ली एसोसिएट्स विजन डाक्युमेंट के शीर्षक में पहले ही बदलाव कर चुकी है। प्रधानमंत्री रामनगरी का ऐसा विकास चाहते हैं कि यहां मिनी भारत की झलक दिखे। रामनगरी को आस्था और सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र और वैदिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें तीर्थ नगरी अयोध्या, हैरिटेज सिटी, सोलर सिटी, समरस एवं स्मार्ट अयोध्या शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रामनगरी के विकास में पीपीपी माडल को अपनाने का सुझाव रखा है। इसे साकार करने के लिए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह की ओर से निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने की कोशिशें भी आरंभ कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सुझाव हैं उसके अनुसार राममंदिर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नो व्हीकल जोन बनाने को कहा गया है। राममंदिर जाने वाले मार्ग पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की रूपरेखा तय की गई थी, लेकिन अब नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। हालांकि वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा दी जा सकती है।

अयोध्या में अन्य मंदिरों का भी होगा सुंदरीकरण

रघुवरशरण, अयोध्या : राम मंदिर के साथ रामनगरी के अन्य मंदिरों के भी दिन बहुरेंगे। उप्र पर्यटन विभाग ने अपने सर्वे में धार्मिक-आध्यात्मिक महत्व के 37 मंदिरों को सूचीबद्ध किया है। इन मंदिरों का परिपूर्ण सुंदरीकरण तो नहीं हो सकेगा, पर उनका अग्रभाग अवश्य सज्जित किया जाएगा, ताकि उनका परिदृश्य रामनगरी की सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप बदल सके। श्रद्धालुओं को रामनगरी की भव्यता का एहसास हो। सुंदरीकरण के लिए प्रस्तावित मंदिरों की सूची में नागेश्वरनाथ, छोटी देवकाली, कालेराम मंदिर, रत्न सिंहासन, रामकचहरी, लक्ष्मणकिला आदि प्रमुख है।

फिर बढ़ने लगे मामले, 44 हजार नए संक्रमित

बढ़ी चिंता ▶ आधे से ज्यादा नए केस केरल में ही मिले

बीते 24 घंटे में सक्रिय मामले भी 3,083 बढ़े, कुल एक्टिव केस 4.14 लाख

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से नए मामले 40 हजार के आसपास ही बने हुए थे, जिनमें से आधे से अधिक मामले केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों से आ रहे थे। बीते 24 घंटे में 44,643 नए केस मिले हैं जो पिछले कुछ दिनों के दौरान सबसे ज्यादा हैं, इसमें से भी 22 हजार से ज्यादा मामले अकेले केरल से हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 41 हजार मरीज ठीक हुए हैं। इसके चलते सक्रिय मामलों में तीन हजार से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में सक्रिय मामले 4,14,159 हो गए हैं जो कुल संक्रमितों का 1.30 फीसद है। हालांकि, दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर अभी तीन फीसद से नीचे ही बनी हुई है।

कोरोना से दिवंगत 101 पत्रकारों के परिवारों के लिए 5.05 करोड़ मंजूर: सरकार ने कोविड-19 के कारण दिवंगत हो गए 101 पत्रकारों में से हर एक के परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता देने के लिए 5.05 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसे पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है।

पटना में महिला सुरक्षाकर्मियों का कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल लेते स्वास्थ्यकर्मी। एएनआइ

▶ 101 पत्रकारों में से हर एक के परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता देने के लिए मंजूर की गई राशि

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	44,643
कुल सक्रिय मामले	4,14,159
24 घंटे में टीकाकरण	57.97 लाख
कुल टीकाकरण	49.53 करोड़

शुक्रवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	44,643
कुल मामले	3,18,56,757
सक्रिय मामले	4,14,159
मौतें (24 घंटे में)	464
कुल मौतें	4,26,754
ठीक होने की दर	97.36 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.72 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.41 फीसद
जांचें (गुरु.)	16,40,287
कुल जांचें (गुरु.)	47,65,33,650

देश में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 83 मामले मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में चार अगस्त तक कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के कुल 83 मामले पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33, मध्य प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 10 मामले हैं। शुक्रवार को लोकसभा को एक लिखित में जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने यह जानकारी दी।

कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पवार ने कहा कि सार्स-कोव-2 के वैरिएंट पर नजर रखने के लिए शुरुआत में पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) में जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू की गई थी। बाद में सरकार ने 10 प्रयोगशालाओं को मिलाकर इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक कंसोर्टियम (इंसाकाग) का गठन किया। धीरे-धीरे प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई।

इस सवाल पर कि क्या निजी प्रयोगशालाओं को भी जीनोम सिक्वेंसिंग करने की अनुमति दी गई है, पवार ने कहा कि इंसाकाग में निजी प्रयोगशालाओं को शामिल करने का मुद्दा विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं ने इंसाकाग में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है और उनकी क्षमता के आधार पर इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा।

निजी अस्पतालों ने अब तक 3.56 करोड़ डोज खरीदीं

स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने एक अन्य सवाल पर सदन को बताया कि दो अगस्त तक निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना वैक्सीन की कुल 3.56 करोड़ डोज की खरीद की गई। उन्होंने कहा कि एक बार निजी अस्पतालों द्वारा खरीदी गई वैक्सीन को दोबारा सरकारी टीका केंद्रों को आवंटित नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल और पाजिटिव लोगों के क्लीनिकल डाटा भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है ताकि मामलों में वृद्धि और वैरिएंट के बीच संपर्कों का पता लगाया जा सके।

एक सवाल के लिखित जवाब में पवार ने कहा कि उत्पादकों द्वारा बताया गया है कि कोविशील्ड की मासिक उत्पादन क्षमता को 11 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ और कोवैक्सीन की मासिक उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5.8 करोड़ डोज करने की योजना है। 16 जनवरी के बाद से अब तक कोविशील्ड की 44.42 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 6.82 करोड़ डोज की आपूर्ति की गई है।

उप्र के निजी अस्पतालों से वापस हुईं 45 लाख वैक्सीन

आशीष त्रिवेदी लखनऊ

कवायद

▶ अगस्त में भी 50 लाख वैक्सीन हाथ से फिसलने का खतरा

▶ दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगवाने को लग रही कतार

कोरोना से बचाव के टीकों में सरकार 75 फीसद वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में और 25 फीसद निजी अस्पतालों को देती है। पहली नजर में यह आंकड़े देख कर कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्र को सरकारी के मुकाबले एक तिहाई वैक्सीन ही दी जा रही हैं, लेकिन सच यह है कि एक ओर सरकारी अस्पतालों में 75 फीसद सप्लाई के बावजूद वैक्सीन की अक्सर कमी हो जाती है तो दूसरी ओर निजी अस्पताल मात्र 25 फीसद वैक्सीन भी नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह कि बीते जुलाई माह में उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों को दी गईं 47 लाख में से 45 लाख वैक्सीन वापस हो गईं, जबकि इस महीने अगस्त में यह संख्या और बढ़ने की आशंका है।

दरअसल सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लग रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए शुल्क लिया जा रहा है। यही बड़ी वजह है कि मुफ्त वैक्सीन के आगे खर्च वाली वैक्सीन टिक नहीं पा रही। नागरिकों को निजी अस्पताल में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने की बजाए सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाकर मुफ्त टीका लगवाना बेहतर लग रहा है। हालांकि निजी अस्पतालों से टीका वापस होने के लिए इस अस्पतालों की बेरुखी भी कम जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश के 15 हजार निजी अस्पतालों में से अब तक सिर्फ 104 अस्पताल ही टीका लगाने के लिए आगे आए हैं। इसी कारण जुलाई में निजी अस्पतालों के लिए तय 25 प्रतिशत कोटे की 47 लाख वैक्सीन में से 45 लाख टीके वापस हो गए। अगस्त में यूपी को कुल 2.08 करोड़ टीके मिलने हैं। इसमें 1.56 करोड़ वैक्सीन सरकारी अस्पतालों को और 52 लाख टीके निजी अस्पतालों के लिए हैं। वैक्सीन लगाने में निजी अस्पतालों का जुलाई जैसा ही रवैया रहा तो अगस्त में भी 50 लाख टीकों से प्रदेशवासी वंचित हो सकते हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डा. अजय घई ने बताया कि निजी अस्पतालों की बची वैक्सीन सरकारी अस्पतालों को दिए जाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। टीकाकरण के मामले में यूपी देश में अव्वल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डा.अशोक राय कहते हैं कि बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने के केंद्र होने से पैसा देकर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग निजी अस्पतालों की ओर कम ही रुख कर रहे हैं। फिर निजी अस्पतालों को वैक्सीन लगाने के लिए डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही डाटा फीडिंग के लिए कंप्यूटर आपरेटर की भी व्यवस्था करनी होती है, जिससे वे दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं।

हिसार की नलवा लैब पर ईडी का छापा, घंटों पूछताछ

जासं, हिसार : हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में आरोपों में आई हिसार की लैब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापे मारे हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ के 18 अधिकारियों की इस टीम ने रेड स्कवेयर मार्केट स्थित नलवा लेबोरेट्री पर दस्तावेज खंगाले। लैब संचालक हिसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) प्रधान डा. जेपीएस नलवा और उनके बेटे से पूछताछ की गई। सुबह सात बजे से शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी थी।

बताया जा रहा है कि ईडी ने स्थानीय पुलिस को सुबह पांच बजे ही नलवा लैब पर तैनात करा दिया था। इसके बाद सात बजे ईडी की टीम पहुंची। पहले स्थानीय स्तर पर दस्तावेज देखे, सवाल जवाब लिए इसके बाद हिसार आइएमए प्रधान डा. जेपीएस नलवा के बेटे डा. नवतेज नलवा को भी लेकर आया गया। टीम ने उनसे भी देर तक पूछताछ की। दैनिक जागरण ने डा. जेपीएस नलवा से बात करने का प्रयास किया, मगर, उनका फोन नहीं उठा।

इलाज में तय दर से ज्यादा पैसे लेने पर अस्पताल का पंजीयन रद

जागरण संवाददाता, पटना

कोरोना के इलाज में सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर पटना के पुष्पांजलि हास्पिटल का पंजीयन रद कर दिया गया है। जिले के सिविल सर्जन ने क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। यहां कोरोना मरीजों के उपचार पर रोक लगा दी गई है। अब ये अस्पताल आयुष्मान भारत, सीजीएचएस, ईएसआइसी आदि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। यदि अस्पताल कोरोना संक्रमितों को भर्ती करता पाया गया तो प्राथमिकी व सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।

हार्ट विशेषज्ञ की जगह बुलाता था निश्चेतक को : राजधानी के भागवत नगर स्थित पुष्पांजलि हास्पिटल में कोरोना का इलाज कराने वाले कई मरीजों के स्वजनों ने लिखित शिकायत की थी। मरीजों से पैसे हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरो फिजीशियन से परामर्श के लिए जाते थे और दिखाया जाता था एनेस्थेटिस्ट, साइकेट्रिस्ट और पैथोलाजिस्ट को। इस फर्जीवाड़े से कई रोगियों की असमय मौत हो गई थी।

एंबुलेंस चालकों की मिलीभगत से खेल

दूसरी लहर में अचानक मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 91 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों के इलाज की अनुमति दी थी। साथ ही इलाज की दरें भी निश्चित की गई थीं। निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। बावजूद इसके एंबुलेंस चालकों की मदद से आक्सीजन, आइसीयू व वेंटिलेटर के नाम पर मरीजों का दोहन किया गया। पूर्व में भी कई अस्पतालों के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई है।

जानसन ने सिंगल डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बड़ी कंपनी जानसन एंड जानसन ने भारत में अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जानसन की यह वैक्सीन एक डोज की है।

इससे पहले, सोमवार को कंपनी ने कहा था कि वह अपनी एकल डोज कोरोना वैक्सीन भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लेकर सरकार के साथ बातचीत चल रही है। जानसन एंड जानसन इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया, 'पांच अगस्त, 2021 को जानसन एंड जानसन प्रा. लि. ने अपनी सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत सरकार के यहां आवेदन किया है।' कंपनी ने कहा कि तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के सुरक्षा और प्रभाव के आंकड़ों के आधार पर इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई है।

देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और अहम मुकाम हासिल किया है। देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। इनमें 43.29 लाख डोज अकेले शुक्रवार को लगाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को जोरदार ताकत मिली है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना टीकाकरण पर भारत तेजी से आगे भाग रहा है। अब तक रिकार्ड 50 करोड़ डोज लगाई गईं।' वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कोरोना टीकाकरण में 50 करोड़ डोज के मील के पत्थर को पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 43,29,673 डोज लगाई गईं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पांच करोड़ और महाराष्ट्र में चार करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में 18-44 वर्ष आयु समूह के एक-एक करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को जोरदार गति मिली है। टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है।'

ऐसे बढ़ी रफ्तार

डोज (करोड़ में)	दिन
1-10	85
10-20	45
20-30	29
30-40	24
40-50	20

16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ

बंगाल में बकाया शुल्क नहीं मिलने पर कार्रवाई कर सकते हैं स्कूल

राज्य ब्यूरो कोलकाताः अभिभावकों को अगले तीन सप्ताह तक स्कूल की बकाया फीस का 50 फीसद देना होगा, अन्यथा स्कूल प्रशासन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिया है।

दरअसल, कोरोना काल के बावजूद निजी स्कूलों ने स्कूल फीस बढ़ा दी है। इस संबंध में अभिभावकों ने पिछले साल मामला दर्ज कराया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल फीस के 80 फीसद बकाया का निपटान करने का निर्देश दिया था। स्कूलों ने कोर्ट को बताया कि अभिभावकों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। बकाया फीस के कारण शिक्षकों को वेतन भुगतान करने में परेशानी हो रही है, जबकि आनलाइन क्लास संचालित हो रही हैं। न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि 80 फीसद बकाया फीस जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन पालन नहीं किया।

न्यूज गैलरी

उपराष्ट्रपति नायडू ने सुषमा स्वराज की सराहना की

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा को सदैव याद किया जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा का 2019 में 67 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। (प्रेट्र)

कोरोना नियम उल्लंघन के लिए मुंबई में बार पर छापेमारी

मुंबई : पुलिस ने मुंबई के मलाड में एक बार में छापेमारी कर कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में एसवी रोड पर गुरुवार रात 9:45 बजे के आसपास छापेमारी की गई। (प्रेट्र)

बेंगलुरु में नशीले पदार्थों के साथ चार पकड़े गए

बेंगलुरु : बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को एक विदेशी समेत चार लोगों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 15 किलो हशीश आयल, 10 किलो गांजा और नशीली गोलियां जब्त कीं। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। (एएनआइ)

मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने के लिए प्रदर्शन

मुंबई : महाराष्ट्र में भाजपा के कई नेताओं ने शुक्रवार को लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा पार्टी ने कहा है कि जिन आम नागरिकों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। (प्रेट्र)

कोर्ट की सुरक्षा में नजर आएंगे यूपीएसएसएफ के जवान

लखनऊ : उप्र की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने दिशा में शासन लगातार कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की लखनऊ बटालियन तैयार है, जबकि गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर बटालियन के गठन की प्रक्रिया जारी है। (राब्यू)

कई लड़कियों के मतांतरण की फिराक में था शफीक

जागरण संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ में अलीगंज नया हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में गिरफ्तार शफीक के कई महिलाओं और लड़कियों से संपर्क थे। पुलिस को उसके इंटरनेट मीडिया अकाउंट से कई लड़कियों और महिलाओं की फोटो मिली हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि वह महिलाओं और लड़कियों का मतांतरण कराने की फिराक में था। शफीक मूल रूप से दिल्ली के सलीमपुर ई-16 बी-के ब्लाक अखाड़ा का रहने वाला है।

शफीक की गिरफ्तारी के बाद एटीएस और खुफिया विभाग की टीम ने उससे घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। पड़ताल में यह भी पता चला कि धमकी भरा पत्र भेजने के बाद शफीक ने अपने मोबाइल फोन का डाटा भी डिलीट कर दिया था। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन का डाटा रिकवर होने पर ही पता चल सकेगा कि शफीक के और मंसूबे क्या थे। वह क्या करना चाहता था। किन-किन लोगों से जुड़ा था। उसके मोबाइल फोन में मिली महिलाओं और लड़कियों की फोटो किसकी हैं, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। वे कहां रहती हैं, उनकी पहचान क्या है।

कई मदरसों में भी रहा शफीक

एसीपी अलीगंज अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि शफीक दिल्ली, खदरा और सीतापुर में मदरसों में भी रहा है। वह धार्मिक कट्टरपंथी था। उसके पास से कई पुस्तकें भी मिली थीं।

'मुस्लिम युवक-युवतियों की गैर-मुस्लिमों से शादी गलत'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुस्लिम युवक-युवतियों की गैर-मुस्लिमों के साथ शादी को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने शरीयत के अनुसार गलत बताया है। बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम में निकाह के मामले में यह जरूरी है कि एक मुस्लिम युवती का निकाह मुस्लिम युवक से ही हो। इसी तरह, मुस्लिम युवक भी किसी गैर-मुस्लिम युवती से निकाह नहीं कर सकता। यदि, उसने किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर भी लिया है तो भी शरीयत के मुताबिक शादी अमान्य करार दी जाएगी।

बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान जारी कर कहा कि शिक्षा और नौकरी के दौरान पुरुषों और महिलाओं के आपस में मिलने-जुलने और धार्मिक शिक्षा से अनभिज्ञता के कारण दूसरे धर्मों में शादियों के कई मामले सामने आए हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि मुस्लिम युवतियां गैर-मुस्लिमों के साथ चली गईं और बाद में कठिन परिस्थितियों से गुजरीं। यहां तक कि उनको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। इसके मद्देनजर जनसभाओं में उलमा अधिक से अधिक इस विषय पर संबोधन करें और मुस्लिम युवक-युवतियों को धार्मिक व सामाजिक नुकसान से आगाह करें।

बरेली में मतांतरण के लिए छात्रा का अपहरण

जासं बरेली : दूसरे संप्रदाय की छात्रा का मतांतरण कराने के लिए बिलाल कुरैशी ने गहरी साजिश की। राह चलते छात्रा का वीडियो बनाया। इसके बाद क्लिप में छेड़खानी कर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। दहशत में आई छात्रा ने कालेज जाना बंद कर दिया मगर, तीन अगस्त को बाजार गई तो उसका अपहरण कर लिया गया।

मुस्लिम बने दो युवकों की हिंदू धर्म में वापसी

जासं, मुजफ्फरनगर : मतांतरण कर सुशील जैन से अब्दुल समद व सौरभ गुप्ता से मोहम्मद अरशद बने दो युवकों ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी की। शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराई। मुंडन के बाद दोनों को गंगाजल से नहलाकर पवित्र किया गया। हवन-यज्ञ में आहुति देकर घर वापसी का संकल्प लिया।

'क्या अंतर धार्मिक विवाह करने वाले को पहले जेल जाना पड़ेगा'

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा कि क्या अंतर धार्मिक विवाह करने वाले को पहले जेल जाना पड़ेगा। राज्य के नए लव जिहाद कानून को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की 17 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। बता दें कि राज्य में नया लव जिहाद कानून लागू होने के बाद इस तरह के चार-पांच मामले दर्ज हो चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ एवं न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की पीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से लाया गया गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 संविधान के खिलाफ है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। देश का कोई भी वयस्क अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन गुजरात सरकार के धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के बाद अंतर धार्मिक विवाह करने वाले युवक को पहले जेल जाना पड़ेगा। अंतर धार्मिक विवाह को लेकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। नए कानून के बाद अंतर धार्मिक विवाह अपने आप में एक अपराध हो गया है।

गुजरात सरकार के लव जिहाद कानून को जमीयत उलेमा ए हिंद और माइनारिटी कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफीस ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कानून में अंतर धार्मिक विवाह को अनैतिक बताया गया है जो संविधान के तहत व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता को बाधित करता है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भेजा और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि गुजरात विधानसभा ने अप्रैल 2021 में यह कानून पारित किया था जिसे राज्यपाल ने मई 2021 में मंजूरी दी। कानून के तहत आरोपित को तीन से पांच साल की सजा तथा दो लाख तक के जुर्माने का प्रविधान है।

सात साल दबाए रखा अदालत का आदेश, अब दर्ज हुआ केस

रमन मिश्र, गोंडा

पुलिस की कार्यप्रणाली का एक उदाहरण देखिए, सात साल में दस एसओ बदले, लेकिन एफआइआर दर्ज करने का एक अदालती आदेश थाने की फाइलों में दफन रहा। थक हारकर महिला फिर अदालत पहुंची। सख्ती हुई तो अब पुलिस ने सात साल बाद मुकदमा दर्ज किया है।

मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है। सितंबर, 2014 में कोतवाली नगर के एक गांव की महिला ने न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय के यहां प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका विवाह 12 वर्ष पूर्व एक गांव निवासी कुमारे के साथ हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही पति उसे प्रताड़ित करने लगा। मारपीट कर जला देने की धमकी दी। इसके बाद उसका पति राजकोट चला गया। इसी क्रम में 21 जुलाई, 2014 को उसके जेठ ने दुष्कर्म का प्रयास करने के साथ ही मारपीट की। अगले दिन 22 जुलाई को जेठ ननके ने बच्चों के साथ उसे भगा दिया। दोबारा आने पर जलाने की धमकी दी। इस पर न्यायालय ने मुकदमा करके तीन दिवस के भीतर रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन न्यायालय के इस आदेश को पुलिस ने फाइलों में दबा दिया। इस बीच लगातार थाने के चक्कर काटने के बाद पारिवारिक समस्याओं के चलते महिला थककर बैठ गई। सात साल बाद महिला ने दोबारा न्यायालय की शरण ली।

बहन की हत्या के आरोप से आठ साल बाद मिली मुक्ति

जासं, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फनगर में आठ साल पहले गर्दन काटकर की गई युवती की हत्या के आरोप में जेल में बंद उसके भाई को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपित को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आनर किलिंग मानते हुए विवेचना की थी पर साबित नहीं कर सकी।

राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, मुंबईः राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ की। पूछताछ से पहले अभिनेत्री ने दावा किया कि वह एक गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने आई हैं। पुलिस को सौंपने के लिए वह कुछ दस्तावेज भी लेकर पहुंची थीं।

मुंबई पुलिस ने करीब दो सप्ताह पहले ही शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए समन भेजा था। गिरफ्तारी की आशंका देखते हुए उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे शर्लिन दस्तावेजों का पुलिंदा लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचीं। माना जा रहा है कि राज कुंद्रा पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछताछ की गई है। शर्लिन ने राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राज की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा था कि राज के साथ उनकी एक बिजनेस डीलिंग को लेकर बात हुई थी, लेकिन यह हाटशाट एप के लिए नहीं थी।

एफएमजीई में शामिल उम्मीदवारों को एक अंक देने के फैसले पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ एनबीई की चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट ने 17 सितंबर तक एकल पीठ के फैसले को लागू करने पर लगाई रोक

दिसंबर 2020 में हुई विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) में पूछे गए गलत सवाल पर एक नंबर देने के एकल पीठ के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई दी है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के फैसले को लागू करने पर 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।

एनबीई की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए तथ्यों को पेश किया। पीठ ने मनिंदर सिंह की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने पांच जुलाई को उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों ने गलत तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया और उन्हें एक अतिरिक्त अंक से सम्मानित किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा था कि जिस उम्मीदवार को 150 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण माना जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि एक अतिरिक्त अंक केवल उन उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा जिन्होंने एफएमजीई बोर्ड की तरफ से सही विकल्प के रूप में दिए गए विकल्प के अलावा कोई उत्तर दिया है। पीठ ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने एफएमजीई की तरफ से स्वीकार किए गए उत्तर को सही के रूप में चिह्नित किया था, उन्हें पहले ही अंक दिया जा चुका है और अब उन्हें गलत या विवादित प्रश्न के लिए दोबारा अंक नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न गलत था।

बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपित अंकुर ने फिर लगाई जमानत याचिका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : टीकरी बार्डर पर कोरोना से मरने वाली बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित अंकुर ने दोबारा अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे एस पुरी ने सरकार को 19 अगस्त तक इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। जून माह में भी अंकुर ने अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बेंच के सामने हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक संभरवाल ने कहा कि आरोपित पर गंभीर आरोप है, इस लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अगर इसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो जांच प्रभावित हो सकती है। अंकुर की पहली याचिका पर बहादुरगढ़ डीएसपी पवन कुमार का हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है।

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 7 अगस्त, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल, नए रिकार्ड पर

मुंबई: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जून को खत्म सप्ताह के दौरान 9.427 अरब डालर उछलकर 620.576 अरब डालर पर जा पहुंचा। इससे पहले के सप्ताह में यह 1.581 अरब डालर गिरकर 611.149 अरब डालर रहा था। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) 8.596 अरब डालर बढ़कर 576.224 अरब डालर पर पहुंच गई। (प्रेट्र)

कारोबार की दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। ग्राहक कंपनियों पर लोगों और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं।
– आनंद महिंद्रा, चेयरमैन महिंद्रा एंड महिंद्रा

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
54,277.72	16,238.20	₹ 46,570	₹ 65,514	₹ 74.15	$ 71.69
▼ 215.12	▼ 56.40	▼ ₹ 283	▼ ₹ 661	▼ ₹ 0.02	

पीएम ने दिए लोकल को ग्लोबल बनाने के चार मंत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ोतरी के लिए सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। फिर, लाजिस्टिक्स सुविधा बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों को भूमिका निभानी होगी। तीसरे मंत्र के रूप में मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को कंधे से कंधा मिलाकर निर्यातकों के साथ काम करना होगा, तभी निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी हो पाएगी। प्रधानमंत्री का चौथा मंत्र था - देसी उत्पादों के लिए बड़े से बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार खोजें। इन सबकी बदौलत ही लोकल का स्वरूप ग्लोबल होगा। प्रधानमंत्री ने इस महीने आजादी के 75वें महोत्सव पर भविष्य के विकास का रोडमैप तैयार करने का भी आह्वान किया।

नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, दुनियाभर में इंडियन मिशन के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधियों एवं उद्योग संगठन के साथ संवाद किया • एएनआइ

वस्तु निर्यात का 400 अरब डालर का रिकार्ड लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को 20 से अधिक विभागों, विभिन्न मंत्रालयों, दुनियाभर में इंडियन मिशन के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधियों एवं उद्योग संगठन के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि वायरस संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है और टीकाकरण की गति बढ़ रही है। दुनिया में भी रिकवरी हो रही है और यह निर्यात बढ़ोतरी के लिए बेहतर समय है। निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उम्दा तकनीक, इनोवेशन और आरएंडडी पर विशेष जोर देना होगा।

इन उपायों से बढ़ेगा निर्यात
- मैन्यूफैक्चरिंग में इजाफा, लाजिस्टिक्स लागत कम करना
- सरकार की भागीदारी और भारतीय उत्पाद के लिए नए बाजार की खोज
- दुनियाभर में भारतीय राजनयिक निर्यात बढ़ाने में करेंगे योगदान
- खनन, कोयला, रेलवे, रक्षा जैसे नए क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी भारत अपना आधा निर्यात सिर्फ चार देशों में करता है और निर्यात में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उत्पाद, जेम्स ज्वैलरी जैसी कुछ वस्तुओं की अधिक भागीदारी होती है। ऐसे में निर्यात लायक उत्पाद बढ़ाने होंगे और नए बाजार भी तलाशने पड़ेंगे। इस काम में विभिन्न देशों में स्थित इंडियन मिशन मदद करेंगे। विदेश में भारतीयों के समूह के साथ संबंध बनाकर भी भारतीय वस्तुओं को विभिन्न देशों में प्रचलित किया जा सकता है। खनन, कोयला, रक्षा और रेलवे जैसे सेक्टर से निर्यात को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय वस्तुओं को 75 देशों में भेजने का संकल्प लेना होगा।

निर्यात प्रोत्साहन का दिख रहा असर : प्रधानमंत्री ने कहा कि सात वर्ष पहले भारत आठ अरब डालर मूल्य के मोबाइल फोन का आयात करता था जो अब घटकर सिर्फ दो अरब डालर रह गया है। वहीं, उस समय देश महज 30 करोड़ डालर के मोबाइल फोन का निर्यात करता था जो बढ़कर तीन अरब डालर से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने तकनीक जांच की सुविधा बहाल करने से मधु के निर्यात में होने वाली बढ़ोतरी का भी उदाहरण दिया। अभी भारत 9.7 करोड़ डालर के मधु का निर्यात करता है।

लक्ष्य पाने को चाहिए 33.68 अरब डालर मासिक निर्यात

राजीव कुमार • नई दिल्ली

चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात का 400 अरब डालर का रिकार्ड मिशन हासिल करने को अगले आठ महीने तक मासिक 33.68 अरब डालर का निर्यात करना होगा। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार माह में प्रतिमाह औसतन 32.64 अरब डालर निर्यात किया गया। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के निर्यात में सबसे अधिक हिस्सेदारी चीन की है। पिछले दस वर्षों से वस्तुओं के निर्यात में 100 अरब डालर की भी वृद्धि नहीं हो सकी है। 2010-11 में निर्यात 246 अरब डालर था जो वित्त वर्ष 2018-19 में 330 अरब डालर के स्तर पर पहुंच पाया। 2011-12 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात 300 अरब डालर के स्तर को पार किया था और तब वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2020 तक इस निर्यात को 500 अरब डालर तक ले जाने का रोडमैप भी तैयार किया था।

सुप्रीम कोर्ट का अमेजन के पक्ष में फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ खड़ी अमेजन इंक के पक्ष में एक फैसला दिया है। इस मामले में सिंगापुर आपात मध्यस्थ के फैसले की वैधता पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ के विलय सौदे पर रोक लगाने का सिंगापुर के आपात न्यायाधिकरण का फैसला भारतीय कानूनों के तहत वैध एवं बाध्यकारी है। जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने इस सवाल की व्यापकता पर फैसला दिया कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के आपात मध्यस्थ (ईए) का फैसला भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत लागू करने योग्य है या नहीं।

कोर्ट ने कहा - फ्यूचर-रिलायंस सौदे में सिंगापुर के आपात न्यायाधिकरण का फैसला भारतीय कानूनों के तहत वैध एवं बाध्यकारी

अमेजन डाट काम एनवी इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी और एफआरएल के बीच इस सौदे को लेकर विवाद था। अमेरिका स्थित अमेजन ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि ईए का फैसला वैध एवं लागू करने योग्य बताया जाए। एफआरएल का तर्क था कि ईए मध्यस्थ भारतीय कानून के तहत नहीं है, क्योंकि इस शब्द का यहां कानून में कोई उल्लेख नहीं है।

कोर्ट के फैसले पर दोनों कंपनियों ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन गोपनीयता की शर्त पर एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि फ्यूचर रिटेल द्वारा आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय, एफआरएल और अमेजन के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित नहीं है।

टाइटन ने फ्लिपकार्ट के साथ लांच किया 'एपिक बाई सोनाटा'

नई दिल्ली, (वि.) : टाइटन कंपनी लिमिटेड की ओर से देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले घड़ी ब्रांड सोनाटा ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी में किफायती और फैशनेबल घड़ियों की सीरीज लांच की है। 'एपिक बाई सोनाटा' के तहत लांच इस सीरीज की घड़ियां आनलाइन रिटेलिंग दिग्गज फ्लिपकार्ट के प्लेटफार्म से खरीदी जा सकती हैं। कंपनी ने कहा कि देशभर में फ्लिपकार्ट के 35 करोड़ पंजीकृत ग्राहकों तक एपिक बाई सोनाटा की पहुंच होगी। टाइटन कंपनी लिमिटेड की सीईओ (वाचेज एंड वियरेबल्स) सुपर्णा मित्रा ने कहा कि सोनाटा पर देश के करोड़ों ग्राहकों का भरोसा है। सोनाटा की इस यात्रा को एपिक के साथ हम एक नए मुकाम पर पहुंचाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फैशन के साथ मूल्य के प्रति सजग ग्राहकों के लिए यह सीरीज बेहद पसंदीदा साबित होगी। उन्होंने कहा, फ्लिपकार्ट बेहद भरोसेमंद ई-कामर्स प्लेटफार्म है।

दो वर्षों में कर्ज करीब सवा दो फीसद सस्ता : दास

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा - सस्ते कर्ज का बाजारों पर दिखने लगा सकारात्मक असर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पिछले दो वर्षों के दौरान ब्याज दरों में की गई कटौती का बाजारों पर सकारात्मक असर दिख रहा है। बैंक ने फरवरी, 2019 से ब्याज दरों में कटौती शुरू की थी। तब से अब तक बैंकों द्वारा दिया गया नया कर्ज 2.17 फीसद और पुराना कर्ज 1.70 फीसद सस्ता हो चुका है। इस दौरान आरबीआइ ने रेपो रेट में ढाई फीसद कटौती की है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में पिछले वर्ष मार्च के बाद से बैंकों ने नए लोन की ब्याज दर में 1.46 फीसद और पुराने कर्ज में 1.01 फीसद तक की कटौती की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आरबीआइ ने ब्याज दरों में जो कटौती की, बैंकों ने उसका एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाया है। यही वजह है इस वक्त कई कर्ज की ब्याज दरें सर्वकालिक निम्न स्तर पर हैं।

अपनी नवीनतम समीक्षा बैठक में आरबीआइ ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। समीक्षा बैठक के फैसलों की शुक्रवार को जानकारी देते हुए दास ने कहा कि बाजार की जरूरत के मुताबिक केंद्रीय बैंक का तरलता उपलब्ध कराने का काम जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआइ को कई मोर्चों पर काम और कई जटिल मुद्दों का एक साथ निदान करना होता है। ऐसे में ब्याज दरों को हमेशा एक दिशा की ओर नहीं रखा जा सकता है।

बैंकों को प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के दायरे से बाहर निकालने के बारे में दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों की स्थितियों की निगरानी कर रहा है। आरबीआइ को जब लगेगा कि अमुक बैंक को पीसीए के दायरे से बाहर निकालना है तो वह उचित समय पर इसका फैसला करेगा। वर्तमान में इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी), यूको बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को आरबीआइ ने पीसीए के दायरे में रखा हुआ है। उन्होंने कहा, एचडीएफसी बैंक व मास्टरकार्ड पर भी जो कार्रवाई की गई, उसका मुख्य मकसद यही था कि वे नियामकीय दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें। जब भी नियामकीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है, तो आरबीआइ का यह दायित्व है कि नियामक होने के नाते वह अनुपालन सुनिश्चित कराए। दास ने रेट्रो टैक्स खत्म करने के सरकार के फैसलों की भी जमकर प्रशंसा की। पूर्व में राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों का सचिव रहने के नाते मैं कह सकता हूं कि रेट्रो टैक्स का काफी वक्त से लंबित मुद्दों में एक रहा है। अगर सरकार इसे खत्म कर देती है तो यह उद्योग जगत के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार ने रेट्रो टैक्स (बाद में जारी नियम के तहत किसी कंपनी से पिछले समय के आधार पर टैक्स वसूलना) को खत्म करने को पिछले दिनों लोस में विधेयक पेश किया है।

विकास दर को तेज करने में मिलेगी मदद : उद्योग जगत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उद्योग जगत और आर्थिक विशेषज्ञों ने ब्याज दरों को स्थिर रखने के आरबीआइ के फैसले को मजबूत व विकास दर को तेज करने वाला बताया है। उद्योग चेंबर एसोचैम के महासचिव दीपक सूद का कहना है कि महंगाई की स्थिति निश्चित तौर पर केंद्रीय बैंक के उच्चतम लक्ष्य के करीब है। लेकिन रिकवरी की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला एकदम सही है। दूसरी तिमाही के बाद आपूर्ति पक्ष सुधरने और मानसून का असर आने की वजह से महंगाई में और सुधार होगा। पीएचडी चेंबर आफ कामर्स ने कहा है कि आरबीआइ की घोषणा से उद्योग जगत व निवेशक समुदाय में भरोसा बढ़ेगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

पंजाब नैशनल बैंक के एमडी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ब्याज दरों का कम होना अनिवार्य है और एमपीसी का कदम उसी दिशा में उठाया गया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के एमडी उमेश रेवांकर ने कहा है कि आरबीआइ गवर्नर ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वो भी इकोनामी में रिकवरी के लिए अपना पूरा योगदान और विकास दर को प्राथमिकता दें। कोटक म्यूचुअल फंड के सीआइओ लक्ष्मी अय्यर का आकलन है कि आरबीआइ के फैसले से विकास दर को बेहतर करने में मदद मिलेगी लेकिन एमपीसी ने यह भी संकेत दे दिया है कि नीतिगत बदलाव की शुरुआत जल्द होने वाली है। एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनोमिस्ट अभीक बरुआ ने कहा है कि संकेत साफ है कि अभी दो तिमाहियों तक कर्ज की दरें और जमा की दरें मौजूदा स्तर पर ही रहेंगी।

कोरोना की वजह से माइक्रो एटीएम कारोबार को लगे पंख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की वजह से पिछले एक वर्ष में माइक्रो एटीएम की संख्या 50 फीसद से अधिक बढ़ी है। आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष जून में देशभर में माइक्रो एटीएम की संख्या 2,95,750 थी जो इस वर्ष जून में 4,53,855 हो गई। फाइनेंशियल टेक्नोलाजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि परिचालन लागत काफी कम होने से माइक्रो एटीएम काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी बैंक या वित्तीय संस्थान पर नहीं होती है।

50 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई एक वर्ष में

देश के कई हिस्सों में माइक्रो एटीएम लगाने वाली कंपनी रैपिपे फिनटेक के नेशनल बिजनेस हेड अंकित लोहाटी ने बताया कि माइक्रो एटीएम से पिछले महीने 24,000 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया और यह तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाके या छोटे शहरों के साथ बड़े शहरों में भी माइक्रो एटीएम का चलन बढ़ रहा है। सामान्य एटीएम के रखरखाव के लिए बिजली, एसी, गार्ड जैसे खर्च उठाने पड़ते हैं। लेकिन माइक्रो एटीएम के लिए इस प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है।

माइक्रो एटीएम भी सामान्य एटीएम की तरह काम करता है। यह एक छोटी सी मशीन होती है जिसकी अधिकतम कीमत 2,500-3,000 होती है। माइक्रो एटीएम से नकदी नहीं निकलती है। इस मशीन में कार्ड लगाकर जितनी रकम डाली जाती है, उतनी रकम माइक्रो एटीएम चलाने वाले दुकानदार नकद में दे देते हैं। माइक्रो एटीएम को संचालित करने वाले दुकानदार को बदले में कुछ कमीशन मिलते हैं। माइक्रो एटीएम से एक बार में अधिकतम 10,000 निकाल सकते हैं। फिनटेक विशेषज्ञों के मुताबिक अमूमन गांव में किराना दुकान या कोई अन्य दुकान चलाने वाले ही इसका संचालन करते हैं और उन्हें माइक्रो एटीएम चलाने से कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाती है।

राष्ट्रीय फलक

अज्ञात नंबर से आया फोन, रिसीव करने के बाद खाते से गायब हुए 84 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कोलकाता में एक बार फिर अभिनव तरीके से बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात नंबर से फोन रिसीव करने के बाद यहां के एक व्यवसायी के बैंक खाते से जालसाजों ने 84 लाख रुपये उड़ा लिए। दिलचस्प बात यह है कि व्यवसायी ने उन लोगों से बैंक संबंधी कोई भी जानकारी साझा नहीं की थी। व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक कोलकाता से सटे साल्टलेक में व्यवसायी शिवम अरोड़ा को जालसाजों ने मैसेज के जरिये ई-सिम इस्तेमाल करने का आफर दिया था। उन्होंने दावा किया कि 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच उनके मोबाइल फोन पर करीब 500 मैसेज आए। उन्हें हर मैसेज में ई-सिम कार्ड इस्तेमाल करने की पेशकश की गई थी। एक ही अनुरोध के साथ उनके पास फोन आते रहे। फिर एक काल रिसीव करने के बाद अचानक उनके मोबाइल फोन के सिग्नल दिखना बंद हो गया। गत मंगलवार को व्यवसायी बैंक गए तो पता चला कि उनके खाते से करीब 84 लाख रुपये गायब हो गए हैं। उन्होंने उसी दिन ही इसकी शिकायत कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार व्यवसायी ने जालसाजों को कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन फोन काल के दौरान उन्होंने उनके सिम का क्लोन बना लिया। फिर व्यवसायी का फोन निष्क्रिय कर दिया ताकि बैंक से कोई संदेश न आए। शायद जालसाजों के पास बैंक खाते की डिटेल पहले ही थी। इसके बाद खाते से पैसे निकाल लिए गए। कोलकाता की खुफिया पुलिस की बैंक धोखाधड़ी दमन शाखा ने इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला है। घटना की जांच की जा रही है।

धोखाधड़ी
- फोन काल के दौरान जालसाजों ने सिम का बना लिया क्लोन
- पीड़ित के फोन को कर दिया निष्क्रिय ताकि बैंक से नहीं आए कोई संदेश

एक्सपर्ट व्यू

फोन काल के दौरान मुमकिन है मूल सिम का क्लोन बनाना

कोलकाता के जाने-माने साइबर जानकार सम्याजीत मुखर्जी का कहना है कि जालसाज फोन काल के दौरान किसी के मूल सिम का क्लोन बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि जालसाजों के पास खुद के विकसित किए हुए अत्याधुनिक साफ्टवेयर तथा उपकरण रहते हैं, जिसके जरिये वे सिम का क्लोन बना लेते हैं। सामान्यत इसके लिए पूरा एक समूह काम करता है। एक जालसाज व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए फोन पर उलझाए रखता है, तभी दूसरा उसी नंबर पर फोन करके अत्याधुनिक टूल्स के जरिये डाटा को बाईपास करता रहता है। इसी दौरान तीसरा शख्स सिम का क्लोन बना लेता है तथा चौथा शख्स फोन को निष्क्रिय कर देता है, ताकि कोई भी संदेश संबंधित व्यक्ति के नंबर पर ना जाए।

जयपुर में धमाके के साथ ईयरफोन फटा, युवक की मौत

जासं, जयपुर: राजस्थान में जयपुर जिले के उदयपुरिया गांव में शुक्रवार को कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन फटने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा दोपहर दो बजे हुआ। जानकारी के अनुसार जयपुर-सीकर हाईवे पर स्थित गांव में 28 वर्षीय राकेश नागर कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन डिवाइस लगाकर किसी से बात कर रहा था। अचानक ब्लूटूथ डिवाइस कानों में फट गई। इससे नागर के कान से खून बहने लगा। तेज धमके की आवाज सुनकर स्वजन नागर के पास पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद स्वजन नागर को पास के ही विनायक अस्पताल लेकर गए जहां, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सक डा. एलएन रूंडल ने बताया कि संभवतः मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई हो।

ब्याज दरों का हो सकता है प्रतिकूल असर

प्रथम पृष्ठ से आगे

डा. दास ने कहा भी कि, 'अगर ब्याज दरों का कोई फैसला धीरे धीरे हो रही रिकवरी को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। रिकवरी को लेकर असमंजसता है और सभी पक्षों को इसमें मदद करने की जरूरत है। आरबीआइ महसूस करता है कि ग्रोथ को अभी ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आरबीआइ बेहद सतर्क है।''

9.5 फीसद विकास दर का लक्ष्य: महंगाई की तरह ही पूरे साल विकास दर में भी भारी उतार चढ़ाव की संभावना है। आरबीआइ गवर्नर के मुताबिक, इस साल विकास दर अप्रैल-जून की तिमाही में 21.4 फीसद, जुलाई-सितंबर की तिमाही में 7.3 फीसद, अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 6.3 फीसद और अंतिम जनवरी-मार्च की तिमाही में 6.1 फीसद रहेगी। पूरे साल के लिए विकास दर का लक्ष्य 9.5 फीसद ही रहने दिया गया है, बशर्ते कि कोरोना की तीसरी लहर और वैश्विक हालात से उम्मीदों पर पानी नहीं फिरे। अभी तक तो घरेलू मांग में कमी के बावजूद सरकार की तरफ से खर्चे को बढ़ाने और विदेशों से भारी मांग निकलने से स्थिति सुधरती दिख रही है।

सहारनपुर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे को मार डाला

सहारनपुर, जासं: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पाडली ग्रंट गांव में शुक्रवार सुबह 12 वर्षीय मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद शादाब आम के बाग में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान करीब 20 कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। बाकी बच्चे शोर मचाते हुए भाग गए, लेकिन कुत्तों ने आमिर पर हमला कर नोच डाला।

खेल जागरण

राहुल और जडेजा के दम पर भारत ने ली बढ़त

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और आलराउंडर रवींद्र जडेजा के अर्धशतकों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ नाटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 95 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। राहुल ने 214 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 84 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 86 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। इस तरह भारतीय टीम की पहली पारी में 278 रन पर खत्म हुई। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन ने 85 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि अनुभवी जेम्स एंडरसन ने 54 रन देकर चार विकेट लिए। पहली पारी में 183 रन बनाने वाली इंग्लिश टीम ने जवाब में जब बिना नुकसान के 25 रन बनाए थे तो बारिश आ गई और उसके बाद दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। तब रोरी बर्न्स 11 और डोम सिब्ले नौ रन बनाकर क्रीज पर थे।

मैच के दौरान रवींद्र जडेजा और लोकेश राहुल • रायटर

भारत ने सुबह चार विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू किया और बारिश से प्रभावित पहले सत्र में रिषभ पंत (25) का विकेट खोकर 66 रन जोड़े। पंत को रोबिनसन ने चलता किया। बारिश के कारण पहले 95 मिनट में केवल 11 गेंदें ही डाली जा सकीं। राहुल ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जडेजा अपने अंदाज में खेले। राहुल पूरी मजबूती के साथ शतक की तरफ बढ़ रहे थे। एंडरसन पर लगाया गया उनका किताबी कवर ड्राइव दर्शनीय था, लेकिन इसी ओवर में कोण लेती गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर को कैच दे बैठे।

सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

गेंदबाज	टीम	टेस्ट	विकेट
मुथैया मुरलीधरन	श्रीलंका	133	800
शेन वार्न	आस्ट्रेलिया	145	708
जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड	163	621
अनिल कुंबले	भारत	132	619

2000 टेस्ट रन पूरे किए रवींद्र जडेजा ने। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के 21वें और भारत के पांचवें खिलाड़ी बने

एंडरसन का यह टेस्ट मैचों में 620वां विकेट और इस तरह वह अनिल कुंबले को पीछे छोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर काबिज हो गए। अपने बल्लेबाजी कौशल के कारण टीम में शामिल किए शार्दुल ठाकुर (0) को भी एंडरसन ने विकेट के पीछे कैच कराया। इसी गेंदबाज के अगले ओवर में जडेजा ने पहले चौका और फिर लांग लेग पर छक्का लगाया। उन्होंने रोबिनसन की गेंद चार रन के लिए भेजकर अपना 16वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। जडेजा ने हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद हवा में लहराकर मिड आफ पर कैच दे दिया।

जसप्रीत बुमराह (28), मुहम्मद शमी (13) और मुहम्मद सिराज (नाबाद 7) ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को राहत नहीं लेने दी। बुमराह ने सैम कुर्रन की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का लगाया। इंग्लैंड ने तुरंत ही नई गेंद ली, लेकिन तब भी बुमराह और सिराज आखिरी विकेट के लिए 33 रन जोड़ने में सफल रहे।

इटली ने 74 वर्षों का सूखा किया खत्म

टोक्यो ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, प्रेट्र: 1948 के बाद से इटली के एथलीट कभी भी ओलिंपिक पुरुष 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ के पोडियम पर खड़े नहीं हुए थे। दूसरी तरफ 2008 के बाद जमैका कभी भी ओलिंपिक पुरुष 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में पदक के बगैर नहीं रहा था।

इटली के चार एथलीटों की टीम में लोरेंजो पट्टा, एसियोसा देसालु, फिलिपो टोर्टू के साथ नए ओलिंपिक 100 मीटर चैंपियन मर्सेल जैकोब्स भी शामिल थे। इन चारों ने इतिहास रचते हुए 37.50 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकार्ड समय के साथ ग्रेट ब्रिटेन (37.51 सेकेंड) को स्वर्ण पदक के लिए 0.01 सेकेंड से पराजित किया। कनाडा (37.70) इटली से 0.20 सेकेंड पीछे तीसरे स्थान में रहा। इस तरह इटली ने इस स्पर्धा का 74 साल से चला आ रहा अपना सूखा खत्म किया है और 1948 ओलिंपिक में इटली की टीम ने पुरुष 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ का कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा जमैका 13 सालों बाद इस स्पर्धा में उसेन बोल्ट के बिना पोडियम पर जगह नहीं बना पाया और पांचवें स्थान पर रहा।

0.02 प्रतिशत ही कोरोना का खतरा : अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) के अध्यक्ष थामस बाक का मानना है कि जापान में जारी आपातकाल के बीच टोक्यो ओलिंपिक का सफल आयोजन उम्मीदों पर खरा उतरा है। उन्होंने आंकड़े प्रदर्शित करते हुए बताया कि इन खेलों में सिर्फ 0.02 प्रतिशत ही कोविड-19 के संक्रमित मामले आए हैं, जो की एक दिलचस्प आकड़ा है।

जमैका की महिलाओं को चार गुणा 100 मीटर रिले का स्वर्ण

ओलिंपिक में महिला चार गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में जमैका की टीम ने अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन को पराजित करते हुए खिताब जीता। जमैका की ब्रियाना विलियम्स, ऐलेन थांपसन हेराहो, शेली एन फ्रेजर प्राइस व शेरिका जैक्सन ने नया राष्ट्रीय रिकार्ड (41.02 सेकेंड) बनाते हुए अमेरिका को पछाड़ा। टीम युएसए की जेवियन ओलिवर, तेहना डेनियल, जेना प्रंदिनी व गैब्रिएल थामस ने अपना सर्वश्रेष्ठ समय (41.45 सेकेंड) निकालते हुए रजत जीता। कांस्य पदक ग्रेट ब्रिटेन की आशा फिलिप, इमानी लैंसिकोट, दीना आशेर स्मिथ और डेरिल नीता (41.88 सेकेंड) के नाम रहा। इस तरह पहले ही टोक्यो ओलिंपिक में दो स्वर्ण पदक जीत चुकी ऐलेन थांपसन हेराहो ने अपने करियर का पांचवां स्वर्ण पदक हासिल किया।

तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने किया बेहतर प्रदर्शन

जासं, सोनीपत : साई सेंटर में दो से पांच अगस्त तक चले ट्रायल के दौरान अमेरिका में होने वाली सीनियर विश्व चैंपियनशिप के टीम का चयन किया गया। ट्रायल में देशभर के करीब 70 तीरंदाजों ने भाग लिया। इसमें दिल्ली के अभिषेक वर्मा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 720 में 714 अंक हासिल किए। हालांकि दावा किया गया कि अभिषेक ने कुल 1440 में से 1425 का स्कोर कर विश्व रिकार्ड बनाया। मौजूदा विश्व रिकार्ड का स्कोर 1422 है। अभिषेक के रिकार्ड पर भारतीय तीरंदाजी संघ के सहायक सचिव गुंजन अबरोल ने बताया कि जब तक ट्रायल या प्रतियोगिता को पंजीकृत नहीं कराया गया हो, तब तक नया रिकार्ड मान्य नहीं होता। अभिषेक के बाद हरियाणा के ऋषभ यादव ने 709, राजस्थान के रजत चौहान, दिल्ली के अमन सैनी और सर्विसेज के एमआर भारद्वाज ने 706, एएआइ के सुखविंद्र सिंह ने 705 अंक हासिल किए।

सत्कर्म कठिन राह को भी सरल बना देते हैं

पीछे लौटता चीन

पूर्वी लद्दाख में गोगरा इलाके से चीनी सेना का पीछा हटना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि इस सैन्य गतिरोध का समाधान दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हो सका। कायदे से इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन जाने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी आमने-सामने खड़ी सेनाओं को अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो चीन के अड़ियल रवैये के कारण। चीन खुद की ओर से पैदा किए गए सैन्य गतिरोध को सुलझाने के मामले में किस तरह अड़ियल रवैया अपनाता है और दूसरे पक्ष को थकाने की रणनीति पर चलता है, इसका एक प्रमाण यह है कि अभी हाट स्प्रिंग और देपसांग इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे लौटाने के लिए तैयार नहीं। यह अच्छा है कि भारत चीन की थकाने वाली रणनीति को समझ गया है और वह भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। शायद यही कारण है कि चीन एक के बाद एक इलाकों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन जब तक पैंगोंग और गोगरा की तरह से बाकी इलाकों से चीन अपनी सेना को पीछे नहीं लौटाता, तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

भारत को अपनी यह बात बार-बार दोहराते रहना चाहिए कि जब तक सीमा पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाती, तब तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं आ सकता। भारत को केवल सैन्य गतिरोध वाले शेष इलाकों से ही सेनाओं की वापसी पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी रेखांकित करना चाहिए कि संबंधों में सुधार के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन सीमा विवाद को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि सीमा विवाद को लेकर बीते दो दशक से भी अधिक समय से बातचीत हो रही है, लेकिन मामला जहां का तहां है। इससे यही पता चलता है कि चीन सीमा पर छेड़छाड़ करने के इरादे से ही सीमा विवाद को हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए जरूरी केवल यह नहीं है कि सीमा पर उसकी सेना के अतिक्रमणकारी रुख पर सख्त रवैया अपनाया जाए, बल्कि यह भी है कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयासों को जारी रखा जाए। चूंकि इस दिशा में वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी अपेक्षित थी, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है? यह ठीक नहीं कि चीनी वस्तुओं का आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

खिलाड़ियों पर धनवर्षा

हरियाणा सरकार ओलिंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ियों पर दिल खोलकर खर्च कर रही है और उन्हें सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण पद देने की घोषणा कर रही है। निश्चित रूप से इससे नवोदित खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे। वैसे हरियाणा में जो भी सरकारें आईं, सबने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अब मनोहर सरकार उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मनोहर सरकार के कार्यकाल में यह एक और अच्छी बात हुई कि खिलाड़ियों को जूनियर स्तर पर ही तराशने का काम हो रहा है। यह भी विचारणीय है कि ओलिंपिक में पदक जीतने के बाद तो खिलाडियों को बहुत कुछ मिलने लगता था, लेकिन वहां जाने से पहले उनके सामने बहुत दुश्वारियां आती थीं। प्रदेश सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए उनका ओलिंपिक में चयन होने के बाद पांच लाख रुपये की राशि प्रदान करने की व्यवस्था की। यही कारण है कि ओलिंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। यद्यपि हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की परंपरा भले ही पूर्ववर्ती सरकारों के समय से हो,

> हरियाणा में खेल-संस्कृति विकसित हो रही है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और खेलों की दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा

लेकिन मनोहर सरकार ने एक अच्छा काम यह किया है कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल के दौरान खेल मंत्री रहे अनिल विज ने इसका आरंभ किया और दूसरे कार्यकाल के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इसे और आगे ले जाने का काम किया। संदीप सिंह स्वयं हाकी के स्टार खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए वह नवोदित खिलाड़ियों के साथ आने वाली समस्याओं को जानते हैं। उन्होंने उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सरकार को प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की प्रतिभा का आकलन कर तदनुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा आठ से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों में सभी खेलों के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था हो। इस तरफ भी विचार किया जा सकता है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को परीक्षा में अलग से विशेष अंक प्रदान किए जाएं। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति का विकास और तीव्र होगा।

भारत के लिए जरूरी होता ईरान का साथ

हर्ष वी पंत

> अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा को देखते हुए भारत के लिए ईरान का साथ जरूरी है, क्योंकि उसे लेकर दोनों देशों का नजरिया बहुत मेल खाता है

ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तेहरान में उपस्थित रहे। अपने दो दिवसीय ईरान दौरे पर जयशंकर इस आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। एक महीने के भीतर जयशंकर का दूसरा ईरान दौरा यही दर्शाता है कि तेहरान किस प्रकार नई दिल्ली की प्राथमिकताओं में है। दरअसल मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों में ईरान की स्थिति जटिल होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। विशेषकर भारत के लिए ईरान की खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी फंसे हुए हैं। जैसे अमेरिका-ईरान के बीच उलझे हुए रिश्तों के कारण भारत के समक्ष अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। वाशिंगटन ने तेहरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि दोनों देशों में सरकारें बदल गई हैं, फिर भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं दिख रहे। यह भी एक दिलचस्प संयोग है कि अमेरिका में अपेक्षाकृत कट्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान में उदारवादी नेता शासन की बागडोर संभाल रहे थे। वहीं अब अमेरिका की कमान उदारवादी बाइडन संभाल रहे हैं तो ईरान में कट्टरपंथी रईसी का राज आ गया है। वैसे तो बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पूर्ववर्ती ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया, लेकिन ईरान को लेकर उनकी नीति कमोबेश वैसी ही रही। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमेरिका रईसी जैसे कट्टर माने जाने वाले नेता के साथ किस प्रकार आगे बढ़ेगा? इस अनिश्चितता को लेकर भारत के समक्ष समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

वैसे तो भारत की विदेश नीति के लिए ईरान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उसकी महत्ता और बढ़ गई है। यही कारण है कि ईरान को साधने के लिए भारतीय प्रयास यकायक तेज हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी तात्कालिक वजह अफगानिस्तान है। वहां तेजी से बदल रहे समीकरणों में केवल ईरान ही ऐसा देश है, जिसका सोच भारत से बहुत मेल खाता है। अफगान अखाड़े में सक्रिय खिलाड़ियों में जहां पाकिस्तान और चीन एक पाले में हैं। वहीं रूस की स्थिति न इधर न उधर वाली है। ऐसे में अफगान सीमा से सटे देशों में केवल ईरान का रुख ही भारत के अनुकूल है। बदलते हालात के हिसाब से ईरान ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने अफगान सीमा के आसपास अपने लड़ाकू दस्तों को सक्रिय कर दिया है। अफगानिस्तान में अपने व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत को ईरान का साथ जरूरी है।

अवधेश राजपूत

दूसरे महत्वपूर्ण मसले की कड़ी भी कहीं न कहीं अफगानिस्तान से ही जुड़ी है। लैंडलाक्ड यानी भू-आबद्ध देश अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस योजना का विस्तार अधर में पड़ गया है और यह आर्थिक स्तर पर भी अपेक्षित रूप से व्यावहारिक नहीं रह गई है। इस मोर्चे पर भारत की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए चीन इस मौके को भुनाना चाहता है। इसी कारण उसने ईरान में करीब 400 अरब डॉलर के निवेश की एक दीर्घकालीन योजना बनाई है। अनुबंधों में अपनी एकतरफा शर्तों और कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात होने के बावजूद चीन को इस मोर्चे पर मुश्किल इसलिए नहीं दिखती, क्योंकि ईरान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में भारत को कुछ ऐसे उपाय अवश्य करने आवश्यक हो गए हैं कि ईरान में चीन का प्रभाव एक सीमा से अधिक न बढ़ने पाए।

भारत और ईरान के संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों के व्यापारिक रिश्तों का एक खास पहलू यह है कि दोनों देश इसके लिए एक-दूसरे की मुद्रा में विनिमय को प्राथमिकता देते आए हैं, ताकि डालर के रूप में अपनी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पिछले कुछ समय से दोनों देशों का व्यापार घटा है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के कोप का भाजन नहीं बनना चाहतीं। ऐसे में भारत-ईरान के संबंधों के परवान चढ़ने में एक तीसरा पक्ष यानी अमेरिका अहम किरदार बना हुआ है। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजरायल जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में आए व्यापक सुधारों से भी ईरान के साथ रिश्तों की तासीर प्रभावित हो रही है। मोदी सरकार के दौर में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। इसका भारत को पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने में फायदा भी मिला। वहीं इजरायल तो भारत का पारंपरिक रूप से सामरिक साझेदार है। जहां सऊदी अरब और यूएई के साथ ईरान की मुस्लिम जगत के नेतृत्व को लेकर प्रतिद्वंद्विता रही है वहीं इजरायल उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। इन तीनों ही देशों के इस समय भारत के साथ अत्यंत मधुर और बेहद अटूट संबंध हैं। ऐसी अड़चनों के बावजूद भारत ने ईरान को लेकर अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी है। यह बहुत ही स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईरान को भरोसे में लेने के लिए भारत को अतिरिक्त प्रयास करने ही होंगे। विशेषकर रईसी जैसे कट्टरपंथी नेता के साथ ताल मिलाने के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है। जयशंकर की एक के बाद एक यात्राएं इसी सिलसिले में ही हुई हैं।

पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य से लेकर अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हों या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मसला या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी पहलुओं के लिहाज से ईरान का साथ भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिशा में हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके समक्ष ईरान की कहानी से जुड़े अन्य किरदारों को साधने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। उम्मीद है कि भारतीय कूटनीति इस दुविधा और धर्मसंकट का भी कोई न कोई समाधान निकालने के लिए और सक्रियता दिखाएगी, ताकि राष्ट्रीय हितों को अपेक्षा के अनुरूप पोषित किया जा सके।

(लेखक नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं)

response@jagran.com

शेयर बाजार की बढ़ती चमक

डा. जयंतीलाल भंडारी

> शेयर बाजार कोई जुआघर नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की चाल को नापने का एक आर्थिक बैरोमीटर है

इस समय दुनियाभर के विकासशील देशों के शेयर बाजारों की तस्वीर में भारतीय शेयर बाजार की स्थिति शानदार दिखाई दे रही है। भारतीय शेयर बाजार का चमकीला परिदृश्य निवेशकों, उद्योग-कारोबार और सरकार, तीनों के लिए लाभप्रद है। पिछले वर्ष 23 मार्च, 2020 को जो बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 25,981 अंकों के साथ ढलान पर दिखाई दिया था, वह पांच अगस्त, 2021 को 54,717.24 अंकों के स्तर को छूने में सफल रहा। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई में शेयर बाजार के निवेशकों ने 31 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है। इस समय शेयर बाजार में आइपीओ लाने की होड़ मची हुई है। आइपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी 25 फीसद बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में 1.4 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। देश में डीमैट खातों की संख्या 6.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यह बात महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से दशक में पहली बार भारत की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से ज्यादा हो गया है। इस लिहाज से बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात 100 फीसद को पार कर गया है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हांगकांग, कनाडा, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में भी यह अनुपात 100 फीसद से अधिक है।

देश में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। निवेशक यह देख रहे हैं कि कोरोना की चुनौतियों के बीच वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर आठ से नौ फीसद पहुंच सकती है। वहीं भारत समेत दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने बाजार में बड़ी मात्रा में पूंजी डाली है। ऐसे में इस समय ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से नीचे हैं। निवेशक यह भी देख रहे हैं कि करीब छह फीसद से अधिक के मुद्रा प्रसार के बीच फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) पर प्राप्त होने वाला लाभ शेयर बाजार के लाभ से कम हैं। अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंधों की संभावनाओं से निवेशकों की धारणा को बल मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत होने से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में ज्यादा पूंजी लगाने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं।

निवेशकों के भरोसे से तेजी पर सवार शेयर बाजार। फाइल

वहीं चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने वृद्धि दर और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जो एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, उससे भी शेयर बाजार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.8 फीसद तक विस्तारित करने में कोई संकोच नहीं किया है।

बजट में सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बीमा-बैंकिंग, विद्युत और कर सुधारों की डगर पर आगे बढ़ी है। इससे भी शेयर बाजार को गति मिली है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, विनिर्माण तथा सर्विस सेक्टर को भारी प्रोत्साहन शेयर बाजार के लिए लाभप्रद है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ ढांचागत क्षेत्र पर केंद्रित नए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआइ) की स्थापना अच्छा कदम है। टीडीएस नियम भी सरल बनाने की पहल की गई है। बजट में कारपोरेट बांड बाजार की मदद के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा तैयार करने की कोशिश की गई है। बिजली वितरण क्षेत्र को उबारने के लिए बजट में 3,00,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वित्त मंत्री ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार ने आइडीबीआइ बैंक के अलावा दो अन्य सार्वजनिक बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। बजट में लाभांश पर स्पष्टता सुनिश्चित की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और निवेशक बाजार में धन लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। यद्यपि छोटे और ग्रामीण निवेशकों की दृष्टि से शेयर बाजार की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाना जरूरी है। लोगों को यह समझाया जाना होगा कि शेयर बाजार कोई जुआघर नहीं है। यह तो देश की अर्थव्यवस्था की चाल को नापने का एक आर्थिक बैरोमीटर है।

निःसंदेह इस समय भारत में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह लंबे समय से सुस्त पड़ी हुई कंपनियों के शेयर की बिक्री कोविड-19 के बीच तेजी से बढ़ी है, उससे शेयर बाजार में जोखिम भी बढ़ गया है। इसका सबसे अधिक ध्यान रिटेल निवेशकों को रखना होगा। ऐसे में शेयर बाजार में हर कदम फूंक-फूंककर रखना जरूरी है। शेयर बाजार की ऊंचाई के साथ-साथ छोटे निवेशकों के हितों और उनकी पूंजी की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। सरकार द्वारा शेयर और पूंजी बाजार को मजबूत बनाने की डगर पर आगे बढ़ने के लिए सेबी की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाना होगा।

हम उम्मीद करें कि कोविड-19 से ध्वस्त देश के उद्योग-कारोबार सेक्टर को पुनर्जीवित करने में शेयर बाजार बहुत प्रभावी भूमिका निभाएगा। निवेशक शेयर बाजार का लाभ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। वहीं केंद्र सरकार भी चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

इच्छाशक्ति का प्रभाव

दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाने वाला ओलिंपिक अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। इसमें विश्व के कोने-कोने से आए चोटी के खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसमें कुछ को ही सफलता प्राप्त हुई और तमाम के खाते में असफलता आई। सफलता और असफलता का निर्धारण करने में जिन बिंदुओं की अत्यंत निर्णायक भूमिका मानी गई, उनमें से एक है प्रबल इच्छाशक्ति। जिस स्वप्निल मुकाबले के लिए खिलाड़ी कई साल कड़ा परिश्रम करते हैं, उसे वह इच्छाशक्ति और मानसिक दृढ़ता के अभाव में मात्र कुछ ही पलों में गंवा देते हैं। कहते भी हैं कि युद्ध केवल अस्त्र-शस्त्र से नहीं, बल्कि उत्साह से भी जीता जाता है। प्रबल इच्छाशक्ति ही उत्साह की वास्तविक जननी है।

प्रबल इच्छाशक्ति ही मनुष्य की सफलता का मुख्य आधार है। यह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, बस उसे जागृत करने और विकसित करने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व निर्माण इच्छाशक्ति पर ही निर्भर करता है। असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहने की लगन ही इच्छाशक्ति का निर्धारण करती है। इच्छाशक्ति के अभाव में योग्यता, अनुकूलता और प्रतिभा किसी काम की नहीं। दुख और असफलता दुर्बल इच्छाशक्ति के कारण ही आते हैं। अतीत को लेकर पछतावा और भविष्य की अनावश्यक चिंता मनुष्य की इच्छाशक्ति पर आघात करते हैं। गलतियों पर चिंतन करने और कुढ़ते रहने से ऊर्जा व्यर्थ होती है और हमें अकर्मण्य बना देती है। यही अकर्मण्यता इच्छाशक्ति का हनन करती है और मनुष्य जीती बाजी भी हार जाता है।

इच्छाशक्ति के अभ्यास की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ऊर्जा को सकारात्मक, सार्थक कार्यों एवं सत्संग में लगाना चाहिए। उत्साह, सकारात्मक विचार, व्यवहार एवं अनुशासन व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। ये इच्छाशक्ति को संबल प्रदान करते हैं। इसी इच्छाशक्ति का विकास ही व्यक्तित्व को समग्र उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाता है।

शिव मोहन यादव

दुनिया बदल देगा क्वांटम कंप्यूटर

प्रदीप

> आज हम जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। ऐसे में भविष्य क्वाटंम कंप्यूटर में ही निहित है

आज की दुनिया एक तरह से कंप्यूटर के दम से ही चल रही है। ये कंप्यूटर नित नए पल और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। फिर भी आज हम जिन क्लासिकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। इनकी सबसे बड़ी सीमा है डाटा प्रोसेस करने की स्पीड। मौजूदा कंप्यूटर्स गणित के जटिल समीकरणों को हल करने में काफी वक्त लगा देते हैं। इतना ही नहीं उनके साथ स्टोरेज व सर्वर से जुड़ी समस्याएं भी हैं। लिहाजा, क्लासिकल कंप्यूटर्स को और भी उन्नत बनाने में विज्ञानी और इंजीनियर जुटे हुए हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और प्रयोग चल रहा है, जिसका नाम है-क्वांटम कंप्यूटिंग।

क्वांटम कंप्यूटिंग व्यावहारिक रूप से अभी तक विज्ञानियों के लिए भी एक सैद्धांतिक कल्पना जैसी ही थी, लेकिन पिछले दो वर्षों में पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। इस दिशा में हो रही प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा क्वांटम कंप्यूटर तो नहीं, पर उसके प्रोसेसर या सीपीयू को लांच किया जा चुका है। हाल में एक डच स्टार्ट-अप क्वांटवेयर ने दुनिया के पहले क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट (क्यूपीयू) को लांच किया है। इस प्रोसेसर का नाम है सोप्रानो। क्वांटम कंप्यूटिंग के इतिहास में यह एक चमत्कारिक उपलब्धि है।

क्वांटम कंप्यूटर को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन 2019 में गूगल ने यह जता दिया कि दुनिया क्वांटम युग के मुहाने तक पहुंच गई है। दरअसल, सितंबर 2019 में 'नेचर' में प्रकाशनार्थ स्वीकृत एक लेख आनलाइन लीक हो गया था। उससे चला कि गूगल ने 'साइकामोर' नामक क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। बाद में गूगल ने दावा किया कि साइकामोर ऐसी गणनाओं को महज 200 सेकेंड में करने में सफल रहा है, जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को करने में दस साल लग जाते। पता नहीं कि गूगल के दावे में कितनी सच्चाई थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि भविष्य के साधारण क्वांटम कंप्यूटर भी आज के सुपर कंप्यूटर्स से लाखों गुना तेज होंगे।

दुनिया भर के विज्ञानी क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए गहन शोध में जुटे हैं। आज जिसके पास डाटा है, वही शक्तिशाली है। क्वांटम कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने की रफ्तार बढ़ा सकता है। कम स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और डाटा प्रोसेस व गणना तकनीकी को अधिक दक्ष बना देगा। इससे ऊर्जा की खपत भी कम होगी। आज क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रोसाफ्ट, इंटेल, अल्फाबेट-गूगल, आइबीएम, डी-वेव सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विभिन्न देशों की सरकारें (इनमें भारत भी शामिल है) राष्ट्रीय रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा उन पर खर्च कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटर की बदौलत स्वास्थ्य एवं विज्ञान, सुरक्षा, औषधि निर्माण और औद्योगिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा होंगी।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

मेलबाक्स

खेलों में अभी दूर है मंजिल

शुक्रवार के अंक में 'नई खेल संस्कृति का नतीजा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी पढ़ी। उसमें उचित ही लिखा गया है कि 'उत्साहजनक और संतोषजनक केवल यह नहीं है कि टोक्यो गए हमारे अनेक खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो जाने की गवाही भी दे रहे हैं।' इसमें कोई संदेह नहीं कि रियो ओलिंपिक की तुलना में टोक्यो में हमारा अभी तक का सफर बहुत शानदार रहा है। यदि सब कुछ सही रहा तो सर्वाधिक पदकों के मामले में वर्ष 2012 के लंदन ओलिंपिक के छह पदकों का आंकड़ा भी पार हो सकता है। इसके बावजूद यह समय आत्ममंथन करने का भी है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत अभी तक अंगुलियों पर गिनने लायक पदक ही क्यों बटोर पाता है? निशानेबाजी का इतना बड़ा दल जाने के बावजूद वह इतना निराशाजनक प्रदर्शन करता है कि एक कांसे का तमगा तक अपने नाम नहीं कर पाता। इतने नामी-गिरामी तीरंदाज एक भी पदक पर निशाना नहीं लगा पाए। यदि हाकी और कुछ व्यक्तिगत उत्कृष्टताओं को छोड़ दिया जाए तो टोक्यो में भी भारतीय खेलों की वही ढाक के तीन पात वाली पुरानी कहानी ही बयान होती दिख रही है। यदि भौगोलिक रूप से भी देखें तो देश की आबादी में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी जहां मात्र करीब पांच प्रतिशत है, वहीं देश के ओलिंपिक दल में 40 प्रतिशत हिस्सा इन दोनों राज्यों के खिलाड़ियों का ही है। पूर्वोत्तर राज्यों को अपवाद छोड़ दिया जाए तो पंजाब-हरियाणा को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में कोई विशिष्ट खेल संस्कृति नहीं दिखती। इस स्थिति पर न केवल विचार करना, बल्कि उसे बदलने के लिए भी कुछ न कुछ करना होगा। देश में प्रतिभाओं का अकाल नहीं है। आवश्यकता है तो उन्हें समय से चिन्हित करने और आवश्यक रूप से निखारने की। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास अपेक्षित होंगे। अतीत पर रोने से कोई फायदा नहीं। पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेते हुए बेहतर भविष्य की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। तभी पेरिस में भारत का परचम वैसा फहराता दिखेगा, जैसा हम देखना चाहते हैं।

साकेत शर्मा, नई दिल्ली

पुरस्कार को लेकर सराहनीय कदम

केंद्र सरकार ने खेल से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला सराहनीय है, क्योंकि क्रिकेट में जो स्थान डान ब्रैडमैन और फुटबाल में पेले का है, वही स्थान हाकी में मेजर ध्यानचंद का रहा है। उन्हें हाकी का जादूगर कहा जाता था। उनके शानदार खेल के कारण ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीते। उन्हीं के नाम पर देश में खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद देश के पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने हाकी में भारत को एक अलग पहचान दिलाई तथा भारत के लिए पदक लेकर आए। जिस शानदार तरीके से पुरुष और महिला हाकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में प्रदर्शन किया है, उस आधार पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

विजय किशोर तिवारी, दिल्ली

जातिगत राजनीति से ऊपर उठना होगा

हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां आज भी चुनावों में जनता को रिझाने के लिए विकास की बात कम और जाति की बात अधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। ऐसे में कई क्षेत्रीय दल अभी से ही यहां खास जाति के लोगों को अपने पक्ष में करने की जुगत लगा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आज भी ज्यादातर पार्टियां जातिवाद को आधार बनाकर ही चुनावों में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करती हैं। जबकि सभी राजनीतिक दलों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास और जनता का भला करने वाली बातों को आधार बनाकर चुनावों में उतरने के प्रयास करने चाहिए। जनता को भी ऐसे स्वार्थी दलों से सावधान रहने की जरूरत है।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

... डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * ... हवाई शुल्क अतिरिक्त।

75 अंकों के साथ सभी राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है केरल, 'सतत विकास लक्ष्यों' की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 52 सबसे कम अंकों के साथ बिहार इसमें सबसे नीचे है।

आजकल

कैलाश बिश्नोई
शोध अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय

आरक्षण नीति की हो समग्र समीक्षा

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ओबीसी से जुड़े विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की बहस एक बार फिर से चर्चा में है। पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा व नौकरी में आरक्षण देने की मांग भी तेज हो गई है। जाति आधारित राजनीति करने वाले दलों को डर है कि कहीं इन वर्गों का बड़ा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी की तरफ न मुड़ जाए। वैसे देश हित में तो यही है कि आरक्षण पर वोट बैंक की राजनीति के स्थान पर मूल्य आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले

एक निश्चित समयांतराल पर आरक्षण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा होनी चाहिए। प्रतीकात्मक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार संसद में इससे जुड़े विधेयक को प्रस्तुत करेगी। विधेयक पारित होने के बाद राज्यों को केंद्र सरकार से इतर अपने हिसाब से ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा।

दरअसल ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि इसी वर्ष मई में देश की शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने पर राज्यों के अधिकार पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि राज्य सरकारें ओबीसी की सूची का निर्धारण खुद करती हैं, जबकि केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्र अलग से करता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 2018 में संविधान में 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 342ए लाया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन-दो के बहुमत से 102वें संशोधन को सही ठहराया था। बहुमत से 102वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया, किंतु कोर्ट ने कहा कि राज्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की लिस्ट तय नहीं कर सकते, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को अधिसूचित कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने संशोधित विधेयक में अनुच्छेद 342ए में एक संशोधन किया है जिसके तहत राज्य सरकारों को संबंधित राज्य सूचियों में शामिल करने के लिए ओबीसी या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति दी है।

भारत में विभिन्न शोधों और अध्ययनों में यह बात समय-समय पर सामने आती रही है कि ओबीसी में ऐसी अनेक जातियां-उपजातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ समुचित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेने में आगे हैं और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुंच गई हैं, जबकि पिछड़े समाज में एक बड़ा तबका शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा है। केंद्र सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था। यह आयोग पिछड़ा वर्गों में ऐसे समूहों का पता लगाएगा जिनको आरक्षण का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है और साथ ही वे समूह जिन तक आरक्षण का लाभ सिमटकर रह गया है। इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मई 2021 में अपने एक फैसले में राज्यों की ओबीसी सूची को ही गलत बता दिया था, तब रोहिणी आयोग ने राज्यों के साथ आरक्षण पर चर्चा की अपनी पूरी योजना को टाल दिया था। अब केंद्र सरकार के नए संविधान संशोधन विधेयक लाने के बाद राज्यों के साथ यह आयोग पुनः चर्चा शुरू कर सकेगा।

आरक्षण का वर्गीकरण : ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27 प्रतिशत आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालय में प्रवेश में विभिन्न ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की आबादी की तुलना करने के लिए आवश्यक डाटा की उपलब्धता अपर्याप्त है। सनद रहे कि वर्ष 2021 की जनगणना ओबीसी समुदाय से संबंधित डाटा एकत्र करने को लेकर घोषणा की गई थी। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वर्ष 2018 में, रोहिणी आयोग/ ओबीसी वर्गीकरण आयोग ने पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दी गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था। आयोग ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, आइआइटी, एनआइटी, आइआइएम और एम्स समेत विभिन्न केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी प्रवेशों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक, ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-श्रेणियों के केवल 25 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त हुआ। उपरोक्त नौकरियों और सीटों का 24.95 प्रतिशत हिस्सा केवल 10 ओबीसी समुदायों को प्राप्त हुआ। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 983 ओबीसी समुदायों (कुल का 37 प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व शून्य है। विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 994 ओबीसी उप-जातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है। वर्ष 2019 के मध्य में आयोग ने यह सूचित किया कि उसका मसौदा रिपोर्ट (उप-वर्गीकरण पर) तैयार है। यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट के गहरे राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

क्या हो आगे की राह : इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी समुदाय में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में हैं। दरअसल, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्याधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया। यदि इस संदर्भ में थोड़ा और गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि मंडल आयोग से पहले भी आरक्षण के संबंध में लोगों की बहुत-सी शिकायतें थीं, लेकिन आयोग की सिफारिशों के बाद से इन शिकायतों ने गंभीर संघर्ष या उथल पुथल का रुख धारण कर लिया।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में कई समुदायों द्वारा (इनमें कई प्रभावशाली और हाशिये पर खड़े समुदाय भी शामिल हैं) ओबीसी आरक्षण की मांग हेतु आंदोलन करने की घटनाएं सामने आईं। इसमें गुजरात के पाटीदार, राजस्थान के गुज्जर, हरियाणा के जाट और सबसे हालिया महाराष्ट्र के मराठा समुदाय जैसे प्रभावशाली समुदाय का आंदोलन शामिल है। कई आधिकारिक आंकड़ों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि ओबीसी को प्रदत्त आरक्षण ने गरीबों को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है।

पिछले दो दशकों के दौरान एक चिंता यह भी उभर कर सामने आई कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमटकर रह गया है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अंदर ही वर्गीकरण की मांग लगातार की जाती रही है और अब तक नौ राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कर चुकी सरकार ने अब ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर उन पिछड़ी जातियों को राहत देने की तैयारी की है, जिन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। वैसे बेहतर यही होगा कि ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण की बढ़ती मांगों का भी कोई समाधान निकालने की कोशिश हो। केंद्र तथा राज्य सरकारों को ओबीसी और एससी/ एसटी समुदाय के जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ न मिलने की चिंता होनी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वे समय-समय पर इसकी समीक्षा करें, ताकि इस वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिले और संपन्न या सक्षम लोग इसे न हड़पें।

मामले पर बने व्यावहारिक सहमति

केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण से जुड़े हाल ही में दो बड़े फैसलों के बाद यह सवाल फिर इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं! दूसरे शब्दों में कहें तो क्या जनसंख्या के एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने का आधार 'जाति' अथवा 'वर्ग' होना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न के जवाब में लंबे समय से कभी भावनात्मक तो कभी मजबूत प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती रही हैं। लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त विचार और पक्ष लेकर बहस में शामिल होते हैं और शायद ही कभी अपना मत बदलते हैं, यही वजह है कि देश में अभी भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि आरक्षण एक आवश्यक और उपयोगी नीति है। इस प्रश्न के संदर्भ में बहुत-से लोगों का विचार है कि आरक्षण के मानदंड के रूप में केवल आर्थिक पिछड़ेपन को ही आधार बनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का विचार यह है कि इसमें सामाजिक पिछड़ेपन को भी शामिल किया जाना चाहिए। जबकि हमें आरक्षण को और अधिक महत्वपूर्ण एवं तटस्थ होकर देखने की जरूरत है। जहां एक ओर इसने कई वर्गों को लाभान्वित किया है, वहीं यह एक सीमित रियायत भी है जो हाशिये पर खड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक असमानता से मुक्त कर मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करता है।

स्वतंत्रता के बाद सात दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बना रहा है। विडंबना यह है कि भारत में उद्यमिता का अभाव दिखाई पड़ता है, ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की नितांत आवश्यकता है, किंतु एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यों के बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को आरक्षण की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद की जाए। भारत की जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में बच्चों को बताया जाए और आरक्षण के लिए व्यावहारिक सहमति बनाई जाए। हमें यह समझने की जरूरत है कि आजादी के सात दशक बाद भी आरक्षण का समुचित लाभ वंचित तबकों तक नहीं पहुंचा पाया है, ऐसे में बिना समुचित क्रियान्वयन के अनेक प्रकार के प्रविधान किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें कौशल और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। इसके लिए भारत में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जा सके जहां हम बिना किसी किंतु-परंतु के अवसर की समानता की बात कर सकें।

खरी-खरी

विनम्रता-पखवाड़ा

जगदीश ज्वलंत

थाने का पूरा स्टाफ चिंतित था। इतनी सर्विस में आज तक ऐसा प्रचलित आचरण विरोधी आदेश नहीं आया था, जैसा कि आज आया। आपरेटर ने 'विनम्रता' शब्द को सर्च भी किया, किंतु विभागीय शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं था। पखवाड़ा तो समझ में आता था। किंतु यह विनम्रता किस चिड़िया का नाम है?

पूर्व में भी कई मलाईदार पखवाड़े हुए। सट्टा निषेध पखवाड़ा, मजनू-पकड़ो पखवाड़ा, अतिक्रमण हटाओ पखवाड़ा, ट्रैफिक सुधार पखवाड़ा। जिससे सभी में सुधार आया। यह विनम्रता पखवाड़ा समझ से परे था।

कोने में बैठे मुंशी ने कहा- नम्रता को तो मैं जानता हूं। कुछ दिन पहले बस-स्टैंड पर जेब कटी में धराई थी। दरोगा ने मुंशी के मूर्खतापूर्ण जवाब पर आंखें तरेरते हुए कहा- अब उसी का पखवाड़ा बचा है मनाने को?

एक अधिक पढ़े लिखे जवान ने आदेश को ध्यान से पढ़ा। एक शब्दावली की सूची दी गई थी। सभी को इन्हीं शब्दों का प्रयोग पूरे पखवाड़े करना था। जैसे- प्रिय, आदरणीय, सर, महोदय, महाशय, महानुभाव, भाई-साहब आदि।

बिना गाली के तो नौकरी हो ही नहीं सकती। संस्कारों में परिवर्तन के आदेश से विभाग की छवि कहीं मसखरे कि न हो जाए? अब क्या चोर को कहें कि -चोर जी, कृपया बताइएगा आप ने चोरी की? तो वह चोरी कबूलेगा? संस्कारी, सदाचारी और सहिष्णु होने से स्टाफ सामाजिक हो गया तो? कर्मचारी कायर हो गए तो? इसी पखवाड़े निवृत्ति को प्राप्त होने वाले एक वरिष्ठ दारोगा ने अपना तर्क रखा। आदेश में मुस्कुराने के भी निर्देश थे। सभी ने मुस्कुराते हुए स्वयं को आईने में देखा। वे स्वयं का चेहरा नहीं पहचान पाए। स्वयं के मुस्कुराने पर स्वयं को ही हंसी आ रही थी। उन्हें मुस्कुराते देख उनकी पत्नियां तक चिंतित, भयभीत, आशंकित हो उठीं। इन्हें हुआ क्या है? कहीं भाग-वांग तो नहीं खाली? उन्हें आज एहसास हुआ कि मुस्कुराहट कितनी विकृत होती है, भयानक होती है, कुरूप होती है।

आज विनम्रता पखवाड़े का अंतिम दिन है। इधर विभाग चिंतित है। यदि विनम्रता एक स्थाई भाव बन सभी में समा गई तो? उधर सारे विनम्रता पीड़ित अपराधी अलग चिंतित हैं। जिस दिन यह ओढ़ी हुई विनम्रता हट गई तो? देखते हैं कल क्या होता है?

ट्वीट-ट्वीट

किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता को उन्हीं लोगों के नाम पर सम्मानित किया जाना चाहिए, जिन्होंने उस क्षेत्र विशेष में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हों। जैसे सिनेमा में दादा साहब फाल्के तो खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ऐसे में खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी के नाम पर किया जाना एक विसंगति ही थी, जिसे सुधार दिया गया है। अखिलेश मिश्रा@amishra77

अगर कांग्रेस स्मार्ट है तो उसे खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने के फैसले का स्वागत करना चाहिए। यह किसी भी लिहाज से उपयुक्त नहीं था कि देश में खेलों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान किसी एथलीट के बजाय एक नेता के नाम पर था। सदानंद धूमे@dhume

दिल्ली में कुछ बहुत दूर तक देख लेने वाले साथी बैठे हैं, जिनकी पास की नजर बेहद कमजोर है। उन सबको नाम बदलने के लिए आज अहमदाबाद का स्टेडियम तो दिख रहा है, मगर दिल्ली के दो बड़े-बड़े स्टेडियम नहीं दिख रहे। ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

चूंकि सरकार नाम बदलने के मूड में है तो आखिर किसी एयरपोर्ट का नामकरण जेआरडी टाटा के नाम पर क्यों नहीं कर दिया जाता। विमानन क्षेत्र के विकास में इंदिरा गांधी का 'अहम योगदान' रहा है, फिर भी सरकार विचार तो करे। किसी स्टेडियम का नामकरण मिल्खा सिंह के नाम पर कैसा रहेगा? यह सूची अंतहीन है। नेहरू पार्क को भी सलीम अली का नाम दिया जाए। सुहेल सेठ@Suhelseth

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल विपक्ष के लिए झटका है?

हां	69.1
नहीं	25.5
कह नहीं सकते	5.4
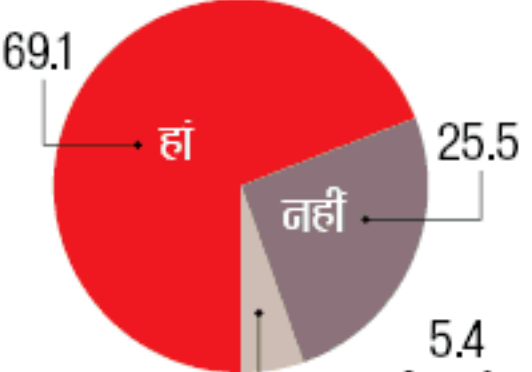
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नेताओं के नाम वाले सभी स्टेडियमों का नामकरण खिलाड़ियों के नाम पर किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पटनायक से सीखिए संघ राज्य का धर्म,
सिर्फ सियासत छोड़ अब दिखलाओ कुछ कर्म।
दिखलाओ कुछ कर्म तभी तो होगा 'खेला',
तब भारत भी देख सके पदकों का रेला।
करे देश हित काम वही है असली नायक,
ज्यों हॉकी को पाल-पोस उभरे पटनायक!
– ओमप्रकाश तिवारी

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

असहज करने वाली सहज मुलाकातें

इधर मेल-मुलाकातों का सिलसिला तेज है। सामान्य सी दिखने वाली सियासी चोले में लिपटी मुलाकातें। मोदी विरोधी तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे ओमप्रकाश चौटाला से नीतीश कुमार की मुलाकात। लालू की मुलाकात मुलायम और शरद यादव से। मोदी और योगी से 'हम' के संतोष मांझी की मुलाकात। सब बेहद सामान्य सी मुलाकातें, लेकिन हर मुलाकात के अपने सियासी मायने।

बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव बेहद प्रासंगिक हैं। दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए जरूरी हैं लालू। लालू का साथ और लालू के डर के बीच बंटी है बिहार की राजनीति। पिछले विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए भी लालू एनडीए के हर मंच पर हाजिर रहे। विकास का मुद्दा हवा था, लालू का जंगलराज एनडीए का हथियार था। अब जब से जमानत पर बाहर आए हैं लालू, भाजपा के कई नेता केवल उन्हीं के विरोध में बयानबाजी कर अपनी राजनीति चमकाए हैं। और लालू हैं कि उनके लिए भी राजनीति ही दवा है। जब भीतर थे तो स्वास्थ्य काफी खराब था। बाहर आए तो बोलते नहीं बन रहा था। एक-दो बार कार्यकर्ताओं व नेताओं को संबोधित किया तो जबान और शरीर दोनों ही साथ देते नहीं दिख रहे थे। लेकिन इन दिनों हर मुलाकात के बाद उनमें निखार आता दिख रहा है। पहले मुलायम के घर और उसके बाद शरद यादव के घर जाकर हुई उनकी मुलाकातों ने उनके शरीर में ही नहीं बिहार की राजनीति में भी रंग भर दिया है। भाजपाई इन मुलाकातों में राजनीति देख रहे हैं और उनकी जमानत रद करने की बात करने लगे हैं। जबकि लालू समर्थक मुलाकातों को सामान्य बता रहे हैं।

इधर नीतीश कुमार की सक्रियता विरोधियों को भाने लगी है और साथी भाजपा को असहज कर रही है। जाति

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (मध्य में) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (सबसे दाएं) से रविवार को गुरुग्राम में मुलाकात की। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के महासचिव डा. केसी त्यागी भी मौजूद थे। जागरण आर्काइव

आधारित जनगणना का मुद्दा दोनों के बीच फांस बनता दिखाई दे रहा है। विधानमंडल से दो बार पारित इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं नीतीश। वो इस मुद्दे पर समर्थन बटोरने के लिए निकलने वाले हैं। उन्होंने मिलने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समय भी मांगा है। उन्होंने स्थानीय भाजपा से भी कहा है कि वह भी साथ चले। इस मुद्दे पर भाजपा से असहमत नीतीश मोदी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे ओमप्रकाश चौटाला से गुरुग्राम जाकर मिल आए। मुलाकात हाल-चाल लेने वाली बताई गई, लेकिन राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की हवा फैला गई। भाजपा और सशंकित हो गई। सबकुछ सहज दिखने वाले हालात के भीतर कुछ-कुछ असहज सा दिखने लगा है। इधर नीतीश का जनता दरबार और जनता के बीच भ्रमण भी चौंकाए है। विरोधी लालू के सुर भी नीतीश के प्रति नरम हैं और तेजस्वी के तेवर भी। कुल मिलाकर विरोधी नरम हैं और सहयोगी सशंकित।

भाजपा व जदयू के अलावा सरकार के अन्य सहयोगी हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) व वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) भी चुपचाप नहीं बैठी हैं। दोनों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं और दोनों भाजपा कोटे से सीटें हासिल करने की जुगत में हैं। वीआइपी वहां फूलन देवी के सहारे जमीन तैयार करने में जुटी है। योगी सरकार की सख्ती की वजह से वहां 18 मूर्तियां लगाने की उसकी कोशिश नाकाम रही तो अब वो 50 हजार मूर्तियां कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घर में लगाने की तैयारी में है। स्वाभाविक है कि इसमें सरकार से टकराव बढ़ेगा और वीआइपी इसी विरोध के बूते अपना वोट बैंक लामबंद करना चाहती है। इस उम्मीद के साथ कि मजबूत वोटबैंक अभी का विरोध खत्म करने में सहायक होगा। अकेले लड़ने पर वह वहां 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा किए है। जबकि इसके उलट हम सीधे योगी के सहायक बनकर उतरने की कोशिश में है। अभी हम के युवराज यानी जीतनराम मांझी के पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने योगी से मुलाकात की उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें 40 मिनट का समय देकर तमाम संभावनाओं को बल दे दिया। संतोष मांझी की इन मुलाकातों ने न केवल उनका राजनीतिक कद बढ़ाया, बल्कि यूपी में हिस्सेदारी की आस भी। अब देखना है कि ये मुलाकातें भविष्य में कोई गुल खिलाती हैं या सामान्य सी होकर गुम हो जाती हैं।

मंथन

डा. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

आर्थिक दुर्दशा की ओर बंगाल

राज्यों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि बंगाल निरंतर पिछड़ता जा रहा है

बीते दो-तीन दशकों में बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट के संकेत। फाइल

भारत के अत्यंत पिछड़े हुए कुछ राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) को उनके नाम के पहले वर्ण को मिलाकर 'बीमारू' राज्य कहा जाता रहा है। इन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय तो कम थी ही, मानव विकास के संकेतकों की दृष्टि से भी इनकी गिनती पिछड़े राज्यों में होती थी। समय बदला, इन राज्यों में भी आर्थिक विकास के प्रयास हुए और उनकी विकास दर भी बेहतर हो गई। उनके मानव विकास संकेतकों में भी सुधार होने लगा।

पिछले दो वर्षों से 'नीति आयोग' ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए 'सतत विकास लक्ष्यों' के अंक प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। 'सतत विकास लक्ष्यों' की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 75 अंकों के साथ राज्यों में केरल सबसे ऊपर बना हुआ है जबकि बिहार सबसे कम 52 अंकों के साथ सबसे नीचे है। हालांकि कई राज्य आकांक्षी (यानी 50 अंकों से कम) से आगे बढ़ते हुए निष्पादक (परफार्मर) की श्रेणी में आ गए हैं, इसके बावजूद सात राज्य अभी भी 60 अंकों से कम ही हैं। आज कोई भी राज्य 50 अंकों से कम नहीं है, यानी सभी राज्य निष्पादक (जिनके अंक 65 से अधिक हैं) की श्रेणियों में पहुंच गए हैं।

उत्तर प्रदेश व बंगाल के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया जाए तो अत्यंत रोचक तथ्य सामने आते हैं। वर्ष 2019-20 में बंगाल की प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक 1,15,748 रुपये थी, जबकि उत्तर प्रदेश में यह मात्र 65,704 रुपये ही थी। यदि सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़े देखें तो यूपी 60 अंकों के साथ बंगाल के 62 अंकों की तुलना में थोड़ा ही पीछे था और ऐसा लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश इसी तरह से अपना कार्यनिष्पादन बेहतर करता रहा, तो बंगाल को जल्द पीछे छोड़ सकता है।

गौरतलब है कि 2018 में सतत विकास लक्ष्यों में बंगाल 56 अंकों के साथ देश में 17वें स्थान पर था, जबकि उत्तर प्रदेश 42 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर था। वर्ष 2020 तक आते-आते बंगाल मात्र छह अंक बढ़कर 62 अंक तक पहुंचा, जबकि उत्तर प्रदेश 18 अंकों की छलांग के साथ 22वें स्थान पर पहुंच गया। यानी जहां दो वर्षों में बंगाल के केवल छह अंक बढ़े, उत्तर प्रदेश के 18 अंकों की छलांग ने उसे कई अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ा दिया।

क्यों पिछड़ रहा बंगाल: यहां मामला मात्र पिछले दो वर्षों का नहीं है। पिछले लगभग दो-तीन दशकों में बंगाल विकास की दृष्टि से फिसड्डी रहा है। यदि आठवीं से 11वीं पंचवर्षीय योजना तक का सफर देखा जाए तो पता चलता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना को छोड़, बंगाल की जीडीपी ग्रोथ की दर राष्ट्रीय औसत से कम रही। इसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले दो दशकों के आरंभिक 12 वर्षों में जब देश की औद्योगिक विकास दर काफी अधिक थी, बंगाल में औद्योगिक विकास की दर इतनी कम हो गई कि जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगातार घटने लगा। जो बंगाल एक औद्योगिक राज्य था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के 2004-05 के अनुमानों के अनुसार उसकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा वर्ष 2004-05 में 11.1 प्रतिशत से घटता हुआ 2011-12 तक 9.21 प्रतिशत ही रह गया। यानी बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र का लगातार क्षरण ही हुआ है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग घटने से रोजगार के अवसर घटते हैं। यहां रोजगार पाने के लिए लोग छोटे-मोटे काम-धंधों में संलग्न हो जाते हैं या आकस्मिक (कैजुअल) श्रमिक बन जाते हैं। इसका असर यह हुआ कि जहां देश में 24.1 प्रतिशत श्रमिक आकस्मिक श्रेणी में आते थे, बंगाल में 29.8 प्रतिशत श्रमिक आकस्मिक श्रेणी में है। यानी बंगाल में श्रम का आकस्मिकीकरण हुआ है।

सामान्य तौर पर माना जाता है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकास हो तो उसका सकारात्मक असर रोजगार के अवसरों पर पड़ता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ-साथ लोगों के कुशल क्षेम में भी सुधार होता है। पिछले लगभग 20 वर्षों में बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि जहां अन्य राज्यों में सतत विकास के लक्ष्यों में अधिक सुधार हुआ है, बंगाल का कार्यनिष्पादन नितांत असंतोषजनक रहा है। यदि पिछले वर्ष का हिसाब लगाया जाए तो गरीबी उन्मूलन में बंगाल का कार्यनिष्पादन इस कारण से प्रतिकूल रहा, क्योंकि मनरेगा में मजदूरों को मांग से कम रोजगार मिला। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक तरफ पांच वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई तो दूसरी ओर प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि हो गई, हालांकि संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन लिंग समानता में स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच पारिश्रमिक में अंतर पहले से ज्यादा हुआ है। कार्य के स्तर और आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत मामूली बेहतरी दिखाई देती है।

उत्तर प्रदेश का कार्यनिष्पादन, बंगाल से कहीं बेहतर होने के कारण ऐसा लगता है कि प्रतिव्यक्ति आय ही सतत विकास का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। बंगाल सरकार को देखना होगा कि सतत विकास के विभिन्न मापदंडों पर गंभीरता से विचार हो, पिछले दो दशकों से चल रही औद्योगिक क्षेत्र की दुर्गति समाप्त हो और निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले।

बंगाल

वैक्सीन पर जारी आरोप-प्रत्यारोप

बंगाल में कोरोना की वैक्सीन को लेकर शुरू से ही भाजपा और तृणमूल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ था वह फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। अभी तीन दिन पहले ही राज्य के भाजपा सांसदों के दल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर कोरोना वैक्सीन पर सियासत करने का ममता सरकार पर आरोप लगाया था। इसके बाद गुरुवार को एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन वितरण में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। साथ में यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि भाजपा शासित राज्यों को बंगाल से अधिक वैक्सीन दी जा रही है, जबकि बंगाल का जनसंख्या घनत्व इन राज्यों से कहीं अधिक है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कूपन बांटे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष पहले ही इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्टी कार्यालय का उपयोग किसी भी तरह से टीकाकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा था कि केवल तृणमूल समर्थकों व कार्यकर्ताओं को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। यही नहीं वैक्सीन की कालाबाजारी होने की भी बात उन्होंने कही थी।

> उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि भारतीय जनता शासित शासित राज्यों को बंगाल से अधिक कोरोना रोधी वैक्सीन देने का आरोप लगाया जा रहा है

आखिर कोरोना महामारी से लड़ने वाले टीका को लेकर इस तरह सियासत और आरोप-प्रत्यारोप क्यों? विधानसभा चुनाव से पहले और उस दौरान भी ममता यह कहती रहीं कि उनकी सरकार सीधे वैक्सीन खरीदकर राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगवाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। जब केंद्र ने राज्यों को सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दे दी तो ममता कहने लगी कि केंद्र सरकार को मुफ्त टीका देना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर बंगाल की सीएम प्रधानमंत्री मोदी को कई पत्र लिख चुकी हैं। अब उनका आरोप है कि कम टीका मिल रहा है। बंगाल में यह हाल है कि सरकारी तौर पर 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों को मुफ्त टीका लगवाने के लिए मारे-मारे फिरना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम समेत मेडिकल जांच केंद्रों में रुपये देकर लोग टीके लगवा रहे हैं। यदि कोविन एप पर बंगाल के जिलों में टीका केंद्रों का स्लाट देखें तो पता चल जाएगा कि टीका की कमी कहां है? केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि देश के हर कोने में पर्याप्त टीका पहुंचे और एक भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित न रहे। ऐसे में राजनीति बंद होनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश

बेसहारा पशुओं को आश्रय

हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। राज्य की आर्थिकी में कृषि बागवानी अहम हैं, लेकिन बेसहारा पशुओं के कारण कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई जिलों में लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। बेसहारा पशु हादसों का कारण भी बन रहे हैं। कई बार पशु घायल हो रहे हैं तो कई बार हादसों में लोगों को जख्म मिल रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं।

बेसहारा पशुओं की समस्या का मामला इसी सप्ताह विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी दो विधायकों ने उठाया। सरकार की तरफ से बताया गया कि इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। गौ सदन और गौ अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। तीन गौ अभयारण्य बन चुके हैं जिनमें 800 से अधिक पशु रखे गए हैं। देखभाल के लिए प्रत्येक पशु 500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। गौ वंश का पंचायतों में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और पशुओं को खुला छोड़ने पर पांच सौ रुपये

गौवंश को बेसहारा छोड़ने से पैदा हो रही अनेक समस्याएं। फाइल

> सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु हर किसी के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, वे चाहे राहगीर हों या फिर किसान। ऐसे में इनके रहने व खाने-पीने की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए

जुर्माने का प्रविधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

दरअसल खेती के लिए बछड़ों का प्रयोग न किए जाने से यह समस्या बढ़ी है। इस समस्या से निपटने के लिए योजना बनाई जा रही है कि अब बछड़ी ही पैदा हो। सड़कों पर घूमता बेसहारा गौ वंश उस समाज को आईना भी दिखाता है जहां पर गौ वंश की पूजा की जाती है। स्वार्थ निकलने पर पशुओं को बेसहारा छोड़ना कतई उचित नहीं है। सुखद है कि समाज में कई लोग गौ सदन में रखे गए पशुओं के लिए चारे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, जबकि कुछ लोग सड़कों पर घायल होने वाले पशुओं के इलाज के लिए जुटे हैं, लेकिन इस समस्या के पूर्ण समाधान के लिए यह जरूरी है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि गौवंश को बेसहारा न छोड़ा जाए। सरकार के साथ समाज भी इस समस्या के समाधान का प्रयास करेगा तो संभव है कि यह समस्या हल हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश

कठोर दंड से भ्रष्टाचार पर लगाम

अन्नदाताओं को सुखी करने और सम्मान देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन्हीं में से एक है किसान सम्मान निधि। इसके तहत किसानों को केंद्र सरकार साल में छह हजार रुपये प्रदान कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की नजर इस निधि पर भी लग गई है। अपात्र धड़ल्ले से इसका लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। अकेले बरेली मंडल में 55,243 अपात्र किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहीं भी मौका मिलते ही भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते। सवाल है कि आखिर अपात्र लोग कैसे किसी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कई स्तर पर जांच होती है और तक पात्र का चयन किया जाता है। निश्चित रूप से बहुत निचले स्तर से ही सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक लग जाता है। बुनियादी स्तर पर जिन्हें जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, वही इसमें जेब भरने में जुट जाते हैं। फिर यह सिलसिला नीचे से

किसान सम्मान निधि में भ्रष्टचार को दूर करना आवश्यक है। फाइल

> कठोर कदम उठाने पर ही भ्रष्टाचार रुकेगा और योजनाओं का लाभ सही पात्र उठा पाएंगे। अपात्रों को दी जा रही किसान सम्मान निधि निरस्त की जाए

ऊपर तक बढ़ता चला जाता है।

किसान सम्मान निधि में भ्रष्टाचार कोई पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण और तरीके भी सबको पता हैं, फिर इन योजनाओं को संचालित करने से पहले कोई ऐसी फूलप्रूफ तैयारी क्यों नहीं की जाती, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। एक ही गलती योजना दर योजना क्यों दोहराई जाती है। महत्वपूर्ण बात है कि योजनाओं में भ्रष्टाचार सामने आने पर उसमें कड़े दंड का विधान नहीं है। साथ ही मामला कोर्ट कचहरी में इतना लंबा खिंच जाता है कि दंड देने का मकसद ही समाप्त हो जाता है। होना तो यह चाहिए कि जानबूझ कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों की न केवल संपत्ति जब्त कर ली जाए, बल्कि सरकार कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर देना चाहिए। वस्तुतः कठोर कदम उठाने पर ही भ्रष्टाचार रुक पाएगा और योजनाओं का उचित लाभ सही पात्र उठा पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार का यह सिलसिला रोक पाना शायद ही संभव हो सके।

उत्तराखंड

आंदोलन की राह पर कर्मचारी

प्रदेश में इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कोई विनियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है, तो कोई वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। कहीं ग्रेड पे को लेकर आक्रोश है, तो कहीं पदोन्नति न होने पर हुंकार भरी जा रही है। अपनी तमाम मांगों को लेकर कर्मचारियों के तेवर दिन ब दिन और सख्त होते जा रहे हैं। सरकार पर लगातार इन मांगों को पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। देखा जाए तो कर्मचारियों की मांगें जायज भी हैं। जब लगातार सरकार को ध्यान दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

सरकार को चाहिए कि वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों की जिन मांगों को निस्तारित किया जा सकता है, उन पर जल्द निर्णय ले। कर्मचारी संगठनों को भी सोचना चाहिए कि आखिर उनकी मांगों को पूरा करने के मामले में सरकार क्यों कदम रोके हुए है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी सरकारी व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। उनकी भी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी है। आंदोलन ही हर समस्या का समाधान नहीं है, मगर प्रदेश में आंदोलन एक परंपरा सी बन गया है। दरअसल, यह देखा गया है कि चुनावी साल में सभी राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं। स्वाभाविक है कि चुनावों के दृष्टिगत सरकार भी जल्द दबाव में आ जाती है, इसलिए भी इस प्रवृति को बल मिलता है। यही देखा गया है कि आंदोलन के बाद ही कर्मचारियों की मांगों के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाते हैं।

> अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवादहीनता ही आंदोलन का रूप लेती है। आपसी संवाद से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है

सोचनीय यह है कि जब मांगों पर निर्णय लेना ही है तो फिर क्यों ऐसी नौबत आने दी जाती है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरें। यह स्थिति तब है, जब सरकार ने शासन और विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए समितियां गठित की हुई हैं। विभागीय सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर कर्मचारी संगठनों से वार्ता करें और उनकी समस्याओं को सुनें। जिन समस्याओं का हल उनके स्तर से नहीं होता, उसे शासन और सरकार के सम्मुख लाया जाए।

जाहिर है कि व्यवस्था पर गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवादहीनता है। सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण को अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे, ताकि प्रदेश के विकास में आंदोलन रूपी बाधाएं न आएं। कर्मचारियों के आंदोलन से राज्य के कार्यों में बाधाएं आती हैं जिससे विकास प्रभावित होता है।

श्रद्धा का महासावन

राममय शिव

सारूप्य, सालोक्य, सान्निध्य, सायुज्य और कैवल्य। ये सभी प्रकार की मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। वस्तुतः ये पांचों मुक्ति भक्ति विषयक ही हैं। भक्ति पर विश्वास ही ज्ञाता स्वरूप है, यह निर्विवाद सत्य है। भगवान के रूप की उपासना करने वाले साधक को सारूप्य मुक्ति मिल जाती है और वह सांसारिक रूपाकर्षण से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। मुझे भगवान की निरंतर सेवा करने को मिलती रहे, इस समर्पण भावना में निष्ठ साधक को सान्निध्य मुक्ति मिल जाती है। फिर वह जीवन की प्रत्येक उपलब्धि को भगवान की सेवा सामग्री बना देता है। जिसने अपने दिव्य विवेक से परम ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए न तो कोई पूर्व संस्कार शेष रह जाता है, न कोई कर्मजन्य प्रारब्ध ही। ऐसी स्थिति में वह साधक सायुज्य अथवा कैवल्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान शिव इतने कृपालु एवं दयालु हैं कि यदि कोई प्राणी उनकी प्रिय नगरी काशी में शरीर त्याग दे तो इसी विशेषता पर वह मृत्यु के समय उसके कान में राम नाम मंत्र फूंककर उसे अपने शिष्य के रूप में दीक्षित कर देते हैं। भगवान शंकर में मुक्ति बांटने की जो अलौकिक शक्ति और उदारता है, वह निरंतर राम नाम जपने से ही आई है। उसी के प्रभाव से वह गरल पीकर भी मृत्यु से मुक्त रहे और उसी राम नाम के प्रभाव से उनके पुत्र प्रथम पूज्य हुए। राम नाम पर विश्वास शिव का परमाश्रय है, जिसके कारण शिव उद्भव, स्थिति और प्रलय में भी सच्चिदानंदमय और ब्रह्मानंदमय स्थिति से विरत नहीं होते हैं।

संत मैथिलीशरण
अध्यक्ष श्री रामकिंकर विचार मिशन स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही की अनदेखी का विरोध शुरू

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में सरकारी नियुक्तियों के लिए चयनित एक दर्जन भाषाओं में से द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त कई भाषाओं को हटा दिए जाने का तीव्र विरोध हो रहा है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने तो आवाज बुलंद की ही है, विपक्षी दल भाजपा और आजसू (आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन) ने भी फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि भाषाओं का भी विकल्प छात्रों के लिए खुला रखने की मांग की है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने इस फैसले में अंगिका की अनदेखी पर सवाल उठाया है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है।

रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि इस निर्णय से एक बड़ी आबादी की अनदेखी हुई है। जिन 12 भाषाओं का चयन किया गया है, उनमें से अधिसंख्य भाषाओं से गढ़वा-पलामू के लोग अनजान हैं। ऐसे में सरकार का फैसला गलत है। वहीं, झामुमो और प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि पूर्व की नियोजन नीति में खामी थी। आदिवासी, मूलवासी, दलितों और पिछड़ों के लिए यह हितकारी कदम है। गौरतलब है कि गुरुवार को राज्य कैबिनेट में नियोजन नीति लाई गई है, इसमें

> झारखंड में जन्मे, पले और बढ़े लोगों का तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों पर पहला हक है। जिनकी नाभि इस धरती में गड़ी है, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। सरकार का फैसला ऐतिहासिक है।
> -सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव, झामुमो

> राज्य सरकार ने पूर्व की नियमावली को परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है। यह न सिर्फ राजभाषा का अपमान है बल्कि इसका सीधा असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा।
> - प्रतुल शाहदेव, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा

यह भी फैसला लिया गया है कि झारखंड की तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियां अब उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होंगे। भाषा संबंधी भी फैसला लिया गया है।

मंत्री ने सीएम को सौंपा मांग पत्र : मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तर्क दिया कि झारखंड की एक बड़ी आबादी वर्षों से झारखंड में निवास कर रही है और वे यहां के मूल निवासी हैं। वह भी मगही, अंगिका एवं भोजपुरी आदि भाषा का उपयोग करती है। यदि इन्हें क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया तो ऐसे छात्र-छात्राओं की बड़ी संख्या प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएगी। ठाकुर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मुलाकात कर उन्हें इस संदर्भ में मांग पत्र भी सौंपा।

मन गिरधर गोपाला...घर 'गिरधर गोशाला'

आलोक शर्मा, कानपुर

सेवा के लिए साधन-संसाधन अहम हैं, मगर जो चीज सबसे जरूरी है, वो है मन। ऐसा ही मन कानपुर के कारोबारी ऋषभ मोहन अग्रवाल के पास है। वह अपने आसपास बेसहारा, बीमार व बूढ़ी गायों की दुर्दशा देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। इसी तड़प से मन में बैठे गिरधर गोपाला ने प्रेरणा दी तो कारोबारी ऋषभ का छावनी स्थित घर गिरधर गोशाला बन गया।

आइआइटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अपना बिजनेस करने का विचार आया तो ऋषभ अग्रवाल ने कोल्ड स्टोर का काम शुरू किया। आज वह एक प्रतिष्ठित कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। इससे इतर उनकी एक और पहचान है, वह है गोसेवक की। वह बताते हैं, सड़क पर कूड़ा और प्लास्टिक खाती गायों को देखकर वह विचलित हो जाते थे, तो खुद उन गायों को सब्जी व चारा खरीदकर खिलाते थे। कारोबार के चलते अधिक समय नहीं दे पाने के कारण 2012 में पनकी में गोरथ सेवा शुरू की। इसके लिए संचालकों को प्रतिवर्ष नौ से 10 लाख रुपये की धनराशि दी। वहां धनराशि का दुरुपयोग होता देख दो साल में ही गोरथ सेवा बंद कर दी। 2014 में घर में ही गोशाला बनाने का निर्णय लिया। रूमा से दो बेसहारा गाय लेकर आए, जिन्हें रामा और श्यामा नाम दिया। इनकी सेवा करते-करते अब उनकी गोशाला में 37 गायें हैं, जो यहां आराम से रहती हैं और ताजा चारा खाती हैं। गायों की देखरेख और उनके खानपान में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख रुपये का खर्च होता है। मां प्रमिला अग्रवाल भी गायों की देखरेख में लगी रहती हैं। उन्होंने बताया कि गोशाला में रहने वाली एक भी गाय दूध नहीं देती है। बाहर से लाई गई एक गाय के बछिया पैदा हुई थी। कमजोर होने के कारण गाय के ज्यादा दूध नहीं निकला, जो दूध निकलता था वह बछिया ही पी जाती थी।

डाक्टर भी करते हैं देखरेख

गोशाला में किसी गाय के बीमार पड़ने पर उनका इलाज उन्नाव के डा. राम करते हैं। ऋषभ बताते हैं, डाक्टर को किसी भी समय फोन करो, वह तत्काल पहुंचने की कोशिश करते हैं।

गोशाला में बछड़े के साथ ऋषभ मोहन अग्रवाल। स्वयं

बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकारियों के बच्चों की बन रही सूची

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अलावा क्लास-वन एवं क्लास-टू के अफसरों के बच्चों की सूची तैयार हो रही है। इसकी रिपोर्ट 10 अगस्त को सभी डीएम एवं एसपी के साथ शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में आएगी।

13 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले अधिकारियों के बच्चों के बारे में जानकारी देने को कहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिलों से इससे संबंधित विवरण नहीं मिला है, जबकि इसके लिए 26 जुलाई को ही निर्देश दिया गया था।

दो लाख पंचायतों में भी नहीं हैं अपने भवन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के मुकाबले दो लाख से कम ग्राम पंचायतों में अपने मिनी सचिवालय (पंचायत भवन) हैं। भवनों और कर्मचारियों की कमी के चलते गांव के लोगों को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। समिति ने ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की सिफारिश की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपना भवन होगा, जिसमें संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे गांव के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

समिति ने सिफारिश में कहा है कि देश के मात्र 2.01 लाख ग्राम पंचायतें ही कंप्यूटर से लैस हैं। स्थायी समिति की बैठक में मंत्रालय ने बताया कि 30 हजार नए पंचायत भवन निर्माण करीब पूरा हो चुका है। छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 24,808 भवन निर्माणाधीन हैं। ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के घटक के रूप में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण को भी शामिल किया गया है। इसके तहत 1347 ग्राम पंचायतों को निर्माण किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रयास करने को कहा है।

ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण का अभियान कई राज्यों में बहुत धीमी गति से चल रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण कम हो सका है। मंत्रालय ने स्थायी समिति के समक्ष स्पष्ट किया कि इस बाबत वित्त मंत्रालय के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा, ताकि वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

हालांकि समिति ने कुछ राज्यों में पंचायतों के कंप्यूटरीकरण पर प्रसन्नता भी जताई है। मालूम हो कि निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पंचायतें पूरी तरह कंप्यूटर से लैस हैं।

समिति ने इस बात पर नाखुशी भी जताई कि पंचायती राज मंत्रालय के 894.03 करोड़ रुपये की बजटीय मांग की तुलना में केवल 593 करोड़ रुपये ही वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूर किए गए हैं। जिन राज्यों की ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए समिति ने अतिरिक्त धन की मंजूरी की सिफारिश की है।

105 साल में पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की निदेशक बनी महिला

कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआइ) की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 105 साल पुराने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआइ) की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी बनी हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अनुसंधान के मानक प्रारूपों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) और इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है ताकि देश की विविधता को सभी लोग समझ सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को संरक्षण के महत्व को समझने की भी जरूरत है।

संस्थान की पहली महिला निदेशक नियुक्त किए जाने पर बनर्जी ने कहा कि इससे कनिष्ठ महिला विज्ञानियों में विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कभी किसी तरह के लैंगिक भेदभाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हां, यह सशक्तीकरण की भावना है, जो अन्य भावनाओं पर हावी हो जाएगी। यदि संस्था की मुखिया एक महिला है, तो इससे सहज रूप से सत्ता में महिला को अधिक मान्यता मिलती है। एक कामकाजी महिला के लिए घर और करियर में संतुलन बनाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है।

जागरण विशेष

रोग की सटीक पहचान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी मददगार

इलाज में अहम भूमिका निभाएगा आइआइटी कानपुर, एआइ से लैस जांच उपकरण बनाने की तरफ बढ़ाया कदम

शशांक शेखर भारद्वाज • कानपुर

आधुनिक तकनीक के सहारे देश में अब इलाज की राह और आसान होगी। चिकित्सीय जांच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे मरीज की जांच के दौरान ही बीमारी की सटीक पहचान हो सकेगी, समस्या तुरंत पता चल जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर ने इसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं। आइआइटी के स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलाजी (एसएमआरटी) में चिकित्सीय जांच उपकरणों में एआइ और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल होगा।

अभी एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआइ व खून आदि की जांच समेत अन्य तरीके से रोगों की पहचान की जाती है। रिपोर्ट रेडियोलाजिस्ट, पैथोलाजिस्ट और दूसरे विशेषज्ञ चिकित्सक जारी करते हैं। रिपोर्ट के आधार पर इलाज की रूपरेखा बनाई जाती है।

मशीनें बनेंगी स्मार्ट: आइआइटी के निदेशक प्रो. अभय करंदीकर ने बताया कि एआइ से जांच करने की दिशा में अमेरिका समेत कुछ यूरोपीय देशों में काम शुरू हो गया है। आइआइटी कानपुर ने भी अब इस पर काम शुरू कर दिया है। आइआइटी चिकित्सीय मशीनों को स्मार्ट बनाएगा। इससे मशीनें आपस में इंटरकनेक्ट हो सकेंगी और रोगों को तुरंत सामने ले आएंगी। शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत होने पर उसका मूल कारण और निवारण तक बताने में मशीनें सक्षम रहेंगी। इसके लिए सिस्टम की प्लानिंग की जाएगी। संस्थान के रिसर्च सेंटर में प्रोटोटाइप माडल विकसित किया जाएगा जो मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा। डायग्नोसिस की मशीनें भविष्य में इस तरह से डिजाइन की जा सकेंगी।

जटिल रोगों पर होगा शोध: एसएमआरटी के लिए संस्थान ने बिल्डिंग का नक्शा और माडल तैयार करा लिया है। एसएमआरटी में 500 बेड के अस्पताल के साथ ही अलग से रिसर्च विंग बनाई जाएगी। देश ही नहीं, विदेश के कई अस्पतालों का माडल तैयार करने वाली कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली है। एसएमआरटी का शिलान्यास नवंबर में कराने की तैयारी है। इसकी कमेटी का गठन कर लिया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया गया है। जटिलतम रोगों पर यहां शोध किया जाएगा।

आइआइटी कानपुर का कैंपस • जागरण

रिसर्च विंग में होगी अत्याधुनिक तकनीक

रिसर्च विंग में टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त डाइग्नोसिस सिस्टम होगा। इसमें कैंसर, लिवर, किडनी, हृदय, फेफड़े व संक्रामक रोगों का इलाज व न्यूरो सर्जरी आदि के क्षेत्र में काम किया जाएगा। रिसर्च विंग अपग्रेड होती रहेगी।

आइआइटी निदेशक प्रो. अभय करंदीकर • जागरण

सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल बनेगा

एसएमआरटी का प्रोजेक्ट 600 करोड़ रुपये का है। इसमें पढ़ाई के लिए अलग से बिल्डिंग बनेगी, जबकि सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, रिसर्च विंग, आवासीय क्षेत्र, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं के लिए अलग भवन बनाए जाएंगे। एसएमआरटी का प्रोजेक्ट शिवली रोड पर संस्थान परिसर में बनेगा। प्रोटोटाइप बनने के बाद यहां पर क्लीनिकल ट्रायल होगा, फिर इस्तेमाल किया जाएगा। रिसर्च विंग में चिकित्सीय उपकरण भी विकसित किए जाएंगे।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

8 देश भीषण आग से जूझ रहे हैं दुनिया में। इनमें अमेरिका, रूस, तुर्की, ग्रीस, ब्राजील, इटली, स्पेन और जापान शामिल हैं। यह आग जून के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई थी, जो अब तक 1.13 करोड़ एकड़ इलाका खाक कर चुकी है।

दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना करेगी पांच दिवसीय सैन्य अभ्यास

बीजिंग, एएनआइ : चीन ने घोषणा की है कि वह क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए शुक्रवार से दक्षिण चीन सागर में पांच दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। चीन इस सैन्य अभ्यास के तहत एक बड़े क्षेत्र को नेविगेशन प्रतिबंधित क्षेत्र भी घोषित करेगा। चीन के दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने के बीच अमेरिका और अन्य देशों ने भी क्षेत्र में दबाव बनाकर रखा है।

चीन ने यह घोषणा भारत की उस घोषणा के तुरंत बाद की है, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि वह दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत सागर में अपने चार युद्धपोतों की टास्क फोर्स तैनात करेगी।

भारतीय युद्धपोत क्वाड (भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका) के मालाबार अभ्यास के अगले संस्करण में वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय अभ्यास शामिल किए जाएंगे।

कोरोना वायरस के वुहान लैब से ही बाहर आने की शंका पुष्ट

- अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा चीन की लैब का डाटा
- डब्ल्यूएचओ ने कहा, नई जांच प्रक्रिया में सहयोग करे चीन

वाशिंगटन, एएनआइ : कोविड-19 महामारी के उत्पन्न होने का स्रोत ढूंढ़ने में लगीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसा जेनेटिक डाटा मिला है, जिससे कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब में पैदा होने और वहां से बाहर आने की शंका पुष्ट हो रही है। अमेरिकी दावों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन से नई जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया है, जबकि चीन ने डब्ल्यूएचओ से कोरोना वायरस के किसी अन्य देश में पैदा होने की संभावना पर जांच करने के लिए कहा है।

अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वुहान लैब से संबंधित डाटा कहां से प्राप्त किया है। माना जा रहा है कि यह डाटा क्लाउड आधारित सर्वर नेटवर्क के जरिये अमेरिकी एजेंसियों को प्राप्त हुआ या वुहान लैब का डाटा हैक किया गया। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले इस संभावना पर प्रकाश डाला है। अमेरिकी प्रशासन के ज्यादातर अधिकारियों का मानना है कि कोविड महामारी वुहान की लैब से निकली, लेकिन चीन सरकार इस आशंका को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।

आइएएनएस के अनुसार, वह कोविड के चीन में पैदा होने की सच्चाई को नकारते हुए अन्य देशों की ओर अंगुली उठा रही है। चीन डब्ल्यूएचओ से मांग कर रहा है कि कोरोना वायरस के अन्य देश में पैदा होने की जांच की जाए। इस सिलसिले में वह अलग-अलग देशों में पैदा हो रहे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का उदाहरण भी दे रहा है।

इस बीच डब्ल्यूएचओ ने चीन से कहा है कि वह संगठन की दूसरे चरण की जांच प्रक्रिया में सहयोग करे और जांच दल को चीन आने की अनुमति दे।

वुहान लैब में 2005 से चल रहा था प्रयोग : डब्ल्यूएचओ का यह बयान तब आया है जब टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेटर माइकल मैक्कौल ने कहा है उनके पास वुहान लैब में नया कोरोना वायरस विकसित किए जाने और उसके लैब से बाहर से आने के सुबूत हैं। कोरोना वायरस को मानव शरीर के लिए ज्यादा घातक बनाने का प्रयोग वुहान लैब में 2005 से चल रहा था, 2016 में यह प्रयोग पूरा हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जांच भी इसी तरह के संकेत दे रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के आदेश पर हो रही जांच का फोकस अब इस बात पर है कि वुहान लैब से वायरस दुर्घटनावश बाहर आया या उसे साजिश के तहत बाहर लाकर फैलाया गया।

कोविड ने अमेरिका की फिर बढ़ाई चिंता

वाशिंगटन, रायटर : कोरोना महामारी ने अमेरिका की चिंता फिर बढ़ा दी है। दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महज एक माह में दैनिक मामलों में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते एक हफ्ते से रोजाना औसतन 95 हजार से ज्यादा केस मिल रहे हैं। बुधवार को दैनिक मामलों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई। अमेरिका में नए मामलों में उछाल के लिए डेल्टा वैरिएंट को कारण बताया जा रहा है।

अमेरिका में इस समय जितने नए मामले मिल रहे हैं, उनसे से करीब आधे सात प्रांतों फ्लोरिडा, टेक्सास, मिसौरी, अर्कांसस, लुसियाना, अलबामा और मिसिसिपी में पाए जा रहे हैं। इन प्रांतों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार बताई जा रही है। कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना करने वाले अमेरिका में 70 फीसद से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया है।

इटली ने दी रियायतें, उमड़े लोग : दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ अब कुछ देशों में सामान्य गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं। इटली ने इंडोर डाइनिंग, थियेटर, स्वीमिंग पूल, जिम और म्यूजियम में लोगों के आवागमन की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को राजधानी रोम में स्थित करीब 2000 साल पुराने कालेजियम में काफी भीड़ जुटी। एपी

सिडनी में भी फैला डेल्टा वैरिएंट : आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ गया है। शहर में बीते 24 घंटे में 279 नए केस पाए गए। एक दिन पहले 259 संक्रमित मिले थे।

चीन में बढ़ रहे कोरोना मरीज : समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, चीन में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। देशभर में बीते 24 घंटे में 80 नए मामले पाए गए। एक दिन पहले 85 मामले मिले थे।

तालिबान ने की अफगान राष्ट्रपति के प्रवक्ता की हत्या

गहराता संकट ▶ नमरुज प्रांत की राजधानी पर भी आतंकियों का कब्जा

गहराते संकट के बीच पूर्व उप राष्ट्रपति का वादा, तालिबान का करेंगे सफाया

काबुल, एपी : अफगानिस्तान में तालिबान संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार को तालिबान आतंकियों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता की हत्या कर दी। साथ ही, आतंकियों ने नमरुज प्रांत की राजधानी जरंज पर भी कब्जा कर लिया है। इसे किसी राजधानी पर आतंकियों का पहला कब्जा माना जा रहा है। अफगान सरकार आतंकियों के कब्जे से इन्कार कर रही है, लेकिन तालिबान ने इंटरनेट मीडिया पर शहर के प्रवेश द्वार खींची गई तस्वीरें पोस्ट की हैं।

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, तालिबान ने सरकारी मीडिया और सूचना केंद्र के प्रमुख दावा खान मेनपाल की हत्या करने की जिम्मेदारी ली है। वह राष्ट्रपति के प्रवक्ता के तौर पर भी काम करते थे। गहराते संकट के बीच, देश के पूर्व उप राष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम ने तालिबान का सफाया करने का वादा किया है। दोस्तम का मिलिशिया समूह अफगान बलों के साथ मिलकर जज्जान प्रांत में आतंकियों से लड़ रहा है।

तालिबान ने हाल में ही सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। आतंकियों ने कुछ दिन पहले ही देश के कार्यवाहक रक्षा मंत्री की हत्या का प्रयास किया था। उनके आवास पर बम से हमला किया गया था। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हुए थे।

आधे से ज्यादा जिलों पर आतंकियों का कब्जा : अमेरिकी सुरक्षाबलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। उसका यहां आधे से ज्यादा जिलों पर कब्जा हो चुका है। यह आतंकी संगठन अब प्रांतों की राजधानियों पर कब्जे के लिए हमले कर रहा है।

वहीं, कई शहरों में हजारों की संख्या में नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर तालिबान का विरोध किया और अफगान सरकार के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

ऐसे बदल रही है अफगानिस्तान की तस्वीर

150 से ज्यादा आतंकी ढेर

अफगान सुरक्षाबल भी आतंकियों के सफाए में जुटे हैं। 24 घंटे में लश्कर गाह समेत कई स्थानों पर 150 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह में अफगान बलों के अभियान में 94 तालिबान व अलकायदा आतंकी मारे गए और 16 अन्य घायल हुए। मरने वालों में तालिबान का प्रांतीय कमांडर मावलवी मुबारक भी शामिल है। इधर, जज्जान प्रांत में 40 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकी घरों में घुसकर नागरिकों को ढाल बना रहे हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत तखर की राजधानी तालोकान में अफगान वायु सेना के हवाई हमले में 13 तालिबान आतंकी मारे गए।

1,659 नागरिकों की मौत

अफगानिस्तान में इस वर्ष के पहले छह महीने के दौरान हुई हिंसा में 1,659 नागरिकों की मौत हुई है और 3,254 घायल हुए। मानवाधिकार संस्था के मुताबिक, पिछले तीन महीने में करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।

ईरान ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका का किया स्वागत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी (दाएं) से मुलाकात की। प्रेट्र

- तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति रईसी से मिले विदेश मंत्री जयशंकर

तेहरान, प्रेट्र : ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि भारत और ईरान इस क्षेत्र और विशेषकर अफगानिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त देश में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका का ईरान स्वागत करता है।

एक दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले रईसी ने जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए नया और विशेष कदम उठाना चाहिए। एक महीने के दौरान जयशंकर और रईसी की यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले सात जुलाई को रूस जाते समय जयशंकर कुछ समय के लिए तेहरान में रुके थे। उस दौरान भी उन्होंने ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति से भेंट की थी। शुक्रवार की बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समन्वय पर जोर दिया। कहा कि ईरान और भारत क्षेत्र और विशेष रूप से अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चत करने में रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। अफगानिस्तान में सुरक्षा के उपाय करने के लिए ईरान भारत की सराहना करता है। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर रईसी की यह टिप्पणी ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

भारत ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारा से धार्मिक ध्वज हटाने की निंदा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने अफगानिस्तान के पाक्तिआ प्रांत में एक गुरुद्वारा के गुंबद पर लगा सिखों का धार्मिक ध्वज उतारे जाने की निंदा की है। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि भारत का मजबूत विश्वास है कि भविष्य का अफगानिस्तान ऐसा होगा जहां अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं समेत अफगान समुदाय के सभी लोगों का हित संरक्षित रहेगा।

सूत्रों ने कहा, 'हमने निशान साहिब पर मीडिया रिपोर्ट देखी है। अफगानिस्तान के पाक्तिआ प्रांत के चामकनी में गुरुद्वारा थाला साहिब के गुंबद से निशान साहिब हटाया गया है। हम इस गतिविधि की निंदा करते हैं और भारत के इस विश्वास को दोहराते हैं कि भविष्य का अफगानिस्तान निश्चित रूप से ऐसा होगा जहां अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं समेत अफगान समुदाय के सभी लोगों का हित संरक्षित रहेगा।'

एक मई से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान पूरे अफगानिस्तान में तेजी से पांव पसारने लगा है। बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का वीजा विस्तार का आवेदन रद

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वीजा विस्तार के आवेदन को ब्रिटेन के गृह विभाग कार्यालय ने ठुकरा दिया है। हालांकि शरीफ के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार रहेगा।

नवाज शरीफ। फाइल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ (71 वर्ष) के खिलाफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दो मामले चल रहे हैं। हालांकि वह इलाज के लिए चार हफ्ते की लाहौर हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नवंबर, 2019 से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रह रहे हैं।

डान की खबर के अनुसार नवाज की पार्टी पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने खुद ही मुहम्मद नवाज शरीफ की वीजा अवधि बढ़ाने से रोकी है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है और उस अवधि तक नवाज शरीफ ब्रिटेन में ही रह सकते हैं। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज के बेटे हुसैन नवाज ने बताया कि ब्रिटेन के आव्रजन प्राधिकरण में इस फैसले के खिलाफ अपील की जा चुकी है। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नवाज शरीफ का वीजा कब तक के लिए वैध है।

अमेरिका की ईरान की नई सरकार से परमाणु वार्ता पर वापसी की अपील

- लंबे समय तक नहीं टाली जा सकती वार्ता प्रक्रिया
- अमेरिका ने इस डील पर वापसी की इच्छा जताई

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका ने ईरान में राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी के नेतृत्व में बनी नई सरकार से अपील की है कि वो 2015 में हुई परमाणु डील पर दोबारा वापसी के लिए वार्ता में शामिल हों। अमेरिका की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति रईसी ने ईरान से प्रतिबंधों को हटाने वाले किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है।

बता दें कि इब्राहीम रईसी इसी वर्ष 18 जून को देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने पांच अगस्त को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उनके शपथ लेने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारा संदेश ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी के लिए भी वही है जो उनके पूर्व के राष्ट्रपति के लिए था। अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करता रहेगा। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान की नई सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान तलाशेगी।

नेड प्राइस ने कहा कि हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि हम वियना में परमाणु डील संबंधी वार्ता पर वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान ईरान से भी अपील की कि वो भी इसमें जल्द वापसी करे, जिससे दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंच सकें।

अमेरिका का विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस (फाइल)। जागरण आर्काइव

ईरान को वातचीत की टेवल पर वापस आना चाहिए

अमेरिका ने ये भी साफ कर दिया है कि बातचीत की इस प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक के लिए रोक कर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए ईरान को बातचीत की टेबल पर वापस आना चाहिए। बता दें कि इब्राहीम रईसी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी भी तरह के कूटनीतिक प्रस्ताव का स्वागत और समर्थन करने को तैयार हैं, बशर्ते ईरान से प्रतिबंध हटते हों।

गौरतलब है कि परमाणु डील को लेकर दोनों के बीच अप्रैल से अब तक करीब छह दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब भी दोनों के बीच कई मुद्दों पर विरोधाभास जारी है, जिस वजह से किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका है। दोनों के बीच वर्ष 2015 में हुई परमाणु डील को ज्वाइंट कांप्रेहेंसिव प्लान आफ एक्शन (जकोपा) नाम से भी जाना जाता है।

टोक्यो में ट्रेन में हमलावर ने 10 लोगों को चाकू घोंपा

टोक्यो, एपी : जापान की राजधानी टोक्यों में दैनिक यात्रियों की एक ट्रेन में एक हमलावर ने चाकू मारकर 10 लोगों को घायल कर दिया। इनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह घटना ओलिंपिक खेल गांव से कुछ ही दूरी पर हुई है। वारदात के बाद आरोपित हमलावर मौके से भाग निकला, लेकिन बाद में उसे दबोच लिया गया।

जापान के एनएचके टीवी ने बताया कि हमला करने वाला अपना चाकू मौके पर ही फेंककर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे टोक्यो के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित स्टोर से गिरफ्तार कर लिया। टोक्यो में इस समय ओलिंपक खेल चल रहे हैं।

टोक्यो दमकल विभाग ने कहा कि 10 घायल यात्रियों में से नौ को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि दसवां व्यक्ति मामूली रूप से घायल था। उसे घटनास्थल पर ही प्रारंभिक उपचार देकर जाने दिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घायल हुए सभी लोग होश में थे। घटनास्थल पर पुलिस और बाकी जांच एजेंसियों की कई टीमें मौजूद हैं।

हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर पाक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को फटकारा

- कहा- मंदिर हमले में शामिल आरोपितों को तुरंत करें गिरफ्तार
- पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर में तोड़फोड़ पर इमरान का पुनर्निर्माण का वादा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उन्मादी भीड़ द्वारा हिंदुओं के मंदिर पर किए गए हमले को लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामले के उठने और भारत की चेतावनी के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने हमले के आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया है। भारत ने हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तानी राजनयिक को गुरुवार को तलब भी किया था। पाक के पीएम इमरान खान ने हमले की निंदा की है और मंदिर के पुनर्निर्माण का वादा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के पीछे शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने हिंसा भड़काने वाले लोगों को भी सलाखों के पीछे करने का आदेश भी दिया। साथ ही पाकिस्तानी शीर्ष अदालत ने सरकार को तुरंत मंदिर की मरम्मत करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलाजर अहमद ने मंदिर पर हुए हमले को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की थी।

फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

उन्होंने इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध भी की थी।

डंडे, पत्थरों व ईंटों से किया हमला : पाकिस्तान पुलिस ने बताया कि रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में भीड़ ने बुधवार को हिंदू मंदिर पर हमला किया। यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है। रहीम यार खान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) असद सरफराज ने बताया कि हमलावरों ने डंडे, पत्थर और ईंटें उठा रखी थीं। उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए देवी-देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दीं। उन्होंने बताया कि मंदिर के एक हिस्से को जला भी दिया गया। सरफराज ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हालात काबू में कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। उन्होंने कहा, रेंजर्स को बुलाया गया और हिंदू मंदिर के इर्द-गिर्द तैनात किया गया।

इमरान ने कहा-गिरफ्तारी हो सुनिश्चित : वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, 'रहीम यार खान जिले में, गणेश मंदिर पर गुरुवार को हुए हमले की सख्त निंदा करता हूं। मैंने पंजाब के आइजी (पुलिस महानिरीक्षक) से बात की है और सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा किसी पुलिस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरकार मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराएगी।' इससे पहले, राजनीतिक संचार पर खान के विशेष सलाहकार डा. शाहबाज गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि खान ने जिला प्रशासन को घटना की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अमेरिका में एक लाख ग्रीन कार्ड के बेकार होने का खतरा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में रोजगार आधारित एक लाख से ज्यादा ग्रीन कार्ड के बेकार होने का खतरा है। अगर दो माह के अंदर जारी नहीं किए गए तो इतनी बड़ी संख्या में ग्रीन कार्ड बर्बाद हो जाएंगे। इसमें हो रही देरी से भारतीय आइटी पेशेवरों में नाराजगी है। वे दशकों से इस कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड मिलने से अमेरिका में कानूनी तौर पर स्थायी रूप से बसने का अधिकार मिल जाता है। इसे स्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है।

भारतीय पेशेवर संदीप पवार ने बताया कि इस साल आप्रवासियों के लिए रोजगार आधारित कोटा दो लाख 61 हजार 500 है। आमतौर पर हर साल यह कोटा एक लाख 40 हजार होता है। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ये कार्ड 30 सितंबर तक जारी नहीं किए गए तो ये हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे।' पवार ने कहा कि अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) की मौजूदा गति से जाहिर होता है कि वे एक लाख से ज्यादा ग्रीन कार्ड बेकार कर देंगे। हाल ही में वीजा उपयोग निर्धारित करने वाले विदेश मंत्रालय के प्रभारी ने भी इसकी पुष्टि की है। इस संबंध में पूछे गए सवालों पर व्हाइट हाउस ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, अमेरिका में रह रहे 125 भारतीय और चीनी नागरिकों ने ग्रीन कार्ड को बेकार होने से बचाने के लिए एक अदालत में मुकदमा दायर किया है।

शिनजियांग में मुस्लिमों के दमन के लिए चीन ने नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति की

- लेफ्टिनेंट जनरल वांग हैजियांग तिब्बत में कर चुके हैं काम

बीजिंग, एपी : चीन ने शिनजियांग प्रांत में नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है। शिनजियांग की सीमा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से लगती है। मुस्लिम बहुल यह प्रांत पिछले कई सालों से अशांत रहा है। चीन ने यहां लाखों मुस्लिमों को आतंकवाद और कट्टरपंथ का आरोप लगा कर बंद किया हुआ है।

लेफ्टिनेंट जनरल वांग हैजियांग ऐसे वक्त में शिनजियांग के कमांडर बनाए गए हैं जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां के हालात अस्थिर हैं। यह चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन को डर है कि अफगानिस्तान का असर शिनजियांग पर भी पड़ सकता है और आतंकवाद फैल सकता है।

वांग बीती सदी के नौवें दशक की शुरुआत में वियतनाम के साथ युद्ध देख चुके हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के इलीट यूनिट में सेवा दे चुके हैं। वांग तिब्बत में पोस्टेड रहे हैं। यहां वह मूल तिब्बती आबादी के बीच सरकार विरोधी भावना को दबाने का काम कर रहे थे। तिब्बत को लेकर चीन हमेशा से सर्तक रहा है।

हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग तिब्बत दौरे पर थे। वहां उन्होंने धार्मिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले मौलिक दिशा-निर्देशों को लागू करने पर जोर दिया था। साथ ही सेना को युद्ध के लिए बेहतर तैयारी करने को कहा था।

हाल ही में तालिबान के टाप लीडर मुल्ला बरादर के नेतृत्व में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा था, जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद तालिबान ने चीन को भरोसा दिलाया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे।

चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन को उम्मीद है कि तालिबान, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ दृढ़ता से निपटेगा। बता दें कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट शिनजियांग में आजादी की लड़ाई लड़ रहा है।

विस्कानसिन के गुरुद्वारे पर गोलीबारी के पीड़ितों को बाइडन ने किया याद

वाशिंगटन, प्रेट्र : विस्कानसिन स्थित गुरुद्वारे पर नौ साल पहले एक श्वेत ने जमकर गोलीबारी कर सिखों की हत्या की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने माना कि वैश्विक महामारी के दौर में एशियाई-अमेरिकियों के खिलाफ नफरत से भरे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

पांच अगस्त, 2012 को एक बंदूकधारी श्वेत ने नस्ली हिंसा को अंजाम देते हुए सात लोगों की हत्या कर दी थी। बाइडन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में रिपोर्टर को बताया कि आज के दिन वह इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों का सम्मान करते हैं। उन्होंने एशियाई-अमेरिकी लोगों से और सिविल अधिकारों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि कोविड-19 के दौरान नफरत के कारण किए जाने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। उनके विचार से वैश्विक महामारी के कारण जो तकलीफें बढ़ी हैं, उनके कारण भी एशियाई-अमेरिकियों के खिलाफ नफरत वाले अपराधों, उत्पीड़न आदि के मामलों में इजाफा हुआ है। व्हाइट हाउस में हुई बाइडन की इस बैठक में कई भारतीय अमेरिकियों को भी आमंत्रित किया गया था।

10 लोगों को मारी थी गोली

श्रद्धांजलि सभा में शामिल एक पीड़ित ने बताया कि इसी दिन 2012 को वह अपने एक मोना सरदार मित्र के साथ गुरुद्वारे में मौजूद थे। ओक क्रीक स्थित सिख मंदिर में एक नफरत भरे घटनाक्रम में एक श्वेत ने 10 लोगों को गोली मारी थी। विस्कानसिन में उस दिन सात लोगों की जान चली गई।

कांसा नहीं, बेटियों ने जीता दिल

- ग्रेट ब्रिटेन से हारकर चौथे स्थान पर रही महिला हाकी टीम
- पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची देश की बेटियां

टोक्यो, प्रेट्र : अपने जुझारूपन और दिलेरी से इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हाकी टीम का पहला ओलिंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया। ग्रेट ब्रिटेन ने टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में भारत को 4-3 से हरा दिया। भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। वहीं, नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता जबकि रजत अर्जेंटीना के नाम हुआ।

भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही सफलता के नए मानदंडों को छू लिया था। कांस्य पदक जीतने के करीब भी पहुंची, लेकिन रियो ओलिंपिक की स्वर्ण विजेता दुनिया की चौथे नंबर की ब्रिटिश टीम ने उसके साथ करोड़ों भारतीयों का भी दिल तोड़ दिया। इससे एक दिन पहले ही भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था। भारतीय महिला टीम ने भी दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए हाफटाइम तक 3-2 की बढ़त बना ली। ब्रिटेन ने हालांकि दूसरे हाफ में जबरदस्त आक्रामक खेल दिखाते हुए दो गोल कर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम ने पांच मिनट के अंदर तीन गोल किए। गुरजीत कौर ने 25वें व 26वें मिनट में जबकि वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में गोल दागे। ब्रिटेन के लिए एलेना रायेर ने 16वें, सारा राबर्टसन ने 24वें, कप्तान होली पीयर्ने वेब ने 35वें व ग्रेस बाल्डसन ने 48वें मिनट में गोल दागे। भारतीय महिला टीम का इससे पहले ओलिंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में था जब वह चौथे स्थान पर रही थी। तब सेमीफाइनल नहीं हुआ था व छह टीमें राउंड रोबिन आधार पर खेलीं, जिनमें से दो फाइनल में पहुंची थीं।

ब्रिटेन ने अपेक्षा के अनुरूप दमदार शुरुआत करते हुए गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा व पहले क्वार्टर में कई मौके बनाए। भारतीय टीम सर्कल में गई, लेकिन मौके नहीं बना सकी। इसके अलावा मिडफील्ड में कई बार गेंद गंवाई। पहले क्वार्टर में भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने कम से कम तीन गोल बचाए। दूसरे मिनट में ब्रिटेन को मिला पेनाल्टी कार्नर बचाने के बाद 12वें मिनट में दो बार बचाव किए। दूसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने रायेर के गोल की मदद से बढ़त बना ली। कुछ मिनट बाद उसे फिर पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन गोल नहीं हो सका। लालरेंसियामी भारत के लिए गोल करने के करीब पहुंचीं, लेकिन उनकी रिवर्स हिट को मैडी हिंच ने बचा लिया। भारत को मिला पहला पेनाल्टी कार्नर भी बेकार गया। ब्रिटेन की बढ़त 24वें मिनट में राबर्टसन ने दोगुनी कर दी। एक मिनट बाद भारत को लगातार दो पेनाल्टी कार्नर मिले जिनमें से एक को गोल में बदलकर गुरजीत ने अंतर कम किया। दो मिनट बाद सलीमा टेटे बायें फ्लैंक से गेंद लेकर आईं और भारत को पेनाल्टी कार्नर दिलाया। गुरजीत ने इसे गोल में बदलकर भारत को बराबरी दिलाई। वंदना के गोल ने पहली बार भारत को 3-2 से बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में कप्तान होली पीयर्ने ने ब्रिटेन को 3-3 से बराबरी दिलाई। अंतिम क्वार्टर में बाल्डसन ने ग्रेट ब्रिटेन की ओर से चौथा गोल दागा। इसके बाद भारत को दो पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन गोल नहीं हो सका और भारत 3-4 से हार गया।

आपका पसीना करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया : मोदी

नई दिल्ली, जेएनएन : हार से दुखी भारतीय महिला हाकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उनका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। आखिरी सीटी बजने के बाद ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर रोने लगी और कोच शोर्ड मारिन तथा टीम के वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोंबार्ड उन्हें संभालते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कप्तान रानी रामपाल और पूरी टीम से फोन पर कहा, 'आप सभी लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने पिछले छह साल से बहुत पसीना बहाया है। सब कुछ छोड़कर आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को बधाई देता हूं। निराश नहीं होना है।' उन्होंने यह भी पूछा कि क्या नवनीत कौर की आंख में चोट लगी है जिस पर कप्तान रानी ने बताया कि उसे चार टांके अए हैं। उन्होंने कहा, 'उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं है ना।' उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, 'वंदना और सभी ने बहुत बढ़िया किया है। सलीमा तो कमाल कर देती है।' प्रधानमंत्री से बात करते हुए कप्तान रानी और गोलकीपर सविता पूनिया फफक पड़े। इस पर उन्होंने कहा, 'आप लोग रोना बंद कर दें। मुझ तक आवाज आ रही है। देश आप पर गर्व कर रहा है। निराश नहीं होना है। आप लोगों की मेहनत से कितने दशकों के बाद हाकी भारत की पहचान पुनर्जीवित हो रही है।' वहीं, कोच मारिन ने कहा, 'लड़कियां भावुक हो गई हैं। प्रोत्साहन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने भी इनसे कहा है कि इन्होंने पदक से बढ़कर कुछ हासिल किया है और उस पर खुश होना चाहिए।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप सभी ने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।'

ओलिंपिक में चौथे स्थान पर रहना छोटी बात नहीं : रानी

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय कप्तान रानी रामपाल ने कहा, 'हम बहुत निराश महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम पदक के इतने करीब थे। हम पिछड़ रहे थे और फिर हमने बराबरी की और हम 3-2 से बढ़त हासिल करने में भी सफल रहे। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन हां, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम कांस्य पदक नहीं जीत सके। मुझे हालांकि लगता है कि सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इसलिए मुझे टीम पर गर्व है। ओलिंपिक खेलों में खेलना और शीर्ष-चार में जगह बनाना आसान नहीं है। मुझे अब भी टीम पर गर्व है। हमने पूरे टूर्नामेंट में इतनी मेहनत की और एक साथ एक टीम के रूप में खेले।'

> एक बहुत कठिन हार थी, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया। हर एक खिलाड़ी ने अपना शत प्रतिशत दिया। हमने इतिहास बनाया है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। यह एक टीम प्रयास था। हम आज भाग्यशाली नहीं थे। **गुरजीत कौर**

> भारत की बेटियां, हमारी समर्पित खिलाड़ी। हमें आप पर गर्व है। हमारी महिला हाकी टीम ने जबर्दस्त जुझारूपन दिखाया। इससे हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। आपने रास्ता दिखा दिया है। **अनुराग ठाकुर**, खेल मंत्री

> यह हमारी महिला टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन वे आखिर तक लड़ी। उन्होंने देश का दिल जीता और हमें उन पर गर्व है। **मनप्रीत सिंह**, कप्तान, भारतीय पुरुष हाकी टीम

> दिल टूट गया, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा है। भारतीय महिला हाकी टीम का शानदार प्रदर्शन। आपने भारत में सभी को प्रेरित किया जो अपने आप में जीत है। **शाह रुख खान**, अभिनेता

50 लाख रुपये राज्य की प्रत्येक महिला हाकी खिलाड़ी को देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा से नौ महिला हाकी खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हैं

75 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के तौर पर मणिपुर सरकार अपने राज्य के पुरुष हाकी खिलाड़ी नीलाकांता शर्मा को देगी। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी भी मिलेगी

50 लाख रुपये सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को देगी झारखंड सरकार। दोनों खिलाड़ियों के पैतृक आवास पक्के मकान में तब्दील होंगे

गोलकीपर सविता पूनिया को संभालते वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोंबार्ड • प्रेट्र

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	36	26	17	79
अमेरिका	31	36	31	98
जापान	24	11	16	51
ग्रेट ब्रिटेन	18	20	20	58
आरओसी	17	23	22	62
आस्ट्रेलिया	17	6	21	44
इटली	10	10	18	38
जर्मनी	9	11	16	36
नीदरलैंड्स	9	10	12	31
फ्रांस	7	11	9	27
भारत	0	2	3	5

नोट : भारत तालिका में 66वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

मारिन ने महिला टीम का कोच पद छोड़ा

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला हाकी टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन को अपनी टीम पर गर्व है और ओलिंपिक कांस्य पदक मुकाबले में पराजय के बावजूद उन्होंने अपने खिलाड़ियों से आंसू रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है कि अपने दिलेर प्रदर्शन से पूरे देश को प्रेरित करने वाली टीम को खुश होना चाहिए। मारिन ने कहा कि ओलिंपिक खेलों में ब्रिटेन के खिलाफ मुकाबला इस टीम के साथ उनकी आखिरी जिम्मेदारी थी। इस 47 वर्षीय कोच ने मैच के कुछ घंटे बाद इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'मेरी कोई योजना नहीं है क्योंकि भारतीय महिलाओं के साथ यह मेरा आखिरी मैच था। हारने पर दुख होता है, लेकिन मैं फख्र महसूस कर रहा हूं। मुझे इन लड़कियों पर गर्व है जिन्होंने एक बार फिर अपना कौशल और जुझारूपन दिखाया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे आंसू तो नहीं पोंछ सकता। तुम्हें कोई शब्द सांत्वना नहीं दे सकता। तुमने पदक नहीं जीता, लेकिन उससे बड़ा कुछ जीता है। अपने देश को प्रेरित किया है। दुनिया ने एक अलग ही भारतीय टीम देखी और मुझे उस पर गर्व है। आम तौर पर भारतीय टीम को दो गोल से पिछड़ने के बाद 3-0 या 4-0 से हार मिलती रही है, लेकिन अब नहीं।'

नेहा को सांत्वना देती ग्रेट ब्रिटेन की गोलकीपर क्लेयर हिंच • प्रेट्र

बजरंग रीप्ले देखकर खुद हैरान होंगे

साक्षी मलिक
कलम से

बजरंग पूनिया को टोक्यो ओलिंपिक खेलों में फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किग्रा. भारवर्ग के फाइनल में न देखना दिल तोड़ने वाला है। मैं बजरंग को हाजी अलियेव के थकने के बाद उन पर हमला करने के बजाय पहले मिनट में ही आक्रमण करते हुए देखना पसंद करती। मुझे विश्वास है कि बजरंग ने अपना सौ प्रतिशत प्रयास किया होगा, लेकिन वह खुद इस बात से निराश होंगे कि उन्होंने शुरुआती गेम में ही विपक्षी को आक्रमण करने का मौका देकर अंक बटोरने दिए और 4-1 की बढ़त बनाने दी। जब आगे कभी बजरंग ओलिंपिक सेमीफाइनल का रीप्ले देखेंगे तो उन्हें हैरानी हो सकती है कि उन्होंने शुरुआती समय में ही हाजी की टांग पर हमला करने की कोशिश क्यों नहीं की। उनके प्रतिद्वंद्वी हल्के भारवर्ग से आकर इस वर्ग में खेल रहे थे और ऐसे में बजरंग के पास उनकी तुलना में अधिक ताकत और मजबूती थी। बजरंग शुरुआत से ही उन पर बढ़त बनाने की कोशिश कर सकते थे। मैंने देखा कि वह शुरुआती दो मुकाबले में भी एक जैसी रणनीति के साथ ही खेले। उन्होंने शुरुआत में रक्षात्मक रवैया अपनाया और बाद में अंक हासिल किए। शायद वह जानते थे कि उनकी बड़ी चुनौती अजरबैजान के पहलवान ही हैं।

उम्मीद है कि अब बजरंग शनिवार को कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहेंगे। वह बेहतरीन पहलवान हैं और ओलिंपिक पदक के साथ घर लौटने के पूरे हकदार हैं। शुक्रवार को उन्हें तीन मुकाबलों में लड़ते देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी फिटनेस में किसी तरह की समस्या है। मैं जानती हूं कि कुछ लोग रूस में लगी घुटने की चोट के बाद उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वह इससे पूरी तरह उबरे हुए लग रहे हैं। जब मैंने सीमा बिसला को उनका मुकाबला हारते देखा तो खुद को ये बात सोचने से नहीं रोक सकी कि दबाव किस हद तक किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। कोई भारतीय महिला ओलिंपिक पदक नहीं जीत सकी थी लेकिन मैंने इसका दबाव कभी महसूस नहीं किया।

जहां तक विनेश फोगाट की बात है तो मैंने रियो में घुटने की चोट के बाद उन्हें दर्द में देखा था और मैं आश्वस्त थी कि नंबर वन पहलवान होने के नाते वह ओलिंपिक पदक जीतने का अपना सपना पूरा कर लेंगी। अगर उनके सामने कोई चुनौती होती तो वह जापानी प्रतिद्वंद्वी की होती, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह यूरोपीयन चैंपियन वेनेसा के खिलाफ चित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि विनेश चीनी पहलवान को भी आसानी से हरा सकती थीं। मैं नहीं जानती कि क्या वो टोक्यो में हिस्सा लेते हुए रियो ओलिंपिक का दबाव लेकर चल रहीं थीं या नहीं। (टीसीएम)

गोल्फ में भारत को मिल सकता है पहली बार पदक

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलिंपिक में गोल्फ में भारत के पहले पदक की दावेदार बनी हुई हैं जिन्होंने तीसरे दौर में तीन अंडर 67 स्कोर करके दूसरा स्थान बनाए रखा है।

तीसरे दौर के दौरान शाट खेलती भारतीय गोल्फर अदिति अशोक • एएफपी

टोक्यो में शनिवार को खराब मौसम की आशंका है ऐसे में चौथे दिन के खेल को जल्दी शुरू किया जाएगा। अगर चौथे दौर (72 होल) का खेल पूरा नहीं हुआ तो तीसरे दौर (54 होल) के नतीजे पर विजेता का चयन होगा। ऐसे में अदिति रजत पदक अपने नाम कर लेंगी। वहीं, अगर फाइनल राउंड पूरा होता है तो वह स्वर्ण जीतने जीतने की प्रबल दावेदार होंगी। अदिति अगर जीतती हैं तो वह गोल्फ में पदक जीतने वाली भारती की पहली खिलाड़ी (महिला/पुरुष) होंगी। अदिति ने रियो ओलिंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वह 41वें स्थान पर थी। अदिति तीन दौर के बाद 12 अंडर 201 के स्कोर के साथ अकेली दूसरे स्थान पर है। अमेरिका की नैली कोरडा उनसे तीन स्ट्रोक्स आगे है जिन्होंने इस दौर में दो अंडर 69 स्कोर किया। न्यूजीलैंड की लीडिया को, आस्ट्रेलिया की हन्ना ग्रीन, डेनमार्क की क्रिस्टीन पेडरसन और जापान की मोने इनामी 10 अंडर 203 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

प्रियंका 17वें और भावना 32वें स्थान पर, गुरप्रीत पूरी नहीं कर सके दौड़ : भारत की राष्ट्रीय रिकार्डधारी प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में आधी दूरी तक अच्छी स्थिति में थीं, लेकिन अंत में 17वें स्थान पर जबकि हमवतन भावना जाट 32वें स्थान पर रहीं। गुरप्रीत सिंह पुरुषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल पूरी नहीं कर सके और गर्मी तथा उमस के कारण ऐंठन की वजह से नाम वापस ले लिया। वह 35 किमी की दूरी दो घंटे 55 मिनट 19 सेकेंड में पूरी करके 51वें स्थान पर थे। इसके बाद वह अलग बैठ गए और मेडिकल टीम ने उनकी मदद की। इससे भारतीय पैदल चाल खिलाड़ियों का अभियान निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ। वहीं, भारत की चार गुणा 400 मीटर पुरुष रिले टीम ने तीन मिनट 00.25 सेकेंड का समय निकालकर नया एशियाई रिकार्ड बनाया, लेकिन फाइनल में जगह बनाने में असफल रही।

बजरंग की चोट उभरी

दीपक गिजवाल • सोनीपत

पदक के दावेदारों में शामिल भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया की शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान हाजी अलियेव के खिलाफ दायें घुटने की चोट उभर गई है। उन्हें यह मुकाबला 5-12 से गंवाना पड़ा। बजरंग को लेग-डिफेंस की कमजोरी के कारण बड़े स्तर पर एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा अब वह ओलिंपिक खेलों में कांस्य पदक के लिए शनिवार को मुकाबला करेंगे।

टोक्यो ओलिंपिक से एक महीने पहले बजरंग के दायें घुटने में चोट लगी थी जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वह पूरी तरह ठीक हैं और जल्दी मैट पर दिखेंगे। घर आए बजरंग के साथी पहलवान कृष्ण ने कहा कि बजरंग बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान है, यूं हार नहीं मानने वाला। देश के लिए पदक लेकर ही लौटेगा। उसकी चोट उसे परेशान कर रही है। बजरंग की मां ओम प्यारी ने बताया कि पिछले महीने ही एक मुकाबले के दौरान बजरंग को चोट लगी थी। अब मैच के दौरान वह चोट भी उभरी है। इसके कारण बजरंग के खेल पर असर दिखा। कृष्ण का कहना है कि चोट के कारण ही बजरंग क्वार्टर फाइनल जैसा प्रदर्शन नहीं दोहराए पाए।

वहीं, सेमीफाइनल में हार के बाद बजरंग के पिता बलवान सिंह पूनिया की आंखें नम हो गई। बलवान ने कहा कि चिंता मत करो, देश खातिर मेडल त लावैगा ऐ (देश के लिए पदक लेकर आएगा)। हार जीत-खेल का हिस्सा है, कांस्य पदक जीतकर देश को निराशा से उबारेगा बजरंग। वहीं, बजरंग की मां ओमप्यारी ने कहा कि चिंता की कै बात है (चिंता मत करो) खेल में तो यो चलता रहवै सै (खेल में तो यह चलता रहता है)।

कुश्ती से पहले बजरंग के पिता ने घर में बने मंदिर में पूजा कर बजरंग की जीत की कामना की। वहीं, पहली और दूसरी कुश्ती में जीत के बाद जश्न मनाया गया।

बाबू जी को भारत रत्न भी मिलना चाहिए : अशोक ध्यानचंद

साक्षात्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पर कर दिया। सरकार के इस फैसले और अन्य मुद्दों को लेकर मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व विश्व कप विजेता भारतीय हाकी टीम के सदस्य **अशोक ध्यानचंद** से **उमेश राजपूत** ने बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

- **मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा अब खेल रत्न पुरस्कार**

- **फैसले को किस तरह से देखते है?**

-ये एक ऐसा फैसला है जिस पर सभी को गर्व होगा। ध्यानचंद साहब को जो सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था वो देर से ही सही अब मिला है। टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक ने भारतीय हाकी को एक नई ऊर्जा दी है और इसे फिर से मुख्य चर्चा का विषय बना दिया है। हाकी के प्रति इस देश के लोगों और खिलाड़ियों में एक अलग तरह की भावनाएं हैं और मैं समझता हूं कि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री के दिल में भी यही भावना आई होगी कि किस तरह एक खिलाड़ी संघर्ष के दौर से गुजरकर आगे बढ़ता है और देश का नाम रोशन करता है।

- **खिलाड़ी को तो खेल पुरस्कार मिलता ही है, लेकिन यदि वो खेल पुरस्कार भी किसी खिलाड़ी के नाम पर हो तो क्या उससे कुछ खास फर्क पड़ता है?**

-अब जब कोई खिलाड़ी देश के सबसे बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार खेल रत्न को हासिल करेगा तो उसके लिए इससे बड़ी उपलब्धि और इससे सुखद अनुभूति दूसरी कोई नहीं हो सकती।

- **आज अगर मेजर ध्यानचंद साहब हमारे बीच होते तो कैसा महसूस करते?**

-ऐसी चीजें यदि इंसान के जीते जी हो जाएं तो उसे गर्व की अद्भुत अनुभूति होती है। बाबूजी भी जब ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीतते थे तो वह भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। लेकिन, उन्होंने कभी अपना बखान नहीं किया। उन्होंने गोल नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भी कुछ बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोला। उन्होंने हमेशा अपनी या अपने छोटे भाई की उपलब्धियों को भी बहुत हल्के शब्दों में या इशारों में ही बयान किया। इसलिए मुझे लगता है कि वह यदि आज होते तो उन्हें खुशी जरूर होती, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं करते।

- **मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस और अब उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार, तो क्या अभी भी उनके लिए भारत रत्न की मांग उठनी चाहिए?**

-देखिए, ये सभी चीजें अलग हैं। इन्हें एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूरा देश उन्हें याद करता है और अब उस दिन उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये देश की उपलब्धि की बाते हैं और हमें इस पर गर्व भी है, लेकिन बाबूजी को भारत रत्न मिलना उनकी और उनके परिवार की उपलब्धि होगी।

- **ध्यानचंद परिवार ने उनके अलावा रूप सिंह, आप खुद और आपकी भतीजी नेहा सिंह जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने के अलावा जूनियर व राष्ट्रीय स्तर पर भी कई हाकी खिलाड़ी दिए, लेकिन ध्यानचंद के अलावा किसी को ना तो पद्म पुरस्कार मिला और ना किसी ने मांगा, तो क्या सरकार को ये पुरस्कार के लिए मांग करने की परंपरा खत्म कर देना चाहिए?**

-बिलकुल, ये बंद होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जब आप इस बात को लिखेंगे तो सरकार इस पर भी विचार करेगी। सरकार को विचार करना चाहिए कि इस तरह की शख्सियत जो अपने आत्मसम्मान के चलते आगे बढ़कर कुछ कह नहीं पाते या मांग नहीं कर पाते उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ करने की शुरुआत करना अपने आप में एक मिसाल होगी। बाबूजी और चाचाजी (कैप्टन रूप सिंह) दोनों ही ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। मैंने उन्हें काफी तकलीफों और परेशानियों में दौर में देखा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ध्यानचंद परिवार के पास छह ओलिंपिक पदक और तीन विश्व कप पदक हैं। यही पदक हमारी और हमारे परिवार की अगली पीढ़ी की विरासत हैं।

टोक्यो से भेजे गए दीपक के कोच

टोक्यो, एपी : भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) ने दीपक पूनिया के विदेशी कोच मुराद गैदरोव को बर्खास्त कर दिया। दीपक के कांस्य के मैच में यह रेफरी मौजूद था। उस मैच में दीपक को सैन मारिनो के माइल्स नजीम अमीन से हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकबले के बाद गैदरोव रेफरी के कमरे में गए और उनके साथ मारपीट की। यूनाइटेड विश्व कुश्ती (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने डब्ल्यूएफआइ को अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए बुलाया, जिसमें राष्ट्रीय महासंघ के सामने शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने मामले की सुनवाई के बाद गैदरोव का एक्रीडेशन रद कर दिया। वहीं, भारतीय खिलाड़ियों को जापान सरकार से खेल गांव छोड़ने और शनिवार को भारतीय दूतावास में समारोह में भाग लेने की अनुमति मिल गई।

पदक के लिए उतरेंगे नीरज

टोक्यो, प्रेट्र : भारत का एथलेटिक्स में ओलिंपिक पदक का पिछले 100 साल का इंतजार खत्म करने के लिए सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी हैं जो टोक्यो ओलिंपिक में शनिवार को पुरुषों के भाला फेंक के फाइनल में उतरेंगे।

नीरज को ओलिंपिक से पहले ही पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और इस 23 वर्षीय एथलीट ने अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करते हुए क्वालीफिकेशन में अपने पहले प्रयास में 86.59 मीटर भाला फेंककर शान के साथ फाइनल में जगह बनाई थी।

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) अब भी नार्मन प्रिचार्ड के पेरिस ओलिंपिक 1900 में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में जीते गए पदकों को भारत के नाम पर दर्ज करता है, लेकिन विभिन्न शोध तथा अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (अब विश्व एथलेटिक्स) के अनुसार उन्होंने तब ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया था। हरियाणा के नीरज पदक जीतकर इतिहास रच सकते हैं। मिल्खा सिंह व पीटी ऊषा 1964 ओलिंपिक व 1984 ओलिंपिक में मामूली अंतर से चूक गए थे।

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

कुश्ती : (पुरूषों का 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मैच), दोपहर, 3 :15 बजे
खिलाड़ी : बजरंग पूनिया

एथलेटिक्स : (पुरूष भाला फेंक फाइनल) : शाम 04 :30 बजे
खिलाड़ी : नीरज चोपड़ा

गोल्फ : (महिलाओं का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले चौथा दौर), सुबह, 03 :00 बजे
खिलाड़ी : अदिति अशोक और दीक्षा डागर

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

अगर आप हर साल अपनी कोशिशें दोगुनी कर दें, तो आपकी सफलताएं भी दोगुनी हो जाएंगी। -जेफ बेजोस

'अच्छा लीडर वह नहीं होता, जो अपने दबाव से काम कराए, बल्कि वह होता है जो अपने प्रभाव और व्यवहार से काम कराए।' सही मायने में यह लीडरशिप की सर्वोत्तम व्याख्या है। एक सफल लीडर अपनी टीम के लिए प्रिय होता है। वह न केवल सहयोगियों की मनोदशा को समझते हुए उनकी हर परेशानी का समाधान सुझाता है, बल्कि बड़ी सहजता से उनसे बेहतर प्रदर्शन भी करा लेता है। आइए जानें, कैसे बढ़ें प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर...

उपयोगी बातें

- एक प्रभावी कम्युनिकेटर या वक्ता वही होता है, जो धैर्य से पहले पूरी बात सुनता है और फिर विस्तार से सभी जिज्ञासाओं को दूर करता है।
- एक कामयाब लीडर तीन सवालों (क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है?) को अपने अंदर हमेशा समाकर चलता है और उनका हमेशा पालन भी करता है।

फोटो : इमेजेज बाजार

पहचानें अपनी क्षमता

लाइफ स्किल

मिलन सिन्हा
मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेलनेस कंसल्टेंट

मनुष्य की हार तब होती है, जब वह खुद पर यकीन करना छोड़ देता है। वास्तविकता यह है कि आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप किसी का कापी-पेस्ट वर्जन नहीं हैं। आप में असीम क्षमताएं हैं, केवल उनका समुचित उपयोग किया जाना शेष है। इस तथ्य को अच्छी तरह जान लें और मान लें तो एक अच्छी शुरुआत स्वतः हो जाएगी। दरअसल, अपनी क्षमताओं को जो पहचान लेगा और उसके अनुरूप काम करने लगेगा, सफलता का साथ उसे हमेशा मिलता रहेगा।

क्षमताओं को उपलब्धियों में तब्दील करने के लिए जरूरी है कि आप जीवन को सजगता से जिएं और इसके हर क्षण का आनंद लें। सदा सीखने की कोशिश करते रहें और खुद को हमेशा युवा ही समझें। वैसे भी रोचक तथ्य तो यही है कि मनुष्य कभी भी बूढ़ा नहीं होता, सिर्फ उसकी उम्र बढ़ती है। अगर आप खुद को तन-मन से स्वस्थ रखेंगे तो न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, बल्कि आपका जीवन भी उत्साह, उमंग और आनंद से भर उठेगा। खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए एक सरल मंत्र है। इसे आजमाकर जरूर देखें। सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले कुछ पल आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारें और एक प्यारभरी मुस्कान से खुद का अभिवादन करें। इसके बाद खुद से कई बार कहें 'आइ एम द बेस्ट', 'आइ कैन एंड आइ विल' अर्थात मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इससे न सिर्फ आपको अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होगी, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ेगा और विचार भी बेहतर बनेंगे। दरअसल, मन को जैसा समझाएंगे, मानस भी वैसा बनेगा और व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा।

एक और दिलचस्प बात। संघर्ष और सफलता दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और करीब-करीब साथ ही चलते हैं। अगर हम दुनिया के किसी भी सफलतम व्यक्ति का इतिहास उठाकर देखें तो पायेंगे कि उन्होंने जीवन में संघर्ष का मार्ग कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी असफलता से घबराए। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप असफलता से बिना डरे, संघर्ष का दामन थामे रहें तो सफलता ज्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रह सकती है।

(hellomilansinha@gmail.com)

नेतृत्व की सही राह

टर्निंग प्वाइंट

डा. विवेक बिंद्रा
मोटिवेशनल स्पीकर एवं सीईओ, बड़ा बिजनेस

लीडरशिप की क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम, एम्पलायी और अपने लोगों का हमेशा प्रिय होता है, क्योंकि वह अपने लोगों की मनःस्थिति को समझते हुए उनकी हर परेशानी का सही समाधान भी निकालता है। अच्छी लीडरशिप के गुणों वाला व्यक्ति हमेशा व्यवसायिक तौर पर उन्नति करता है और युवाओं के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। लेकिन कोई भी युवा, एम्पलायी या सामान्य व्यक्ति आखिर लीडरशिप के बेहतरीन गुणों को अपने अंदर किस तरह विकसित कर सकता है? आइए जानें, उन लीडरशिप स्किल्स के बारे में, जो किसी व्यक्ति में लीडरशिप के गुणों को विकसित करने में मददगार हो सकते हैं:

कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण गुण: साहस और विचारों के बीच कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यह तभी संभव हो पाता है, जब उसे अपनाने वाला व्यक्ति कम्युनिकेशन के सभी गुणों को भली प्रकार से समझता हो यानी हमें कभी-कभी सामने वाले व्यक्ति की कुछ अनकही बातों को भी सुनना और समझना पड़ता है। ऐसे में प्रभावी कम्युनिकेटर या वक्ता वही होगा, जो धैर्य से पूरा वर्णन सुनेगा और फिर विस्तार से सभी जिज्ञासाओं को दूर करेगा। वार्तालाप के बीच में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दरअसल, जब दो व्यक्ति एक साथ बोलते हैं, तो इससे कम्युनिकेशन में समस्या होती है। लेकिन जब एक व्यक्ति सुनता है और दूसरा बोलता है, तो आसानी से किसी भी परेशानी के समाधान को तलाश लिया जाता है और सभी सवालों के जवाब भी पा लिये जाते हैं। कारोबारी दृष्टि से इस गुण की व्याख्या अगर की जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण गुण है, जिसे युवाओं को अपने भीतर शामिल करना चाहिए।

लीडरशिप का एमसीडी माडल (मैनेजिंग पावर, कोचिंग और डेलीगेटिंग): एक अच्छे लीडर की क्या परिभाषा होती है? वैसे, इसे लेकर हम सभी की अपनी-अपनी अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन एक अच्छा और कुशल लीडर वही है, जो लीडरशिप के कुछ खास गुणों को अपने अंदर समाकर चलता है और उनका हमेशा पालन भी करता है। लीडरशिप के गुणों में तीन सवालों का उत्तर बखूबी छिपा होता है और ये तीन सवाल हैं-क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है? इन तीनों सवालों के जवाबों को व्यवस्थित करना हमें आना चाहिए, जैसेकि:

मैनेजिंग पावर: लीडरशिप में मैनेजिंग पावर अधिक काम आती है, क्योंकि लीडरशिप चाहे बिजनेस में हो या फिर अन्य स्थानों पर, मैनेजिंग क्षमता का होना एक अनिवार्य शर्त होती है। मैनेजिंग गुण ही हमें सभी क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करवाता है। हमें आखिर कब और क्या करना है? इस सवाल के जवाब की तलाश इसी चरण के दौरान करनी पड़ती है। मैनेजिंग पावर ही काम में होने वाली गलतियों को भी पहचानने का काम करता है और फिर उन्हें सुधार कर अगली कड़ी पर काम किया जाता है।

कोचिंग: मैनेजिंग पावर के बाद बारी आती है कोचिंग की। इस चरण में हमें कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अगर हम एक एम्पलायी के रूप में काम करते हैं, तो यह स्वतंत्रता हमें हमारे कोच द्वारा दी जाती है और अगर हम एक बिजनेस लीडर के तौर पर टीम को संभालने का काम करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें वही स्वतंत्रता अपनी टीम को भी देनी चाहिए। काम में मिली स्वतंत्रता को ही कोचिंग कहा जाता है, जिसमें हम लगातार अभ्यास के दम पर काम में महारत हासिल करते हैं।

डेलीगेटिंग: मैनेजिंग पावर और कोचिंग के बाद डेलिगेटिंग के तहत हमें काम की प्रैक्टिस के बजाय जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करना होता है, जो भी हमने ट्रेनिंग में सीखा है, उस दक्षता को काम में इस्तेमाल करने के साथ ही नवीनता लाकर एक मिसाल के रूप में पेश करना होता है।

टैलेंट प्रोग्रेशन माडल

बिजनेस माडल के इस चरण में स्मार्ट माडल पर काम किया जाता है। इस माडल के माध्यम से टीम लीडर अपनी टीम के निपुण कर्मचारी की पहचान कर उसके कौशल का सदुपयोग करने का काम करता है। कुल मिलाकर, अच्छा लीडर वही है, जो कर्मचारी की दक्षता और उसकी स्किल्स को पहचान कर उसमें निखार लाए और उसे आगे बढ़ाने का काम करे। जाहिर है जब कर्मचारी अपनी तरक्की होते हुए देखता है, तो वह भी कंपनी के प्रति ईमानदार बनता है और गंभीरता के साथ काम करता है। इसी माडल को टैलेंट प्रोग्रेशन माडल कहा जाता है। यही माडल आगे चलकर हमारी उन्नति का रास्ता बनाता है, हमें कामयाबी दिलाता है, जो बाद में दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है।

सफलता उम्र की मोहताज नहीं

सक्सेस मंत्रा

यशराज भारद्वाज
संस्थापक/सीईओ, जेनिथ वाइपर्स ग्रुप

जेनिथ वाइपर्स ग्रुप के सह-संस्थापक एवं सीईओ यशराज भारद्वाज रिसर्च एवं इनोवेशन में देश को वैश्विक पहचान दिलाना चाहते हैं। इन्होंने 'पेटोनिक इंफोटेक' नाम से भी एक कंपनी शुरू की है, जो पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को कंसल्टेंसी देती है। हाल ही में कंपनी ने एचएएएस स्कूल आफ बिजनेस (कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले) के साथ मिलकर 'ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन' लांच किया है, जो यूनिवर्सिटी में होने वाले रिसर्च को समाज के हित में उपयोग करने के लिए काम करेगी। कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हो चुके यशराज कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। हम भी इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कम उम्र में जोखिम लेने के कारण आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन इससे घबराने की बजाय अपना विश्वास कायम रखना होता है। एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमती है।

यशराज की बचपन से ही क्रिकेट एवं विज्ञान में रुचि थी। विज्ञान की किताबें दिलचस्पी लेकर पढ़ते थे। साथ ही, नेशनल ज्योग्राफी एवं डिस्कवरी जैसे चैनल नियमित रूप से देखा करते थे। वह बताते हैं, इससे सातवीं कक्षा से ही रिसर्च के प्रति रुझान बढ़ता चला गया। लेकिन आगे चलकर जब रिसर्चर के तौर पर समस्याओं से सामना हुआ, तो हमने 'जेनिथ वाइपर्स' नाम से एक आर्गेनाइजेशन शुरू किया, जो स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित करता था।

होमवर्क करके आए उद्यमिता में: यशराज एवं युवराज दोनों जुड़वा भाई एंटरप्रेन्योर से पहले खुद को एक इनोवेटर मानते हैं। यशराज बताते हैं, हमें बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। कारोबार कैसे विकसित करते हैं, रेवेन्यू माडल कैसे बनाते हैं, इन सबकी जानकारी नहीं थी। न ही कोई मेंटर था। कई मुद्दों पर हम भाइयों के विचार नहीं मिलते थे। इसलिए प्रयोग करने के बाद उसके परिणाम को देखते हुए साझा फैसले लेते थे। हमने दुनियाभर के प्रतिष्ठित उद्यमियों की केस स्टडी का अध्ययन किया। एक समस्या को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझकर उसका हल निकालने की कोशिश की। आसपास के लोगों से सीखा।

प्रतिस्पर्धा से नहीं लगता डर: यशराज का कहना है कि छोटी आयु में उपलब्धियां एवं सम्मान मिलने से कभी-कभी अति-उत्साही होने का खतरा रहता है। लेकिन माता-पिता इसका ध्यान रखते हैं कि हमारे कदम जड़ों से जुड़े रहें। उन्होंने सिखाया है कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे तरक्की हासिल की जा सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा से डर नहीं लगता है। वर्तमान में जीना पसंद करता हूं और अपनी कंपनी के विजन पर पूर्ण विश्वास है। उसके साथ कोई समझौता नहीं करता। मैं उम्र को महज एक संख्या मानता हूं।

बातचीत : अंशु सिंह

रिसर्च के साथ इनोवेशन

अब तक 36 रिसर्च प्रोजेक्ट करने के अलावा यशराज एवं उनके जुड़वा भाई युवराज ने करीब 15 पेटेंट्स फाइल किए हैं। स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने 'बाजरा प्यूरीफायर' बनाया है, जिसमें बाजरे की मदद से नदी जल के रासायनिक और जहरीले तत्वों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, आल इन वन मेडिकल असिस्टेंस मशीन (पोर्टेबल डिवाइस) विकसित की है, जिससे इंसानों की 11 प्रकार की शारीरिक जांच एक साथ की जा सकती है।

स्मार्ट तैयारी का वक्त

नाबार्ड परीक्षा-2021

अनुज जिंदल
सीईओ, अनुज जिंदलडॉटइन

नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा ग्रेड ए और बी अधिकारी पदों के लिए कुल 162 रिक्तियों के लिए परीक्षा अगस्त 2021 के आखिरी सप्ताह से सितंबर 2021 के पहले सप्ताह के मध्य आयोजित होनी है। नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों पद देश की बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठित नौकरियों में से हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों परीक्षाएं आनलाइन आयोजित की जाती हैं। चयन प्रक्रिया में तीन राउंड होते हैं। पहला राउंड प्रारंभिक परीक्षा (आनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा) का है। दूसरा और तीसरा राउंड क्रमशः मुख्य परीक्षा (आनलाइन वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक परीक्षा) तथा साक्षात्कार का है। फिलहाल, परीक्षार्थियों के पास पहले राउंड की तैयारी को धार देने के लिए कुछ वक्त बचा हुआ है।

तैयारी की रणनीति: नाबार्ड ग्रेड ए 2021 परीक्षा को पास करने के लिए रणनीतिक और नियोजित तैयारी की आवश्यकता होती है। इसलिए तैयारी करते समय यह न सोचें कि आपको एक विषय के रूप में कृषि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बस, इसकी बुनियादी बातें जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों परीक्षाओं की पहले और दूसरे चरण की परीक्षाएं एक समान होती हैं। इसलिए जब आप एक की तैयारी करते हैं, तो दूसरे की भी साथ में होती रहती है। जहां तक रणनीति का सवाल है, तो दूसरी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने से पैटर्न को जानने में आपको अच्छी मदद मिलेगी। इसके अलावा, अभी आप परीक्षा की तारीख से पिछले तीन-चार महीनों के करेंट अफेयर्स को कवर करें। वैसे, जनवरी 2021 से करेंट अफेयर्स को कवर करना ज्यादा उचित रहेगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक योजना बनाएं और उसके अनुसार लगातार तैयारी करते रहें। समसामयिक मामलों की कवरेज के लिए सप्ताहांत को सुरक्षित रखते हुए क्वांट्स, रीजनिंग और अंग्रेजी के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें।

कुल मिलाकर, अभी ध्यान भटकाने से बचें और माक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाने का प्रयास करें। माक टेस्ट विषयों के अलग-अलग कठिनाई स्तरों के प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे।

कवर किए जाने वाले विषय: भारत में मत्स्य पालन, भारत में पशुपालन, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, एग्रोनामी, मृदा विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, आर्थिक योजना की भूमिका, गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन, सिंचाई प्रबंधन, औद्योगिक-श्रम नीति तथा राजकोषीय नीति पर विशेष ध्यान दें।

फोटो : इमेजेज बाजार

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 7 अगस्त, 2021 शनिवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
भद्रा: प्रातः 06:56 बजे तक।

मेष: बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।

वृष: शुक्र, मंगल और बुध की युति आर्थिक रूप से प्रगति में सहायक होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

मिथुन: किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी।

कर्क: आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सफलता से अहंकार आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

सिंह: किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान, किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।

कन्या: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।

तुला: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

वृश्चिक: शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

धनु: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

मकर: गृह कार्य में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ: शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी।

मीन: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी।

कल 8 अगस्त का पंचांग

कल का दिशाशूल: पश्चिम।
पर्व एवं त्योहार: हरियाली अमावस्या, स्नानदान की अमावस्या।
विशेष: बुध मघा नक्षत्र।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तत्पश्चात् प्रतिपदा पुष्य नक्षत्र तत्पश्चात् आश्लेषा नक्षत्र व्यतिपात योग तत्पश्चात् वरियान योग कर्क में चंद्रमा।

वर्ग पहेली-1660

बाएं से दाएं
1 अनुचर, पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला (4)।
3 [illegible] (5)।
6 किसी के शरीर पर [illegible] (4)।
8 [illegible] (3)।
9 प्रकाशित होना, [illegible] (5)।
11 पार्वती का पुत्र (4)।
12 [illegible] (4)।
16 बिना प्रयोजन का, जिसकी कोई जरूरत न हो (5)।
17 रहने का घर (3)।
18 [illegible] (4)।
20 [illegible] (5)।
21 [illegible] (4)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (5)।
2 [illegible] (3)।
3 [illegible] (4)।
4 [illegible] (2,2)।
5 [illegible] (4)।
7 [illegible] (2,3)।
10 [illegible] (5)।
13 [illegible] (2,1,2)।
14 [illegible] (4)।
15 [illegible] (4)।
16 [illegible] (4)।
19 [illegible] (3)।

कल का हल

चिं	ह	चिं	हा		सि	र	ख	पा	नों
रा		म			ह				जा
ग		नी	ला	ह	र		चि	ल	व
दा			छि		नों	नि	र		न
न	फा	सौं	त				च		
		च				औ	न	ना	हीं
कें		मु	ल	नों		हा			मी
तों	ल	च		रों	श	ना	हूं		ष
त्म				चि			मा		र
कें	ल्प	ना	तौ	त		औ	न	म	ना

जागरण सुडोकू-1660

1			4					6
	3		2		7		4	
9				1		2		
	1		6				2	
3				2	5		1	4
		6	9				5	
		1				5		2
	8		7	6	2		9	
2				5				8

कल का हल

4	6	1	9	8	7	3	2	5
5	8	3	6	4	2	7	9	1
9	2	7	5	3	1	4	8	6
3	4	8	7	5	6	2	1	9
2	9	5	8	1	3	6	4	7
1	7	6	4	2	9	8	5	3
7	1	9	2	6	8	5	3	4
6	5	2	3	9	4	1	7	8
8	3	4	1	7	5	9	6	2

मौसम

हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी।

कल पढ़ें

इंटरनेट आडियो एप्स का बढ़ा क्रेज

इंटरनेट आडियो चैट एप क्लबहाउस तेजी से लोकप्रिय हुआ है। ये एप्स उन लोगों के लिए एक प्लेटफार्म बनकर उभर रहे हैं, जो फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्म के इतर नये विकल्प की तलाश में हैं। जानेंगे [illegible] इंटरनेट आडियो प्लेटफार्म के बारे में...

आटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर का हुआ निर्माण

1944 में आज ही हार्वर्ड और आइबीएम ने मार्क1 कंप्यूटर का निर्माण किया। इसे आटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। यह 55 फीट लंबा, आठ फीट ऊंचा और पांच टन भारी था। यह विश्वसनीय गणना के साथ ही लगातार काम कर सकता था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपरेशन डेजर्ट शील्ड का आदेश दिया

1990 में आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज एच डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ आपरेशन डेजर्ट शील्ड का आदेश दिया था। कुवैत पर इराक के दो अगस्त के हमले के बाद यह कदम उठाया गया था। 1991 में अमेरिकी सेना ने 38 देशों के साथ इस आपरेशन को पूरा किया था।

भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन

भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का जन्म आज ही 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। आइपीएस में चयन के बावजूद यूनेस्को की एग्रीकल्चर रिसर्च फेलोशिप को तरजीह दी और नीदरलैंड चले गए। वहां से पीएचडी के बाद भारत लौटे। 1966 में मैक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों से मिलाकर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज तैयार किए। इन बीजों ने ही देश में हरित क्रांति की नींव रखी। उन्हें 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।

इधर-उधर की

कार को बना दिया आग उगलने वाला ड्रैगन

कार की हेडलाइट से निकलती हैं आग की लपटें • इंटरनेट मीडिया

मास्को, एजेंसी : फिल्मों में आग उगलती गाड़ियां तो आपने खूब देखी होंगी। अब रूस के मैकेनिक वेहान माइकलिन ने ऐसा ही अजूबा किया है। माइकलिन ने अपनी कार को मोडिफाई कर उसे आग उगलने वाली गाड़ी बना दिया है। कार की दोनों हेडलाइट से आग की लपटें निकलती हैं। उन्होंने इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला है, जिसमें वह कार में बैठकर उसकी हेडलाइट से आग फेंकते नजर आते हैं। माइकलिन ने इसे ड्रैगन नाम दिया है। वह इससे पहले आठ पैरों पर चलने वाली कार भी बना चुके हैं। आने वाले दिनों में उनका इरादा अपनी ड्रैगन कार से एक अन्य कार को जलाने का करतब दिखाने का है। इंटरनेट मीडिया पर उनकी इस ईजाद के खूब चर्चे हैं।

व्यायाम बढ़ाते शब्द सीखने की क्षमता

आया सामने ▶ यूनिवर्सिटी आफ डेलावेयर के शोधकर्ताओं के अध्ययन का निष्कर्ष

छह से 12 साल के बच्चों पर किया गया शोध

वाशिंगटन, एएनआइ : आप यदि अपने बच्चों में शब्द सीखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो एक और तरकीब जानिए। यूनिवर्सिटी आफ डेलावेयर की शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि बच्चे यदि व्यायाम करें तो शब्द सीखने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

यह अध्ययन जर्नल आफ स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक, बच्चों के शब्द सीखने की क्षमता पर व्यायाम के प्रभाव को लेकर यह पहला अध्ययन है।

इसके तहत छह से 12 वर्ष के बच्चों को नए शब्द सिखाने से पहले तीन काम कराए गए- पहला तैराकी, दूसरा क्रास फिट एक्सरसाइज और शीट कलरिंग। पाया गया कि जिन बच्चों ने तैराकी की, उनमें शब्द सीखने की सटीकता अन्य बच्चों की

तैराकी के हैं ज्यादा फायदे। फाइल/इंटरनेट मीडिया

तुलना में 13 फीसद अधिक थी। यह शोध मैडी प्रुइट की अगुआई में किया गया। प्रूइट खुद भी कालेज के दिनों में तैराक रह चुकी हैं और अब क्रास फिट क्लास भी लेती हैं।

व्यायाम से मस्तिष्क में बढ़ता है खास प्रकार का प्रोटीन : वह बताती हैं कि मस्तिष्क का मोटर मूवमेंट नए शब्द की इनकोडिंग में मदद करता है। माना जाता है कि व्यायाम के कारण मस्तिष्क में पाए जाने वाले न्यूट्रोफिक फैक्टर (एक प्रकार का प्रोटीन) का स्तर बढ़ जाता है। इसे मस्तिष्क के क्रियाकलापों का चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि तैराकी और क्रास फिट एक्सरसाइज (जिम में किए जाने वाले व्यायाम) के कारण फर्क क्यों आता है? इसके बारे में प्रूइट का कहना है कि हर व्यायाम मस्तिष्क से ऊर्जा की मांग करता है। तैराकी एक ऐसी गतिविधि (एक्टिविटी) है, जिसे बच्चे बिना कुछ सोचे-विचारे या निर्देश के बिना ही पूरी कर लेते हैं। मतलब यह स्वतः ही हो जाता है, जबकि क्रास फिट एक्सरसाइज उनके लिए नया था। इसलिए बच्चों को उसके तौर-तरीके सीखने पर ध्यान देना होता है, जिसके लिए मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

प्रूइट ने शोध अपनी पढ़ाई के दौरान एक प्रोजेक्ट के तहत किया था और साल 2020 में स्नातक किया। अभी वह साउथ कैरोलिना में एक प्राइमरी स्कूल में स्पीच लैंग्वेज पैथोलाजिस्ट के तौर काम करती हैं, जहां अपने अध्ययन के निष्कर्षों को व्यावहारिक तौर पर आजमा रही हैं।

वह बताती हैं, मेरी कक्षा विरले ही कमरे में होती है। मैं बच्चों को अक्सर मैदान में या स्कूल के आसपास टहलने के लिए ले जाती हूं।

प्रूइट की सलाहकार और अध्ययन की सहलेखक व डिपार्टमेंट आफ कम्युनिकेशन साइंस एंड डिसआर्डर की असिस्टेंट प्रोफेसर जियोवाना मोरिनिक के मुताबिक, अभी तक अधिकांश शोधों में व्यायाम को स्वस्थ जीवनशैली के रूप में परखा गया है। इसे भाषा सीखने के स्तर नहीं देखा गया। अब आगे उम्मीद है कि अन्य शोधकर्ता भी इस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाएंगे।

मोरिनिक ने बताया कि वे इस अध्ययन को लेकर इसलिए भी उत्साहित थीं कि इसका इस्तेमाल डाक्टर, देखभाल करने वाले तथा प्रशिक्षक अपनी प्रैक्टिस में कर सकेंगे। यह साधारण सी बात है। इसमें कुछ भी असामान्य या असाधारण नहीं है। लेकिन इसके निष्कर्ष वाकई मददगार हैं।

फिल्म रिव्यू

★★★

डायल 100

प्रमुख कलाकार : मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता, साक्षी तंवर
निर्देशक : रेंसिल डिसिल्वा
अवधि : एक घंटा 44 मिनट
प्रसारण प्लेटफार्म : जी5

बदले व इंसाफ के बीच अटकी कहानी

क्राइम थ्रिलर फिल्मों का डिजिटल प्लेटफार्म पर बोलबाला है। इस कड़ी में रेंसिल डिसिल्वा निर्देशित फिल्म 'डायल 100' भी जी5 पर रिलीज हो गई है। कहानी शुरू होती है मुंबई की तूफानी बरसात से। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर निखिल सूद (मनोज बाजपेयी) की इमरजेंसी कंट्रोल रूम में नाइट शिफ्ट होती है। उसी दौरान सीमा पालव (नीना गुप्ता) का फोन आता है, जो आत्महत्या करने की बात करती है। फिर उसके सुर बदलते हैं और वह एक कत्ल करने का जिक्र करने लगती है। इसी बीच निखिल की पत्नी प्रेरणा उसे फोन करके बेटे के देर रात घर से बाहर जाने को लेकर चिंता जताती है।

एक तरफ निखिल अपनी पारिवारिक जिंदगी की कश्मकश से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा की कॉल कहीं न कहीं उसके परिवार से जुड़ती जाती है। आगे कहानी में सस्पेंस है। 'कुर्बान', 'उंगली' जैसी फिल्में और '24' जैसा थ्रिलर शो का निर्देशन कर चुके रेंसिल डिसिल्वा इस जोनर के अनुभवी निर्देशक हैं। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले भी लिखा है। फिल्म का पहला दस मिनट वाकई बहुत रोमांच पैदा करता है, लेकिन थ्रिलर तब तक ही रोमांच पैदा कर सकता है, जब तक उसमें सस्पेंस बना रहे। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पटकथा और स्क्रीनप्ले दोनों ही इस रोमांच को पैदा नहीं कर पाते। वहां से फिल्म बोझिल हो जाती है। हिट एंड रन मामला, ड्रग्स का एंगल, पारिवारिक कश्मकश, बदला आदि बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में कहानी से रिश्ता छूट जाता है। माता-पिता अपने परिवार को बचाने के लिए या बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इस पर कई फिल्में बनी हैं। इस फिल्म में ताजगी की कमी खलती है।

पुलिस इमरजेंसी कंट्रोल रूम जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में किसी का वायर काट देना, गर्लफ्रेंड पर जासूसी करने के लिए पुलिस नेटवर्क को हैक करने जैसे प्रसंग कमजोर रिसर्च की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कंट्रोल रूम में पुलिस वालों के वड़ा-पाव खाने के दौरान की बातचीत मजेदार लगती है। फोन पर नीना और मनोज के किरदार के बीच की बातचीत रोमांच लाती है। एक मजबूर पुलिसकर्मी और पिता के किरदार में मनोज बाजपेयी विश्वसनीय लगे हैं। साक्षी तंवर जैसी अनुभवी कलाकार की प्रतिभा का फिल्म में समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। नीना गुप्ता निगेटिव किरदार में जंची हैं। उन्होंने बेटे को खो देने वाली मां के किरदार का दर्द और गुस्सा अपने अभिनय से दर्शाया है। फिल्म का संवाद यह इंसाफ नहीं है, बदला है..., बस लाइनों में कैद होकर रह जाता है, क्योंकि उस बदले का मकसद बहुत पेचीदा है, इसलिए सीन में भी वह गंभीरता नहीं नजर आती।

प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

कोरोना में काम आ सकती है ब्लड फैट कम करने की दवा

अनुसंधान

इलाज के नए विकल्प की उम्मीद। फाइल फोटो

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले के लिए प्रभावी उपचारों की तलाश के साथ ही मौजूदा दवाओं में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कवायद में जुटे शोधकर्ताओं को ब्लड फैट कम करने के काम में आने वाली एक दवा में उम्मीद दिखी है। उनका दावा है कि इस दवा से कोरोना संक्रमण को 70 फीसद तक कम किया जा सकता है। यह ओरल दवा रक्त में वसायुक्त पदार्थों के असामान्य स्तरों के इलाज में काम आती है।

ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की अगुआई वाली टीम के अनुसार, लैब में मानव कोशिकाओं पर किए गए परीक्षण में पाया गया है कि फेनोफाइब्रेट और इसका सक्रिय रूप फेनोफाइब्रिक एसिड कोरोना संक्रमण को काफी हद तक कम कर सकता है। इस अध्ययन से जुड़े इतालवी शोधकर्ता एलिसा विसेंजिक ने कहा, 'हमारे नतीजों से जाहिर होता है कि फेनोफाइब्रेट दवा कोरोना के गंभीर लक्षणों को कम करने और इस वायरस के प्रसार को रोकने में काम आ सकती है।' यह दवा किफायती और सुरक्षित होने के साथ ही दुनियाभर में उपलब्ध है। इससे खासतौर पर गरीब देशों को मदद मिल सकती है। अगर यह दवा क्लिनिकल ट्रायल में खरी पाई जाती है तो उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी जाती है। -प्रेट्र

फोटो से हो सकेगी कैंसर की पहचान

नलिनी रंजन, पटना

▶ पटना आइआइटी की छात्राओं ने ईजाद की नई तकनीक

▶ देशभर में हुए आनलाइन हैकथान में प्रोजेक्ट को मिला पहला स्थान

कैंसर की पहचान अब आम मरीज भी कैंसर की आशंका वाले अंग की तस्वीर या 'जांच रिपोर्ट' पोर्टल पर डाल कर आसानी से कर सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), पटना से इंटर्न कर रही चार छात्राओं ने यह तकनीक ईजाद की है। छात्राओं के आइडिया को बीते मई में हुए हैकथान में प्रथम स्थान मिला था।

पुरस्कार में मिली राशि से छात्राएं शांभवी, श्रुति मिश्रा, राशि अग्रवाल एवं वृद्धि लालवानी संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे रही हैं। आइआइटी के मेंटर प्राध्यापक श्रीपर्णा साहा सहित कई टीचर उनका सहयोग कर रहे हैं। इस वेब पोर्टल पर डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग किया गया है।

इससे स्तन, त्वचा और गर्भाशय के कैंसर का आसानी से पता चल जाता है। त्वचा कैंसर के मामले में कैंसर की आशंका वाले शरीर के हिस्से की तस्वीर, जबकि अन्य मामलों में मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे रिपोर्ट की तस्वीर के आधार पर बीमारी की जानकारी मरीजों को दे दी जाती है।

एम्स में होगा प्रायोगिक परीक्षण : इस प्रोजेक्ट के प्रायोगिक परीक्षण का एक चरण एम्स पटना में होगा। एम्स पटना में इस वेब पोर्टल की मरीजों के रिकार्ड के साथ एक्यूरेसी चेक की जाएगी। यदि एक्यूरेसी 95 फीसद से अधिक होती है तो यह तकनीक आमजन के लिए वरदान साबित हो सकती है।

रोग की पहचान और उपचार में देरी की समस्या होगी खत्म

सामान्य तौर पर आरंभिक चरण में कैंसर की पहचान नहीं हो पाती है। इससे उपचार में देर हो जाती है। इस समस्या के निदान में इंजीनियरिंग छात्राओं का यह प्रयोग बेहद अहम साबित होगा। इस पोर्टल में डीप लर्निंग तकनीक से स्तन, त्वचा और गर्भाशय कैंसर के फैलाव का भी पता किया जा सकेगा। इस संबंध में पटना एम्स की रेडिएशन आंकोलाजी विभाग की अध्यक्ष डा. प्रीतांजली सिंह ने कहा कि पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग कर रोग का पता लगाने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने मरीजों ने पोर्टल का उपयोग किया। यदि पोर्टल की एक्यूरेसी सही साबित हुई तो मरीजों के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। एम्स के पास प्रस्ताव आने पर शोध को आगे बढ़ाने में हरसंभव मदद दी जाएगी।

स्क्रीन शॉट

...तो भूमि होंगी शाहिद के अपोजिट

अली अब्बास जफर की फिल्म में भूमि हो सकती हैं कास्ट। इंस्टाग्राम

बीते दिनों आई खबरों में कहा गया था कि अली अब्बास जफर अपनी अगली फिल्म की तैयारी में हैं। यह विदेशी फिल्म की रीमेक होगी। फिल्म में शाहिद कपूर प्रमुख भूमिका में होंगे। इस फिल्म की इस साल के अंत तक शूटिंग शुरू होने की संभावना है। इस फिल्म की अभिनेत्री को लेकर भी खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म में शाहिद के अपोजिट भूमि पेडणेकर होंगी। सूत्रों के मुताबिक फिल्म मेकर्स भूमि को फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। उसके लिए भूमि से बात हो रही है। भूमि और शाहिद ने इससे पहले कोई फिल्म साथ में नहीं की है। दोनों की जोड़ी पर्दे पर नई दिखेगी। शाहिद फिलहाल राज एंड डीके की अनाम वेब सीरीज की शूटिंग पूरी करने में लगे हैं। उसमें उनके साथ राशि खन्ना और विजय सेतुपति प्रमुख भूमिका में हैं। उसके अलावा वह अपनी फिल्म जर्सी की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। उसमें उनके अपोजिट मृणाल ठाकुर हैं। वहीं भूमि पेडणेकर ने हाल ही में अपनी फिल्म बधाई दो की शूटिंग पूरी की है। उसके अलावा आनंद एल राय के निर्देशन में बनी रक्षा बंधन और शशांक खेतान की फिल्म में विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के साथ नजर आएंगी।

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में आने वाला है सात साल का लीप

टेलीविजन पर पीरियड ड्रामा शोज को खासा पसंद किया जाता है, तभी शो की कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब सोनी एंटरटेनमेंट पर चल रहे शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में सात साल का लीप आने वाला है, यानी कहानी सात साल आगे बढ़ जाएगी। रानी अहिल्याबाई होल्कर की जीवन यात्रा को दिखाने वाले इस शो में उनका युवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस लीप में अहिल्याबाई की जिंदगी का वो सुनहरा अध्याय दिखाया जाएगा, जिसमें वो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए और समाज के रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते हुए भारतीय इतिहास की सबसे कुशल शासकों में से एक बनीं। अभिनेत्री एतशा संझगिरी को युवा अहिल्याबाई होल्कर का रोल निभाने के लिए चुना गया है। एतशा मराठी टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। वह कहती हैं कि मैं खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं कि मुझे भारतीय इतिहास की सबसे श्रेष्ठ महिला शासकों में से एक रानी अहिल्याबाई होल्कर की भव्य विरासत प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मेरे लिए यह सपना सच होने जैसा है। शो में अहिल्या के पति खंडेराव होल्कर की भूमिका के लिए एक्टर किंशुक वैद्य को चुना गया है। अहिल्याबाई होल्कर के जीवन का नया अध्याय 16 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर शुरू होगा।

युवा अहिल्याबाई होल्कर का किरदार निभाएंगी एतशा संझगिरी। सोनी पीआर टीम

राखी सावंत ने कहा, मुंह नहीं लगना चाहती क्योंकि मेरा मुंह बहुत महंगा है

राखी ने फिर दिखाई बेबाकी। इंस्टाग्राम

जब बात आती है, जवाब देने की तो राखी सावंत का ख्याल आ जाता है। उनकी बेबाकी अक्सर पैपराजी दिखा देते हैं, जब वह कहीं बाहर निकलती हैं। पिछले दिनों एक शख्स को मास्क पहनने को लेकर राखी ने जो लाइनें कही थीं, उस पर तो मीम्स भी खूब बने थे। राखी अक्सर जिम में वर्कआउट करते हुए अपने वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं। इस बार उन्होंने ट्रेडमिल पर चलते हुए अपने फैंस के साथ लाइव कर लिया। लाइव के दौरान राखी अपनी लिपस्टिक के बारे में फैंस को बता रही थीं कि लिपस्टिक के शेड की वजह से उनके लिप्स बिल्कुल हालीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली की तरह लग रहे हैं। इसी बीच उनके फैंस जहां कमेंट्स में उनकी तारीफ कर रहे थे, तो वहीं कुछ यूजर्स ने राखी पर भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। राखी ने अपने अंदाज में उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहां मेरे पेज पर कुछ निगेटिव लोग हैं। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन मुंह नहीं लगना चाहती हूं। मेरा मुंह बहुत ही महंगा है। आप मुझसे नफरत करते रहिए, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। मैं मेहनती हूं और मेहनत करने वालों को किसी से डर नहीं लगता है।

10 साल पहले देल्ही बेली के रूप में अभिनय देव ने खास जानर की कामेडी फिल्म बनाई थी। उनका कहना है कि किसी टाइपकास्ट से बचने के लिए उसके तुरंत बाद उन्होंने इस जानर को नहीं दोहराया। लंबे अंतराल के बाद वह फिर लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे।

डेल्ही बेली जैसी फिल्म बनाएंगे अभिनय देव

फिल्म डेल्ही बेली के निर्देशक अभिनय देव उसके सीक्वल के बजाय उस जैसी ही एक और फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में अभिनय ने कहा कि डेल्ही बेली फिल्म को बनाए हुए 10 साल हो गए हैं। इस फिल्म के बाद मैंने जानबूझकर कोई कामेडी फिल्म कई सालों तक नहीं बनाई। 2018 में मैंने ब्लैक कामेडी फिल्म ब्लैकमेल बनाई थी। अब मैं डेल्ही बेली जैसी ही या कह सकते हैं उसी जानर की फिल्म लेकर आ रहा हूं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। अगले साल फिल्म को शूट करने की तैयारी है। मैं चाहता तो डेल्ही बेली के बाद ही उस फिल्म को ला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में सब बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर देते हैं कि यह निर्देशक तो सिर्फ कामेडी फिल्में ही बना सकता है। टाइपकास्ट से बचने के लिए मैंने डेल्ही बेली के बाद 24 शो और फोर्स 2 जैसी फिल्में बनाई। फिर ब्लैकमेल से ब्लैक कामेडी जानर में काम किया। अब जिस फिल्म पर काम कर रहा हूं, वह डेल्ही बेली की सीक्वल नहीं होगी, बल्कि पूरी नई कहानी होगी। जहां तक बात है डेल्ही बेली के सीक्वल की, तो उसके राइट्स आमिर खान के पास हैं। उम्मीद है कि सीक्वल बनेगा।

पिछले कुछ समय से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं अभिनय देव • इंटरनेट मीडिया

प्रयागराज में शूटिंग से यादें ताजा होंगी : आयुष्मान

अभिनेता आयुष्मान खुराना बैक टू बैक अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने में लगे हैं। अनुभव सिन्हा की फिल्म अनेक और अभिषेक कपूर की चंडीगढ़ करे आशिकी की शूटिंग वह पूरी कर चुके हैं। अब वह अपनी फिल्म डाक्टर जी के अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। वह पहली बार वहां किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि आयुष्मान का प्रयागराज से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। रियलिटी शो रोडीज में हिस्सा लेने के दौरान वह यहां आए थे। आयुष्मान उस शो के विजेता बने थे। आयुष्मान कहते हैं, मैं हमेशा से अपने खूबसूरत देश की चारों दिशाओं में घूमना चाहता था। सौभाग्य से मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे ऐसा करने का मौका मिल रहा है। जब मैं रोडीज में हिस्सा ले रहा था, संयोग से तब प्रयागराज आया था और सीरीज के लिए शूटिंग की थी। उन्होंने बताया, मुझे अभी भी याद है कि किस तरह मैं इसके इतिहास, विरासत और वास्तुकला पर मंत्रमुग्ध था। प्रयागराज तीन नदियों - गंगा, यमुना और सरस्वती का संगमस्थल है और मैं इसकी मनमोहक सुंदरता से बेहद प्रभावित था। यहां पर शूटिंग करना भावनात्मक अनुभव होगा। यह मेरी पुरानी यादों को ताजा करेगा। उस शहर में शूटिंग करना कमाल होगा, जिसने मेरे करियर की शुरुआत में मेरी किस्मत को गढ़ा। डाक्टर जी का निर्देशन अनुभूति कश्यप कर रही हैं और जंगली पिक्चर्स इसके निर्माता हैं।

डाक्टर जी की शूटिंग के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे आयुष्मान खुराना • इंस्टाग्राम

बोहेमियन अंदाज में सजा बिग बास ओटीटी का घर

इस बार घर में होंगे रंगीन पर्दे • वूट पीआर टीम

बिग बास शो के घर को लेकर चर्चाएं खूब होती हैं। हर सीजन में एक थीम के साथ घर को बनाया जाता है। बिग बास ओटीटी शो के घर की झलक भी सामने आ गई है। घर को बोहेमियन अंदाज में सजाया गया है। निर्देशक ओमंग कुमार और प्रोडक्शन डिजाइनर वनिता ओमंग कुमार ने इस घर को डिजाइन किया है। शो को पहले डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जाएगा, इसका ध्यान भी दोनों ने घर को डिजाइन करते हुए रखा है। ओमंग ने बताया कि डिजिटल प्लेटफार्म के लिहाज से हमने बिग बास ओटीटी हाउस के लिए बोहेमियन, जिप्सी, कार्निवल लुक को चुना है। बोहेमियन लुक को ध्यान में रखते हुए पर्दों को कलरफुल बनाया गया है। इसके साथ ही हमने इसे वेकेशन हाउस (छुट्टियां बिताने वाला घर) जैसा बनाया है। यह घर से दूर एक प्यारा सा घर है। हम चाहते थे कि कंटेस्टेंट जब यहां पहुंचें तो उन्हें यहां और भी रुकने का मन करे। प्रतिभागी बारिश में भीग जाने की चिंता किए बिना ओपन गार्डन वाले हिस्से में आराम से बैठ सकते हैं। बेडरूम की नई बात हैं उसके बंक बेड्स, जो घर जैसा आरामदायक अहसास कराते हैं। बेडरूम में भी कार्निवल वाले लुक को शामिल किया गया है। घर के कई किनारे और कोने बनाए गए हैं, जहां दो-तीन कंटेस्टेंट आराम से बैठकर गप्पे मार सकते हैं। शो को करण जौहर होस्ट करेंगे। आठ अगस्त से यह शो वूट डिजिटल प्लेटफार्म पर शुरू होगा।

अध्ययन ने अपनी मैनेजर से कहा, आप हो गाने की एक्ट्रेस

अभिनेता अध्ययन सुमन अभिनय के साथ गायिकी में भी सक्रिय हैं। हाल ही में उनका गाना जबसे देखा... रिलीज हुआ है। गाना बनाने को लेकर अध्ययन ने एक लाइव चैट के दौरान बताया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था। जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूं तो करके ही रहता हूं। मैंने अपनी मैनेजर मलाइका को फोन किया जो कि वीडियो में मेरी अभिनेत्री हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने कास्ट्यूम्स लेकर आ जाओ। हम गाने को शूट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अभिनेत्री नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पास है। जैसे ही वह पहुंचीं, मैंने कहा कि आप यह वीडियो कर रही हो। उन्होंने कहा- नहीं। मैंने कहा- आप उसमें फिट हैं। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैंने ही गाने को डायरेक्ट किया और उसकी स्क्रिप्ट लिखी है। महज पांच घंटे में हमने गाने की शूटिंग कर ली थी। इस गाने को बहुत कम बजट में शूट किया गया। जब आपके पास ज्यादा बजट और सुविधाएं नहीं होती है, तो प्रेशर में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। गाने के शौक को लेकर अध्ययन ने आगे बताया कि मुझे गाने का शौक बचपन से था, लेकिन कांफिडेंस नहीं था। मैंने प्रोफेशनली गाना तब शुरू कि जब मुझे वैसे एक्टिंग आफर्स नहीं आ रहे थे, जैसा मैं चाहता था। मुझे लगा कि पांच छह साल घर पर बैठे-बैठे हो गए हैं। मैं कब तक यूं ही बैठा रहूंगा तो अपने दूसरे पैशन को फालो कर लेता हूं जो सिंगिंग है। वहां से इस क्षेत्र की ओर बढ़ा। तब सोचा नहीं था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा। शुरू में डरा हुआ था कि लोग कहेंगे कि फिल्में नहीं चल रही है तो सिंगिंग कर रहा है। फिर मैंने महसूस किया कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जिन्हें आपकी आलोचना करनी है, वह करेंगे। आप अपना काम उन लोगों के लिए करें, जो आपसे प्यार करते हैं। अध्ययन आगामी दिनों में वेब सीरीज आश्रम 2 में नजर आएंगे। उसमें उन्होंने राक स्टार की भूमिका निभाई है। वेब सीरीज में बाबी देओल, चंदन राय सान्याल प्रमुख भूमिका में हैं।

गायिकी में भी सक्रिय हैं अध्ययन सुमन। इंस्टाग्राम

बेल बाटम फिल्म के मेकर्स ने अफवाहों को नकारा

बड़े पर्दे पर 19 अगस्त को रिलीज होने जा रही बेल बाटम को लेकर सामने आई अफवाहों का मेकर्स ने खंडन किया है। मेकर्स ने स्पष्ट किया है कि फिल्म सिनेमाघरों में ही आएगी और इससे उसकी कोई डील प्रभावित नहीं हुई है। मेकर्स इस फिल्म को थिएटर में ही लाना चाहते थे, इसलिए इस फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदलना भी पड़ा। फिल्म का निर्माण पूजा एंटरटेनमेंट ने किया है। हाल में फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फिल्म को थिएटर में लाने की वजह से अमेजन प्राइम वीडियो ने उसकी डील की कीमत घटा दी है। पहले यह डील 65-70 करोड़ के बीच थी, लेकिन अब इसे घटाकर 45 करोड़ कर दिया है। इस पर पूजा एंटरटेनमेंट ने ट्वीट किया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता मुख्य भूमिका में हैं।

थिएटर में 19 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय अभिनीत बेल बाटम • इंस्टाग्राम